

कोयलांचल संवाद

संक्षिप्त खबरे

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाएं : कल्पना सोरेन

गिरीडीह (ईएमएस)।गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह प्रवास के दौरान गुरुवार को कई कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने गिरिडीह जिला परिसदन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली से लौटे, कहा संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने पर रहेगा जोर

रांची (ईएमएस)।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद से रांची लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित बैठक बेहद सकारात्मक रही। इसमें प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों की सराहना की गई।शीर्ष नेतृत्व ने कई निर्देश दिए हैं।इसमें संगठन, कार्यकर्ताओं और जनता को प्राथमिकता दिया है।केंद्रीय नेतृत्व ने सभी मंत्रियों और विधायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठन, कार्यकर्ताओं और जनता को प्राथमिकता देते हुए काम किया जाए।समय-समय पर ऐसी बैठकें होती रहेंगी ताकि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय बना रहे।मंत्री जिलों में जनता दरबार लगाएंगे: अब राज्य के मंत्री जिलों में नियमित रूप से जनता दरबार भी लगाएंगे, ताकि लोगों की समस्याएं सीधे सुनी और हल की जा सकें।प्रदेश कांग्रेस ने दो अगस्त को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत तक बढ़ाने, ओबीसी मंत्रालय का गठन और आरक्षण की अधिकतम सीमा में वृद्धि की मांग की जाएगी। इसके अलावा आगामी 25 जुलाई को दिल्ली में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में भागीदारी को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है।

अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारियों का समायोजन की मांग पर राजभवन के समक्ष आंदोलन जारी

रांची (ईएमएस)।झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के बैनर तले राजभवन के समक्ष अनुबंध कर्मचारियों का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पिछले 100 दिनों से अधिक समय से जारी है। गुरुवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने साक्षरता अभियान चलाकर विरोध जताया और सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की।कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से पुस्तकालय, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मी, माली आदि के रूप में निष्ठा और ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं। लेकिन मार्च 2025 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया।इससे वे आजीविका संकट से जूझ रहे हैं।इससे पहले 11 जून को कर्मचारियों ने बृट पोलिश और 16 जून को भिषाटन कार्यक्रम के माध्यम से भी अपना विरोध प्रकट किया था।बावजूद इसके राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की है।गुरुवार को प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने यज्ञ-हवन कर राज्य सरकार, राजभवन और विश्वविद्यालय प्रशासन से पुनः समायोजन की मांग की।संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

विधायक कल्पना सोरेन ने मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित

गिरीडीह (ईएमएस)।गिरिडीह दौरे पर पहुंचीं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को प्लस-2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। समारोह में मैट्रिक व इंटर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक ने मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और बेहतर करने की प्रेरणा दी।कहा कि युवाओं की सफलता ही राज्य का उज्जवल भविष्य तय करेगी।समारोह में कई अधिकारी, स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

ग्रास रूट लेवल पर काम करेगी प्रदेश कांग्रेस, जिला व ब्लॉक नेताओं को किया जाएगा ट्रेड

रांची (ईएमएस)।प्रदेश कांग्रेस ने ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश 20 जुलाई से पूरे झारखंड के सभी जिलों में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल होंगे।बैठक और प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य झारखंड के सभी पंचायतों में पंचायत समिति के गठन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं को प्रशिक्षित करना है।तय कार्यक्रम के अनुसार 20 जुलाई को पूर्वी और सरायकेला खरसावां जिले के जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। 21 जुलाई को हजारीबाग में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। 22 जुलाई को धनबाद में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले के जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के साथ ग्राम पंचायत समिति के गठन हेतु प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे।23 जुलाई को बेतला में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के पंचायत समिति के गठन के लिए जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर और समीक्षा बैठक में भाग लेंगे जबकि 24 जुलाई को पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रशेखर दुबे उर्फ दर्दाई दुबे के श्राद्ध क्रम में भाग लेंगे।

चाईबासा में खनन विभाग की टीम ने मड़गांव में अवैध बालू का भंडारण किया जब्त

पश्चिमी सिंहभूम (ईएमएस)।एनजीटी की रोक के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू का खनन, भंडारण व खरीद-बिक्री जारी है। एसडीओ महेंद्र छोटन उरांव के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने सीओ विजय बिरज के साथ गुरुवार को मड़गांव में छापेमारी की।इस दौरान खेरपाल व गुगुरखुंडा में भारी मात्रा में अवैध बालू का भंडारण पाया गया।टीम ने बालू को जब्त कर लिया।खनन विभाग के अधिकारी बालू के भंडारण की जांच-पड़ताल में जुट गए हैं।छापेमारी में अंचल अधिकारी, खान निरीक्षक निखिल दास,मड़गांव थाना प्रभारी संग्रह कुंवर व पुलिस के जवान शामिल थे।

झारखंड में 25 वर्षों में सिर्फ सत्ता बदली व्यवस्था जस की तस : सूर्य सिंह बेसरा

रांची (ईएमएस)।झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड में बीते 25 वर्षों में केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है। व्यवस्था जस की तस है, बेसरा गुरुवार को धनबाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो चुके हैं। इस दौरान 12 मुख्यमंत्री बदले, छह बार विधानसभा चुनाव हुए और तीन बार राष्ट्रपति शासन की लाला। लेकिन दुर्भाग्य है कि आम जनता की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं।उन्होंने भाजपा पर राज्य को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया। कहा कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा व रघुवर दास जैसे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन राज्य को दिशा देने में विफल रहे। झामुमो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार बनने के बावजूद उसके घोषणा पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने में सरकार विफल रही है। हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वादों को निभाने में उनकी सरकार कामयाब रही है।

बिजली सरचार्ज प्रस्ताव पर व्यापार संगठनों की नाराजगी

संयुक्त बैठक में विरोध जताया

रांची (ईएमएस)।नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्रेशन सरचार्ज रूल्स 2025 को लेकर राज्य के व्यापारिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। इस मुद्दे पर गुरुवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स, जेसिया और लघु उद्योग भारती की संयुक्त बैठक जेसिया कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तावित 5% बिजली सरचार्ज के संभावित दुष्प्रभावों पर गंभीर चर्चा हुई।बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया कि यह प्रस्ताव उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक बोझ डालेगा और झारखंड के औद्योगिक माहौल को अस्थिर



करेगा। सरचार्ज सभी शहरी बिजली उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है, चाहे खपत

की मात्रा, उपयोग का उद्देश्य या उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।चैंबर अध्यक्ष परेश गह्वानी ने कहा,

‘5% बिजली सरचार्ज से व्यापार महंगा होगा, जिससे राज्य में निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम सरकार

से इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं।जेसिया अध्यक्ष अंजय पचेरीवाल ने चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड की औद्योगिक इकाइयां पहले से ही लागत और लॉजिस्टिक समस्याओं से जूझ रही हैं और यह प्रस्ताव उनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता को और कमजोर करेगा।लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष विजय मेवाड़ और महाप्रीती विनोद कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि एमएसएमई सेक्टर पहले ही संघर्ष कर रहा है, ऐसे में यह अधिभार उत्पादन लागत को और बढ़ाएगा और छोटे कारोबारियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा करेगा।चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि अधिभार का निर्धारण और अपील की प्रक्रिया एक ही विभाग द्वारा संचालित करना अनुचित और असंवैधानिक है। साथ

ही नियम बनाने से पहले संबंधित औद्योगिक संगठनों, उपभोक्ताओं और जेएसईआरसी से कोई परामर्श नहीं लिया गया, जो प्रस्ताव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।बैठक में निर्णय लिया गया कि तीनों संगठन संयुक्त रूप से राज्य सरकार को प्रस्तावित नियमों से होनेवाली कठिनाइयां से अवगत कराएंगे और इसे जर्नलित में वापस लेने की मांग करेंगे।चैंबर के सह सचिव विकास विजयवर्गीय ने राज्य भर के जिला चैंबरर्स, संस्थाओं और आम नागरिकों से इस प्रस्ताव का विरोध दर्ज कराने की अपील की। बैठक में परेश गह्वानी (चैंबर अध्यक्ष), अंजय पचेरीवाल, विजय मेवाड़ (लघु उद्योग भारती अध्यक्ष), आदित्य मल्होत्रा (चैंबर महासचिव), दीपक कुमार मारू (पूर्व अध्यक्ष, चैंबर) शामिल थे।

समाहरणालय , गिरिडीह, समाहर्ता या समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30 / 2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चूंकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनायें यथा कोडरमा-गिरिडीह नई रेलवे लाईन निर्माण परियोजना हेतु ग्राम-लोहपिंडी, थाना-गिरिडीह, थाना सं0-108, अंचल-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह में कुल **5.1000** एकड़, यानि **2.0639** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है ।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से क्रमशे **5.1000** एकड़, यानि **2.0639** हेक्टेयर है और जो ग्राम-लोहपिंडी, थाना-गिरिडीह, थाना सं0-108, अंचल-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है—

क्रसं.	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (मुखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	97	853	रैयती	कृषि	5.1000	शहबाज अहमद वो फातिहा अली वो फरिसहा अहमद पिता स्व0 डॉं खुशींद अहमद	प्लॉट सं0 853 का अंश	प्लॉट सं0 853 का अंश	प्लॉट सं0 889 एवं 806	प्लॉट सं0 921 एवं 883
कुल						5.1000				

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30 / 2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सत्त्यक जांच के पश्चात किया गया है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्राम—**X**, थाना— **X**, थाना सं0— **X**, अंचल—**X** जिला—**X** क्षेत्रफल—**X** एकड़ यानि **X** हे0 भूमि अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गिरिडीह ।	अपर समाहर्ता, गिरिडीह ।	समाहर्ता, गिरिडीह ।
-----------------------------------	-------------------------	---------------------

PR 357583 Land Reforms (25-26)_D

 झारखण्ड सरकार कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद । मोबाईल नं० : 7061981397 Email : rdsd.dhanbad@rediffmail.com					
पत्रांक—583			धनबाद / दिनांक—17.07.2025		
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना					
ई— निविदा सूचना संख्या – 14/2025-26/RDSD/EE/Dhanbad/3 rd Call					
1.कार्य की विस्तृत विवरणी:—					
क्र०सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	बाघमारा प्रखण्ड के धावाचिता पंचायत अन्तर्गत धावाचिता के बरवाडीह गाँव में एन०एच०-32 पथ से कतरी नदी तक तथा कतरी नदी से काली मंदिर तक पी०सी०सी० पथ एवं कतरी नदी में पुल निर्माण ।	110.02400	परिमाण विपत्र की राशि 2%	10000.00	4 महीना
2.	वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि —24.07.2025				
3.	ई—निविदा प्राप्ति एवं समय—दिनांक 24.07.2025 से दिनांक 31.07.2025 को अपराह्न 5:00 बजे तक ।				
4.	ई—निविदा खोलने का स्थान — कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद ।				
5.	ई—निविदा खोलने की तिथि एवं समय— 02.08.2025 अपराह्न 2:00 बजे				
6.	ई—निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता :— ई० बेनौलाल मरांडी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद ।				
7.	ई—निविदा प्रकोष्ठ का दूरभास सं० – 7061981397 (संबंधित कार्यपालक अभियंता का दूरभाष नम्बर)				
8.	परिमाण विपत्र की राशि घट—बढ़ सकती है तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी ।				
9.	निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि केवल Online Mode द्वारा स्वीकार्य होगी ।				
10.	निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि का ई—मुग़तान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में अग्रघन की राशि वापस होगी । अगर खाता को बंद कर दिया जाता है तो सारी जवाबदेही आपकी होगी ।				
विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.jharkhandtenders.gov.in एवं कार्यालय की सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है ।					
कार्यपालक अभियंता					
PR 357593 (Rural Development) 25-26 (D)					
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद					

जिला परिषद, धनबाद

क्र	प्रखण्ड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	B.O.Q. मूल्य	अग्रघन राशि	समय अवधि
1	झरिया	भाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह
2	तोपचौदी	चलकरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह
3	टुण्डी	बालकुश (अलकुशिया) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह
4	निरसा	बेनागड़िया-1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह
5	निरसा	तेतुलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण ।	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह
6	गोविन्दपुर	तिलैया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	1,43,00,000	10,000	B.O.Q. का 2%	12 माह

- वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि : दिनांक **21-07-2025**
- ई0-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक **29-07-2025** को **5 P.M.** बजे तक
- निविदा खोलने के तिथि एवं समय : दिनांक **31-07-2025** को **3:00 P.M.** बजे ।
- केवल ई—निविदा (**E-Tender**) ही स्वीकार की जाएगी।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी : जिला अभियंता, जिला परिशद, धनबाद
- ई—निविदा प्रकोश्ट का दूरभाश संख्या— **9431396945**
- जिला परिशद, धनबाद के अन्तर्गत समुचित श्रेणी से निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेंगे ।
- परिमाण विपत्र विपत्र की राशि घट—बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रघन की राशि देय होगी ।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी ।
- निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि का ई—मुग़तान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में **अग्रघन की राशि** वापस होगी । यदि खाता बन्द कर दिया जाता है तो सारी जवाबदेही संवेदक की होगी ।
- योजनाओं की विवरणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी वेबसाईट <https://jharkhandtenders.gov.in> में देखा जा सकता है ।

ह0 /—
जिला अभियंता
जिला परिषद, धनबाद

PR 357604 (Rural Development)25-26*D

धनबाद गर्भवती महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल में जमकर हंगामा

धनबाद (ईएमएस)।धनबाद के एमएरकुंड क्षेत्र के गलफरबाड़ी मोड़ के समीप स्थित कुमारधुबी हॉस्पिटल में गुरुवार को 21 वर्षीय गर्भवती महिला सामोली दास को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिवार के लोगों और ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा कर जमकर हंगामा किया।लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया गया।हालात की नजाकत को देखते हुए वहां मौजूद डॉक्टर और सभी कर्मचारी भाग गए।मृतक महिला सामोली दास के परिवार के लोगों के अनुसार सामोली छह माह की गर्भवती थी। सबकुछ ठीकठाक चल रहा था। बुधवार की सुबह करीब छह बजे अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ने पर उसे सुबह आठ बजे कुमारधुबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसके

बड़कीपोना में पानी निकासी को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद 34 लोगों को मिला नोटिस, ग्रामीणों ने की बैठक

रामगढ़ (ईएमएस)।चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़कीपोना में पानी निकासी को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद गांव के 34 लोगों को न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया है। जिसे लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने तेतर टोला में एक बैठक कर झूठे प्राथमिकी का विरोध किया।बैठक में मुख्य रूप से मुखिया अरविंद सिंह, पंसस शम्भू कुमार, जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी पनेश्वर कुमार महतो शामिल हुए।बैठक में ग्रामीणों ने एक स्वर में रामप्रसाद महतो द्वारा गांव के 34 लोगों पर कराये गये प्राथमिकी का एक स्वर में विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि कई दशकों से हमारे पूर्वजों का पानी अखरा टोला, तेतर टोला के बाद रेलवे लाइन की तरफ जाता है।लेकिन रामप्रसाद महतो द्वारा इन दिनों पानी निकासी को लेकर विवाद उत्पन्न कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है।उन्होंने पिछले दिन गांव

के 34 महिला पुरुषों के ऊपर मामला दर्ज कराया है। पिछले दिन हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे कई जनप्रतिनिधियों पर भी झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है।उन्होंने ग्रामीणों पर हत्या करने का प्रयास, मारपीट, छेड़खानी, धमकी देने सहित कई गंभीर आरोप लगाया है।इस संदर्भ में मुखिया ने कहा कि इस तरह अगर कोई व्यक्ति द्वारा विवाद पैदा कर पानी को रोक दिया जायेगा, तो पूरे गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ जायेगी।उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय द्वारा ग्रामीणों को मिले नोटिस को स्वीकार करते हुए 28 जुलाई को सभी लोग न्यायालय पहुंच कर अपना पक्ष रखेंगे।साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का विवाद को आपसी बैठक कर ही सुलझाया जा सकता है। पूर्व प्रत्याशी पनेश्वर महतो ने कहा कि यहां पानी निकासी की बड़ी समस्या है।

एचईसी टेका मजदूरों के आंदोलन को आजसू पार्टी का समर्थन



रांची (ईएमएस)।एचईसी (हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन) के टेका मजदूरों की मांगों को लेकर जारी आंदोलन को आजसू पार्टी ने अपना समर्थन दिया। स्पनाई मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले मजदूरों ने नेहरू पार्क से एचईसी मुख्यालय तक जुलूस निकाला और घंटों प्रदर्शन किया।मजदूरों के आमंत्रण पर आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने एचईसी मुख्यालय

का उद्देश्य ही यह था कि गरीबों और मजदूरों को न्याय मिले।टेका मजदूरों का हक छीनने की कोशिश हो रही है, जिसे किसी भी कोमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।जरूरत पड़ी तो यह मुद्दा केंद्र सरकार तक उठाया जाएगा।आजसू पार्टी ने एचईसी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि यदि 17 दिनों से चल रहे आंदोलन का समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।प्रदर्शन के बाद एक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता दिलीप सिंह ने की और कहा कि 25 वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी मजदूर ने आउटसोर्सिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा है। जब तक पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं होती और चार महीने का बकाया वेतन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

संक्षिप्त खबरें

आदर्श आचार संहिता के मामले में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव हुए बरी

दुमका। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक 11 साल पुराने मामले में दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसडीजेएम मोहित चौधरी ने गुरुवार को सभी आरोपियों को साक्ष्य के आभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित तीन लोगों के खिलाफ चले मामले में 17 जुलाई को एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र नारायण प्रसाद मौजूद थे।मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है जो लोकतंत्र, न्याय और संविधान में अटूट आस्था रखते हैं। उन्हें कहा प्रारंभ से ही न्यायपालिका पर विश्वास रखता आया हूँ और आज उनका सम्मान और बढ़ गया है। यह रिहाई उनके राजनीतिक जीवन को और ऊर्जा देगी, जनसेवा की भावना को और दृढ़ बनाएगी। उन्होंने अपने अधिवक्ताओं का और सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार प्रकट किया।यह मामला गोड्डा जिला के पथरगामा थाना में 09 दिसम्बर 2014 में विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। गोड्डा के पथरगामा थाना में तत्कालीन बीडीओ पायल राज के लिखित आवेदन पर कांड संख्या 144/2014 के तहत दर्ज करवाया था। यह मामला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 123, 133 और डिफेंशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें राजद प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल, जेवीएम प्रत्याशी संजीव आनंद एवं झामुमो प्रत्याशी राजेश साह के खिलाफ सरकारी जगह पर कार्यालय खोलने एवं पार्टी कार्यालय एवं झंडा-पोस्टर लगाने का आरोप है। आरोपियों में से भाजपा प्रत्याशी रघुनंदन मंडल का निधन हो चुका है। अब इस केस में तीन ही आरोपी बचे थे। मौके पर राजद जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता डॉ अमरेंद्र कुमार यादव मौजूद थे।

कॉलेज में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस

दुमका: राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1,3,4,5 की ओर से एम जी कॉलेज रानीश्वर में अंतराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया।इस अवसर प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर नब कुमार पाल ने ग्राम स्वच्छता, बालिका शिक्षा पर जोर दिया, उन्होंने कहा आज बहुत सारी सरकार द्वारा योजना निर्धारित की गयी उसमे हम सभी को वर्तमान समय मे जागरूक होने का, ै है और जागरूक होकर सरकार द्वारा न्यायिक जानकारीया रखनी चाहिए । इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन इकाई 3 कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ रूपम कुमारी तथा धन्यवाद ज्ञापन इकाई 1 कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ अवर्णा रॉय ने किया साथ ही इकाई 5 कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर आशीष कुमार मंडल ने वालंटियर्स का उत्साह बढ़ाया साथ ही इस अवसर पर इकाई 4 कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ प्रशांत पांर, प्रोफेसर (काजल मंडल, विजय राना, ततत नूर, मोहम्मद रियाजुद्दीन) डॉ रानी कुमारी तथा स्वरूपा दे, आशा मरांडी, काजल भट्टाचार्य, श्यामल घोष, आदि तथा सभी वालंटियर्स रिमी सिन्हा पूजा मंडल, सुप्रिया सिंह, तितली सिंह, आदि उपस्थित थे ।

कार्यालय गिरिडीह नगर निगम			
Email id(giridihmunicipalcorporation@gmail.com)			
शुद्धि पत्र			
प्रकाशित- PR NO356912 के द्वारा प्रकाशित निविदा में आंशिक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत् है-			
पूर्व में प्रकाशित विवरण	आंशिक शुद्धि विवरण		
वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने की तिथि- 15.07.2025 (पूर्वाहन 11:00 बजे से)	वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने की तिथि- 19.07.2025 (पूर्वाहन 11:00 बजे से)		
वेबसाईट पर निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 05. 08.2025 (अपराहन 03:00 बजे तक)	वेबसाईट पर निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि -11.08.2025 (अपराहन 03:00 बजे तक)		
निविदा खोलने की तिथि- 05.08.2025 (अपराहन 04:00 बजे)	निविदा खोलने की तिथि- 13.08.2025 (अपराहन 04:00 बजे)		
अन्य यथावत् रहेंगी।		प्रशासक,	गिरिडीह नगर निगम।
PR.NO.357572 Urban Development(25-26):D			

झारखण्ड सरकार	
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय	
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद ।	
मोबाईल नं० : 7061981397 Email : rdsd.dhanbad@rediffmail.com	
पत्रांक:-582 धनबाद /दिनांक-17.07.2025	
कार्यालय आदेश	
इस कार्यालय के पत्रांक 457 दिनांक 05.06.2025 के द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालीन निविदा सूचना सं0- 11/2025-26/RDSD/EE/ Dhanbad/2 nd Call जिसका PR No. 354420 Rural Department(25-26)D में प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है ।	
कार्यपालक अभियंता	
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,	
धनबाद	
PR 357595 Rural Development(25-26)D	

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, ANIMALHUSBANDRY & COOPERATIVE GOVERNMENT OF JHARKHAND	
O/O District Agriculture Officer, Giridih	
Email- atma20giridih@rediffmail.com	
NOTIC INVITING EXPRESSION OF INTEREST	
EOI Reference no.- Agri/Grd/01/2025 Dated:- 18-07-2025	
1	Name of Work
2	Contract Period
3	Estimated Quantity & Cost (Rs.)
4	Tender Form Cost
5	EMD Amount
6	Date of Publication of Tender on website
7	Document Download Start From
8	Submission of Hard Copy of EOI BID Document
9	Bid Opening Date
10	Date & Opening Place
11	Name & Address of the Inviting Tender
12	Further details can be seen on website- www.atmagiridih.co.in.
13	Bid Document (Tender Paper) can also be collected from DAO, Giridih Office from 18-07-2025 to 08-08-2025 between 10.00 AM to 5.00 PM by Payment of Rs. 500/- through Bank Draft in the Name of “District Agriculture Officer, Giridih” payable at Giridih.
14	Ashutosh Kumar, District Agriculture Officer, Giridih, Jharkhand
15	PR 357535 Agriculture (25-26)_D

उपायुक्त ने किया विद्यालय का औचक निरीक्षण प्रधानाध्यापक नही मिले विद्यालय में, भेजा स्पष्टीकरण



दुमका:उपायुक्त अभिजीत सिन्हा द्वारा प्रखण्ड रामगढ़ के उक्तमित मध्य विद्यालय, सहेजना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक निराकार समीर सुमन अनुपस्थित पाए गए। इस पर उपायुक्त ने कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया। विद्यालय में भवन मरम्मत एवं बाउंड्री वॉल निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित



रही सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने उपस्थित सेविका एवं सहायिका को बच्चों की नियमित उपस्थिति, पोषण आहार की गुणवत्ता तथा शिक्षा संबंधी गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्र में डी एम एफ टी मद से प्राप्त सामग्रियों के उपयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर उपलब्ध सुविधाओं को समीक्षा की तथा बच्चों को दी जा



स्वच्छता एवं पोषाहार वितरण की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने निर्देशित किया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से साफ-सफाई, वजन मापन, टीकाकरण एवं अन्य आवश्यक गतिविधियाँ सुनिश्चित की जाएँ। इसके उपरांत उपायुक्त ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय सरैयाहाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया तथा उपस्थित पंजी,

महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विधायकों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट

मुंबई (ईएमएस)। गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। भाजपा और शरद पवार की पार्टी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार) के विधायकों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें लात-झसे चले। बाद में भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और राकापा (शरद पवार गुट) विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, जो अब हिंसक रूप ले लिया। हाल ही में गेट के पास दोनों नेता एक-दूसरे को गालियां देते देखे गए थे, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।यह घटना आव्हाड द्वारा की गई एक भड़काऊ टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने विधानसभा परिसर में रेड कार्पेट पर चलते हुए एक महिला के मंगलसूत्र को लेकर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से पडलकर पर तंज के रूप में देखा गया था, हालांकि आव्हाड ने किसी का नाम नहीं लिया था।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधान भवन में इस तरह मारपीट करना गलत है। मारपीट करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर के साथ विधानसभा की लॉबी में धक्का-मुक्की की गई, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। ऐसी मांग संजय उपाध्याय ने विधानसभा में की। इस पर अध्यक्ष राहुल नावकर ने आवासन दिया कि जांच तुरंत की जाएगी।महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में हुई हाथापाई और मारपीट पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन गुंडों को विधानसभा परिसर में घुसने के लिए पास किसने दिए? विधानसभा परिसर में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और अध्यक्ष को उन गुंडों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने उन्हें पास दिए।

सासनी बिजली घर पर विद्युत बिल समाधान शिविर, स्मार्ट मीटर से बड़े बिलों पर उपभोक्ताओं ने जताई नाराजगी

हाथरस (ईएमएस)। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के विद्युत वितरण उपखंड द्वितीय सासनी बिजली घर पर गुरुवार को मेधा विद्युत बिल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा सांसद अनूप प्रधान ने फीता काटकर किया। उन्होंने उपस्थित उपभोक्ताओं की समस्याएं गंभीरता से मनीं और समाधान का भरोसा दिलाया।एक्सईएन अविनाश तिवारी और एसडीओ आशीष रतन समेत विभागीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिलों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो गई है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि सिर्फ दो एलईडी बल्ब जलने के बावजूद तौल महीने का बिल 15 हजार रुपये तक आ रहा है। कैसर पीडित घूरलाल ने कहा कि घर में कोई नहीं रहता, फिर भी 14 हजार रुपये का बिल आ गया है।एक्सईएन ने जांच और समाधान का आश्वासन दिया।स्मार्ट मीटरों में एक साथ लोड बढ़ने की तकनीकी समस्या को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। अध्येक्षण अभियंता मनीष, अधिशासी अभियंता अभिनव तिवारी, सहायक अभियंता अमित कुमार गुप्ता, अवर अभियंता ब्रजेश कुमार, लाइनमैन मुनंद्र सिंह, शकिल आदि अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए उपायुक्त, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा



दुमका: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, हंसडीहा, जिला दुमका में विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) की बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता अभिजीत सिन्हा उपायुक्त दुमका (अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति) ने की।इस बैठक में भूतनाथ राजवार जिला शिक्षा पदाधिकारी (डियो), सरैयाहाट अंचल के अंचलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ), दुमका के प्रतिनिधि, जेएनवी बांका के प्रधानाचार्य, हंसडीहा थाना के थाना प्रभारी, एवं विद्यालय के अधिभावक- शिक्षक परिषद (पीटीसी) के दो नामित सदस्यगण की गरिमामयी उपस्थिति रही।बैठक की शुरुआत विधायन के प्रधानाचार्य कमल नयन पांडेय द्वारा स्वागत भाषण



के विकास के लिए अपने सुझाव एवं आश्वासन प्रदान किए गए। बैठक का समापन विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।बैठक उपरांत उपायुक्त ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन करते हुए कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्रों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने छात्रों के ज्ञान, अनुशासन एवं नवाचार क्षमता की सराहना की। इसके पश्चात उपायुक्त ने विद्यालय के एम.आई.रूम (मेडिकल इंस्पेक्शन रूम) एवं एम.पी. हॉल का भ्रमण किया, जहाँ विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई कला प्रदर्शनी, फोटोग्राफी प्रदर्शन और स्वदेशी खेलों की मनमोहक प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। बच्चों की रचनात्मकता एवं प्रयासों की सराहना करते हुए

कोर्ट आदेश पर लक्ष्मीगंज में मकान से अवैध कच्चा हटवाया, असली मालिक को दिलाया गया कच्चा

गुना (ईएमएस)। शहर के लक्ष्मीगंज क्षेत्र में मंगलवार को एक पुराने विवादित मकान पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने कच्चा हटवाकर असल मालिक को उसका वैधानिक हक दिलाया। यह कार्यवाही प्रथम व्यवहार न्यायाधीश आयुष भित्तल के आदेश पर कोर्ट नाजिर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2015 से न्यायालय में विचाराधीन था। विवादित मकान पर ओमप्रकाश जगगी द्वारा कब्जा किया गया था, जिसे लेकर सुनीता जगगी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था। वर्षों चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद वर्ष 2019 में सुनीता जगगी को केस में विजय मिली, लेकिन व्यावहारिक रूप से कब्जा नहीं मिल पाया था। कोर्ट आदेश के अनुपालन में मंगलवार को जेसीबी की मदद से मौके पर पहुंची टीम ने मकान से अवैध कच्चा हटवाया और वास्तविक स्वामिनी सुनीता जगगी को मकान का कब्जा दिलाया।

आपदा से निपटने की तैयारी: सिंगवासा तालाब पर गैस रिसाव व बाढ़ बचाव की माँक झिल आयोजित

गुना। जिले में संभावित आपदा स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से गुरुवार को गुना के सिंगवासा तालाब क्षेत्र में एक बहुआयामी माँक झिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास विशेष रूप से गैस पाइपलाइन से रिसाव और बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों में राहत व बचाव कार्यों की तैयारी को परखने के लिए किया गया। इस अभ्यास में जिलाधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने स्वयं मौके पर पहुंचकर संपूर्ण कार्रवाई का अवलोकन किया और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, एसडीएम शिवानी पाठक, नगर पालिका अधिकारी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दमकल विभाग, एनएफएल और गेल विजयपुर के सुरक्षा अधिकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे।माँक झिल के दौरान गैस पाइपलाइन से रिसाव जैसी स्थिति को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लीक क्षेत्र की घेराबंदी, प्रभावित लोगों को

सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और प्राथमिक उपचार जैसी प्रक्रिया को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। वहीं, दूसरी ओर बाढ़ जैसी स्थिति में संभावित जलभराव, नावों से रेस्क्यू, रिसस्यों व जीवन रक्षक उपकरणों के उपयोग का भी अभ्यास किया गया। गेल और एनएफएल की संयुक्त फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आगजनी की स्थिति में नियंत्रण की संपूर्ण कार्यप्रणाली को दर्शाया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि जिले में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संसाधन और टीम दोनों ही तैयार हैं। नगर पालिका का अमला भी जल निकासी और सफाई व्यवस्था के अभ्यास में सक्रिय रहा। जिलाधिकारी कन्याल ने इस झिल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी तैयारियों से न केवल आपदा आने की स्थिति में राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकती है, बल्कि आमजन को सुरक्षित रखने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता भी परिलक्षित होती है। उन्होंने टीमों को लगातार अभ्यास करते रहने की आवश्यकता भी जताई।

बिहार में पूर्व से बना वोटर लिस्ट अगर गलत है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव करानी चाहिए : संजय प्रसाद यादव

दुमका। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के बाद 35.5 लाख मतदाताओं के पते पर न पाए जाने और 54.5 लाख मतदाताओं द्वारा फॉर्म नहीं भरे जाने का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और झारखंड सरकार में श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।मिडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर, कि इस स्थिति से किस राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता है, मंत्री संजय यादव ने इस वोटर लिस्ट को गलत बताते जाने पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि यह वोटर लिस्ट गलत मानी जा रही है, तो बिहार के पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को रद्द करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए।संजय यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब भी चुनाव का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी देश में 'हिंदू-मुसलमान' का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि देश में अवैध अप्रवासी हैं, तो केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी में आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी मंत्री संजय यादव ने अपना मत व्यक्त किया। उनका मानना ​​है कि



झारखण्ड सरकार, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद

मोबाईल नं० : 7061981397 Email : rdsd.dhanbad@rediffmail.com



पत्रांक :- 581

धनबाद /दिनांक- 17.07.2025

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक 523 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-13/2025-26/RDSD/EE/Dhanbad/2nd Call जिसका PR No. 356238 Rural Development(25-26):D में प्रकाशित निविदा की तिथियों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

क्र०	विवरणी	पूर्व में प्रकाशित तिथि	संशोधित तिथि
1.	वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि	दिनांक 08.07.2025	दिनांक 24.07.2025
2.	ई०-निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक 08.07.2025 से दिनांक 15.07. 2025 को अपराहन 05:00 बजे तक।	दिनांक 24.07.2025 से दिनांक 31.07. 2025 को अपराहन 05:00 बजे तक।
3.	ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.07.2025 अपराहन 02:00 बजे।	दिनांक 02.08.2025 अपराहन 02:00 बजे।

अतः अन्य शर्तों यथावत रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, धनबाद

PR 357598 Rural Development (25-26)_D

<

कोयलांचल संवाद

मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का किया उद्घाटन

मतदाताओं को ईवीएम के प्रयोग की भौतिक और डिजिटल रूप से दी जाएगी जानकारी

मधुबनी, (ईएमएस)। मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने नगर भवन के समीप गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में स्थित ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन गुरुवार को किया। जिलाधिकारी ने ईवीएम बटन दबाकर प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि निर्वाचकों को यहां इसके प्रयोग की भौतिक और डिजिटल रूप में जानकारी दी जाएगी और मतदाता को जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्वयं बैलेट यूनिट का बटन दबाकर मत डाला। उन्होंने इस दरम्यान डमी चुनाव चिन्ह का वीवीपैट के प्रिंटेड पन्नों से मिलान भी किया। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग



संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम जागरूकता को लेकर विशेष मुहिम चला रहा है। इसका उद्देश्य जनता को ईवीएम के प्रयोग की जानकारी देना और वीवीपैट की पच्ची से अपना वोट

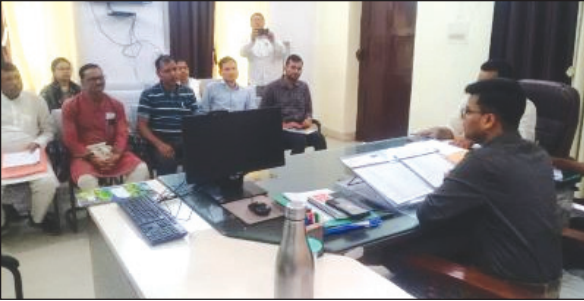
जांचने और परखने के गूर को बताना है। इससे विश्वसनीयता मजबूत होगी, साथ ही पारदर्शिता भी रहेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ईवीएम जागरूकता अभियान चुनाव की घोषणा होने तक चलाया

जाएगा। प्रदर्शन केंद्र हर कार्य दिवस को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। इस दरम्यान गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन किया जाना है। उन्होंने बताया कि वोटर ट्रेनिंग अवैयरनेस के लिए पृथक की गयी मशीनों का ही प्रयोग होगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में बीयू , सीयू और वीवीपैट को चिन्हित कर पृथक किया गया है। उन मशीनों को आयोग के विशेष पोर्टल ईएमएस-0.2 पर मार्क कर दिया गया है। इसकी सूची राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गयी है। नामित मशीनों पर ट्रेनिंग-अवैयरनेस का स्टिकर, डमी बैलेट पेपर और सिम्बॉल लोड किए गए हैं। इन मशीनों का प्रयोग केवल प्रदर्शन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को ईवीएम का हैंडस ऑन कराने के साथ ही उसके हैंडलिंग, परिचालन और मूवमेंट में सावधानियां और

गाइडलाइंस के अनुपालन की जानकारी दे दी गई है। केंद्र पर मॉक वोटिंग के दौरान पंजी पर आगंतुकों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। प्रत्येक दिन कुल डाले गए मतों की गिनती , फोटोग्राफ आदि का प्रतिवेदन संबंधित नोडल के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आयोग को प्रेषित किया जाएगा। वीवीपैट की पच्ची को विनिप्ट कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने निर्वाचकों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदर्शन केंद्र पर आकर ईवीएम के क्रिया-कलापों से रूबरू हों और ज्ञानवर्धन के साथ क्षमतावर्धन करें। इस अवसर पर जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि,मीडिया प्रतिनिधियों सहित अपर समाहर्ता मुकेश रंजन,डीडीसी सुमन प्रसाद दास, डीपीआरओ परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, नोडल पदाधिकारी ईवीएम प्रमत्त कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में अब तक 86.09 प्रतिशत गणना प्रपत्र भरा गया

विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सदर अनुमंडल कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक



मधुबनी, (ईएमएस)। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक गुरुवार को मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रतिनिधियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए 36-मधुबनी विधानसभा में 367 बीएलओ, 734 सहायक बीएलओ, 37 बीएलओ सुपरवाइजर तथा 11 एईआरओ की नियुक्ति की गयी है। 36- मधुबनी विधान सभा में कुल 365809 मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर दिया गया। वितरित किये गये गणना प्रपत्र

प्रतिनिधियों को सूची उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया कि मृत,स्थायी रूप से स्थानंतरित, दोहरी प्रविष्टि,अनुपस्थित मतदाता का सत्यापन अपने बुध लेवल एजेंट से करा लें, ताकि किसी योग्य व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची मे शामिल होने से वंचित ना रह जाए। सभी मतदान केंद्र के लिए नामित बुध लेवल एजेंट को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने तथा बीएलओ से समन्वय स्थापित कर सत्यापन करने का अनुरोध किया गया। अभी तक हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया ।

संक्षिप्त खबरें

नव नियुक्त प्रधानाध्यपको को 21 से 26 के बीच करना होगा योगदान

मधुबनी, (ईएमएस)। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं काउंसिलिंग में सफल प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना के संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने गाइडलाइन जारी किया है। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक को लिखे पत्र में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि शिक्षा विभाग के आदेश के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर अनुशंसित एवं काउंसिलिंग के दौरान सभी कागजात दस्तावेज सही पाए गए हैं। 5728 अभ्यर्थियों को उत्कृष्टित, नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापना के संबंध में आदेश दिए जाते हैं कि जिन प्रधानाध्यापकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है उन्हें आवंटित विद्यालय में 21 जुलाई से 26 जुलाई तक योगदान के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन प्रधानाध्यापकों का औपबर्धिक नियुक्त पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान प्रपत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 18 जुलाई से प्रिंट किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक को 21 जुलाई से योगदान करना है ऐसे में आवश्यक है कि इस स्थिति के पूर्व औपबर्धीक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र एवं प्रारूप योगदान प्रपत्र का सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रिंटिंग करना सुनिश्चित करने एवं इसे स-समय प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। प्रधानाध्यापक को आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन देय होगा। प्रधानाध्यापकों के योगदान के बाद इनका विभागीय काउंसिलिंग पोर्टल पर टैक्निकल जॉइनिंग अनिवार्य है। जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट अंकित होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा ने निदेशक इस संबंध में स-समय कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

मधुबनी जिला को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय : वामदल

मधुबनी, (ईएमएस)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जिला कमिटी द्वारा विशाल गुरा नगर को मधुबनी समाहरणालय के सामने आयोजित किया गया। धरना सभा की अध्यक्षता सीपीआई के कृपा नंद आजाद, सीपीएम के रामजी यादव ने संयुक्त रूप किया। धरना 10 सूत्री मांगों के समर्थन में किया गया। धरना के मुख्य मांगों में जिला को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, आम लोगों को राहत पहुंचाने, पेयजल संकट का समाधान अविर्लंब करने, सरकारी खाद्य चापाकल को ठीक कराने, सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाएं नल-जल योजना को अविर्लंब चालू करने और लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने, नल-जल योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच सर्वदलीय कमिटी से कराने और दोषी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गयी। बाढ़-सुखाड़ एवं बिजली संकट के स्थायी निदान के, भारत नेपाल के बीच हुए समझौते को लागू किया कराने, पश्चिमी कोशी नहर को दुरुस्त करने एवं अन्य सिंचाई योजना को शिफ चालू करनेकी मांग की गयी। धरना को संबोधित करने वालों में सीपीआई के मनोज मिश्र, सीपीएम के मनोज कुमार यादव, सीपीआई के लक्ष्मण चौधरी, सीपीएम के दिलीप झा, सीपीआई के रामनारायण यादव, सत्यनारायण राय, मोती लाल शर्मा, आनंद झा, उपेन्द्र सिंह,सुदन मिश्र, वाला जी, संतोष झा,किरण देवी, आशेश्वर यादव,मनोहर देवी, मय्य नारायण महतो,अजय कुमार वर्मा, महेश यादव, सीपीएम के राम-लखन यादव, गणपति झा, सत्यनारायण यादव, शशिभूषण प्रसाद, बाबू लाल महतो, अशोक यादव, बिन्दु यादव, राजेन्द्र यादव,सोनधारी यादव,राम कृष्ण यादव, विजय पासवान, अनीस कुमार, रेखा देवी, बीबी खातून, अरूण यादव सहित अन्य कई कार्यकर्ता शामिल थे।

मधेपुरा में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 11 मजदूर चपेट में आए

पटना (ईएमएस)। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। बांका-बक्सर में सुबह-सुबह बारिश भी हुई। सीवान से तेज बारिश हो रही है। इधर, मधेपुरा में सुकरी को खेत में बिजली गिरी, जिससे वहां काम कर रहे 11 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हालांकि, सभी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। अब यह धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अहर से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के साथ-साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, सिस्टम के कारण अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पटना सहित 18 जिलों बारिश हो सकती। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।

बिहार में सक्रिय शूटरों पर नकेल कसने हेतु शूटर सेल बनाएगी पुलिस

पटना, (ईएमएस)। बिहार में सक्रिय शूटरों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा शूटर सेल बनाया जायेगा। इस बात की जानकारी एडीजी, एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने दी. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध के बढ़ते आंकड़े, खासकर हत्या की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस मुख्यालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एडीजी कृष्णन ने बताया कि इस नई पहल के तहत बिहार के हर जिले में सक्रिय शूटरों का एक व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। जिसमें पुराने और नए सभी शूटरों का डाटा शामिल किया जाएगा। यह डाटाबेस ही भविष्य में इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनेगा। इस कार्य को गति देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि शूटर सेल के माध्यम से जेल में बंद और बेल पर बाहर आए शूटरों की भी निगरानी की जाएगी। यह देखा जाएगा कि बाहर आने के बाद वे किन गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई नए शूटर पैसे की लालच में पहली बार अपराध कर रहे हैं। इन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अब स्प्रीडी ट्रायल चलाकर भी अपराधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी पटना में हत्या की बढ़ती घटनाओं पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं में तेजी से पैसा कमाने की चाह और चकाचौंध भरी जीवनशैली के प्रति आकर्षण उन्हें अपराध की दुनिया की ओर ले जा रहा है।

अमृत भारत ट्रेन: आम से खास बनी आम आदमी की रेल यात्रा

पटना, (ईएमएस)। एक मध्यमवर्गीय परिवार या उसका कोई एक सदस्य जब रेल यात्रा पर निकलता है तो उसके साथ सिर्फ एक बैग नहीं होता- बल्कि उसके साथ जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऐसे लाखों यात्रियों के लिए रेल यात्रा हर रोज की जरूरत थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने समझा और अब उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल इन्हें पूरा कर रही है। अमृत भारत ट्रेन योजना न केवल रेलवे के ढांचगत सुधार का प्रतीक है, बल्कि श्रमजीवी और मध्यमवर्गीय समाज की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर बनाई गई एक सुधारपरक एवं ऐतिहासिक पहल है।भारत की एक बड़ी आबादी के लिए हर दिन की यात्रा रोजगार, शिक्षा और जीवन की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी है। इन वर्गों के लिए रेल यात्रा का उद्देश्य गंतव्य पर पहुँचकर आजीविका के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अमृत भारत ट्रेन इस वर्ग के लिए यात्रा का नया विकल्प है, जो सस्ती, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा की गारंटी है। इस ट्रेन में विशेष रूप से सामान्य और स्लीपर श्रेणी के आधुनिक कोच शामिल किए गए हैं, जिससे वे लोग भी तेज, सुरम एवं सुविधाजनक यात्रा का लाभ उठा सकें।अमृत भारत ट्रेन पहली बार देश के अंत्योदय



और मध्यमवर्ग के लिए रेल यात्रा को तेज, सुरक्षित, किफायती और सम्मानजनक बना रही है। यह ट्रेन उस नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता का प्रमाण है कि विकास अब केवल उच्च वर्ग या महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और मेहनतकश नागरिकों तक पहुंचा है। यह ट्रेनें पूरी तरह मेक इन इंडिया तकनीक पर आधारित हैं। इनका नया संस्करण अमृत भारत 2.0 न केवल अधिक तेज (130 किमी./घंटा तक की रफ्तार) है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करता है— जिनमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, आरामदायक सफर के लिए एयर सि्रिंग बांडी, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स,

स्वच्छ दिव्यांगजन-अनुकूल शौचालय और सेफ्टी के लिए फायर डिटेक्शन व टॉक-बैक यूनित शामिल हैं।यह ट्रेन सेवा न केवल किफायती है, बल्कि इसमें सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सामान्य श्रेणी में भी बेहतर वॉटेलेशन, आरामदायक सीटें, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और यात्री सूचना प्रणाली जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसका उद्देश्य लोगों को सुविधा के साथ गरिमाययी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।अमृत भारत ट्रेनों के रूट भी बेहद रणनीतिक रूप से चुने गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों से चलने वाली ये ट्रेनें उन मांगों

को जोड़ रही हैं जो श्रमिकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए रोजाना की जरूरत हैं। चाहे वो पटना से दिल्ली की यात्रा हो या दरभंगा से लखनऊ की, अब यात्रियों को महंगी और सीमित ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह योजना, छोटे शहरों और कस्बों को बड़े औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्रों से जोड़कर सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा दे रही है।बिहार से पांच अमृत भारत ट्रेनों का संचालन पूर्वी भारत के अंत्योदय और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सीगात हैं। वर्तमान में बिहार से दो अमृत भारत ट्रेनें- दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली और सहरसा से मुम्बई का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेनें

बिहार में दिनदहाड़े हत्या, सांसद पाप्पू यादव को अस्पताल में नहीं घुसने दिया

तेजरवी यादव बोले, बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं

पटना, (ईएमएस)। पटना के पारस अस्पताल में दिनदहाड़े हुई हत्या को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। राजद और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर तंज कसा। इस बीच पूर्णिया के निरदलीय सांसद पप्पू यादव जब पारस अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान पप्पू यादव और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच बहस हुई। हालांकि वहां इयूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पप्पू यादव को अंदर नहीं जाने दिया।पप्पू यादव ने कहा कि

बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि वह राज्यपाल से मिलकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। इस बीच पारस अस्पताल में हुई हत्या को लेकर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी दावा है कि वहां पांच आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर मारी गोली। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं? 2005 से पहले ऐसे होता था जो?’ इधर बिहार कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पटना के पारस हॉस्पिटल में सरेआम गोलीबारी। राज्य में अपराध इतना स्वस्थ है कि अब हॉस्पिटल का ही रुख कर लिया। कानून-व्यवस्था बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। इस हत्याकांड पर बिहार के डिप्टी

सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बता दें पटना के भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित पारस अस्पताल में कुछ अपराधी हथियार लेकर घुस गए। अपराधियों ने यहां अस्पताल के आईसीयू में चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। चंदन मिश्रा पेरौल पर बाहर आया था और वह इलाज कराने अस्पताल गया था। लेकिन यहां दिनदहाड़े अपराधियों ने उसे गोली मार दी और सभी अपराधी फरार हो गए। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई। चंदन मिश्रा मूल रूप से बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव का रहने वाला था। जेल में बंद चंदन पेरौल पर बाहर आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

एडीजी हेडक्वार्टर कृष्णन का तर्क, बिहार में अप्रैल, मई और जून में ज्यादा हत्याएं होती

बारिश होते ही किसान खेत में काम करने लग जाते हैं



पटना, (ईएमएस)। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बिहार में क्राइम को लेकर कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती रही हैं। ये पिछले कई सालों से ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है, तब तक ये सिलसिला लगातार जारी रहता है।एडीजी हेडक्वार्टर कृष्णन के अनुसार इस टाइम खेती नहीं होती है। किसान अपने पस काम नहीं होता है। इसके बाद ये वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है, तब किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसकारण घटनाएं कम हो जाती हैं।कृष्णन ने कहा कि, बिहार एसटीएफ ने इसी महीने एक नए सेल का गठन किया है। इस सेल का काम सिर्फ इतने के शूटर्स, जो सुपारी लेकर हत्या करते हैं। उनका डेटाबेस तैयार

करना है। इसके लिए नया सेल तमाम सुपारी लेने वालों का पूरा ब्यौरा जुटाकर उनका डोजियर बनाएगा। इससे किसी हत्यादात को शामिल हत्यारों की पहचान करने में आसानी होगी।सुपारी किलर की फोटो, नाम, पता सहित तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। कई युवा राह भटक कर पैसे के लालच में सुपारी लेकर हत्या करने का काम करने लगे हैं। इन युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। इस साल अब तक में

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 125 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली

पटना, (ईएमएस)। मुफ्त बिजली योजना अब बिहार पहुँच गई है। जी हाँ, बिहार में 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट में शामिल हत्यारों की पहचान करने में आसानी होगी।सुपारी किलर की फोटो, नाम, पता सहित तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। कई युवा राह भटक कर पैसे के लालच में सुपारी लेकर हत्या करने का काम करने लगे हैं। इन युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। इस साल अब तक में



जांच में पहला सुराग मनेर थाना क्षेत्र के हाथी टोला निवासी सुमित कुमार के रूप में मिला, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और बिहटा

थाना क्षेत्र के मौदही गांव से चोरी की छह बाइक बरामद की गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का नेटवर्क पटना और भोजपुर जिलों तक फैला हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में मनेर

कोयलांचल संवाद

संक्षिप्त खबरे

हरदोई के बाल चिकित्सालय में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

हरदोई, (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बाल चिकित्सालय में आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन समय पर कार्रवाई से कोई हताहत नहीं हुआ। यह आग संभवतः शॉर्ट सर्किट या बैटरी फटने के कारण लगने की आशंका जताई गई है। जानकारी अनुसार कीर्ति कृष्णा अस्पताल में आग लगने के समय अस्पताल में लगभग 18 से 20 बच्चे और उनके परिजन मौजूद थे। आग लगते ही धुआं पूरे परिसर में भर गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर भर्ती कुछ शिशुओं को कपड़ों की गठरियों में बांधकर रस्सियों के सहारे नीचे उतारा गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्रा ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और आग के कारणों की जांच की जा रही है। अस्पताल संचालक की पत्नी अपना गुप्ता ने बताया कि घटना के समय वह ऑफिस में थीं और भूमिगत तल से धुआं उठता देख उन्हें आग लगने का संदेह हुआ। अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली कि समय रहते सभी सुरक्षित निकाल लिए गए।

लोकसभ अध्यक्ष बिरला बाढ़ प्रभावितों से मिले, जलभराव रोकने के दिए निर्देश

कोटा, (ईएमएस)। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा-बूंदी से सांसद ओम बिरला ने कोटा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जान-माल का नुकसान हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला सबसे पहले बुधवार को रणपुर पहुंचे थे, जहां एक महिला की स्कूटर सहित नाले में बहने से मौत हो गई थी। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने जलभराव की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए रणपुर तालाब और आलानिया क्षेत्र से पानी को चंबल नदी की ओर मोड़ने की योजना पर चर्चा की। इसके साथ ही नालों की क्षमता बढ़ाने और वर्षा जल को नियमित रूप से निकासी देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का सुझाव दिया। बिरला ने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए और जलभराव रोकने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए।

विधायक ने फडणवीस के गुणों की तुलना राम और कृष्ण से कर चर्चा में आए

मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र विधान परिषद में भाजपा विधायक परिणय फुके का बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना भगवान राम और कृष्ण से करते हुए उन्हें ईश्वरीय व्यक्तित्व बता दिया है। भाजपा विधायक फुके ने अपने एक बयान में कहा कि फडणवीस का चरित्र भगवान श्रीराम जैसा है, बुद्धि श्रीकृष्ण जैसी, सहनशीलता महादेव जैसी, सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शांति उनमें है। उन्होंने आगे कहा, कि हम उनके भजन गाते हैं, वे हमारे लिए भगवान जैसे हैं। मुझे नहीं पता कि वे भगवान हैं या नहीं, लेकिन वे एक ईश्वरीय व्यक्ति हैं। भाजपा नेता का यह बयान न सिर्फ सत्तापक्ष बल्कि विपक्षी नेताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ इसे राजनीतिक चापलूसी बता रहे हैं तो कुछ इसे फडणवीस की कार्यशैली की सराहना के रूप में देख रहे हैं। फडणवीस वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी के भीतर और बाहर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी हुई है।

तेंदुओं की खाल बरामदगी के साथ ही सरकारी शिक्षक समेत 07 गिरफ्तार वन्यजीवों के अवैध व्यापार का मामला

मयूरभंज, (ईएमएस)। ओडिशा के मयूरभंज जिले में वन्यजीवों के अवैध व्यापार का बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने तीन तेंदुओं की खाल बरामद की है और इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक भी शामिल है। सिमिलिपाल टाइनर रिजर्व (एसटीआर) के उप निदेशक सम्राट गौड़ा ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर उदाला थाना क्षेत्र के कुटलिंग और बादसाही थाना क्षेत्र के चंदनचतुरी गांव में छापेमारी की गई। इसमें पांच साल के दो और एक साल के एक तेंदुए की खाल बरामद की गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेंदुओं को कहां मारा गया था। गौड़ा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के छत्तीसगढ़ और एसटीआर क्षेत्र के शिकारियों से संबंध पाए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मनोरंजन टिपरिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। वन विभाग इस पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

शादी के झूठे वादे पर रेप के आरोप में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली, (ईएमएस)। शादी के झूठे वादे पर बलात्कार से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अंतिम जमानत बरकरार रखी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाने वाली महिला को कड़ी फटकार लगा दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेटेवर सिंह की बेंच ने महिला के विवाहेतर संबंध पर सवाल उठाकर कहा कि वे एक शादीशुदा महिला और दो बच्चों की मां होने के नाते परीपक्व है और उसे पता था कि वह शादी के बाहर रिश्ता बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला से पूछा कि वहां आरोपी के कहने पर बार-बार होटल क्यों जाती थी, जबकि उस पता था कि वह शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखकर अपराध कर रही है। महिला ने आरोप लगाया था कि राक्षस ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके दबाव में पति से तलाक भी ले लिया। हालांकि, पटना हाईकोर्ट ने राक्षस को जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि महिला के तलाक के बाद से दोनों के बीच कोई शारीरिक गतिविधि नहीं हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 968.47 ग्राम सोना जब्त किया

अमृतसर, (ईएमएस)। पंजाब के अमृतसर में मौजूद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। कस्टम की टीम ने 2 यात्रियों से कुल 968.47 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत 96 लाख 75 हजार आंकी गई है। यह कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार दोनों ही यात्री ईंडिगो की फ्लाइट से कोलकाता से अमृतसर पहुंचे थे। जैसे ही दोनों यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे, कस्टम अधिकारियों ने उन्हें संदेह के आधार पर रोककर गहन जांच की। जांच में यह सामने आया कि दोनों ने सोना अल्टट चालाकी से छिपाकर रखा था। अधिकारियों ने जब सोना जब्त किया, तब यात्रियों ने इसके स्रोत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इसके बाद कस्टम विभाग ने तत्काल मामला दर्ज कर सोना जब्त किया है और दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों को संदेह है कि यह एक संगठित तस्करी रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जो घरेलू ऋट् का इस्तेमाल कर तस्करी को अंजाम दे रहा था। विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या यह गिगह पहले भी इसी तरह सोना पहुंचाता रहा है। सरकारी निर्देशों के अनुसार, जब्त सोना अब सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तमिलनाडू में एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन एआईएडीएमके सरकार बनाएगी : पलानीस्वामी

चेन्नई, (ईएमएस)। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगमियां तेज हो गई हैं। एआईएडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती है, तब तमिलनाडु में उनकी एकदलीय सरकार बनेगी और मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंग। उनके इस बयान से सहयोगी दल चालतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ संभावित सत्ता-साझेदारी को लेकर भारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। पलानीस्वामी ने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन जीतेगा, लेकिन एआईएडीएमके अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, हमारा गठबंधन जीतेगा... लेकिन एआईएडीएमके अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने जोर दिया कि गठबंधन का नेतृत्व एआईएडीएमके कर रही है और मुख्यमंत्री बनने का फैसला उनका है।

यूपी में 3363 किलोमीटर लंबाई की कुल 50 नदियों का कार्याकल्प किया

करीब मृतप्राय हो चुकी नदियों में फिर फूटी जलधारा, गांवों को नई ऊर्जा और

लखनऊ (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जल व पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं अब जमीन पर दिखाने लगी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम और मनरेगा के तहत हो रहे प्रयासों से राज्य की सूखी व विलुप्तप्राय नदियों में फिर से जीवनन्तन मिला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3363 किलोमीटर लंबाई में कुल 50 नदियों का कार्याकल्प हो चुका है, जिससे गांवों की नई ऊर्जा और किसानों को सिंचाई का बेहतर साधन मिल रहा है।

दरअसल योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 1011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटी नदियों व जलधाराओं का पुनरुद्धार कराया है। इन जलस्रोतों को न केवल साफ-सुथरा किया गया, बल्कि उनकी प्राकृतिक धारा को भी पुनर्जीवित किया गया। इससे इन क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार हुआ

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा देने की कांग्रेस की मांग

नई दिल्ली, (ईएमएस)। संसद के मॉन्सून सत्र में मोदी सरकार को घेरने की विपक्षी कवायद शुरू हो गई है। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉन्सून सत्र के लिए गार्मांगं मुद्दा बिहार में वोटर लिस्ट से जुड़ा है, लेकिन पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मामला अभी तक कांग्रेस की तरफ से खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि, संसद का विरोध सत्र बुलाने की कांग्रेस की डिमांड टुकरा कर मोदी सरकार ने जख्मों को भरने की नहीं दिया है। इस कारण संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए जो हथियार तैयार हो रहे हैं, उसमें पहलगाम में सैलानियों पर हुआ आतंकवादी हमला ज्यादा असरदार हो सकता है। इस मौहाल में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांगला भी काफी प्रभावी हो सकता है। इसकारण लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर पत्र लिखा है। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी दोनों कांग्रेस नेताओं ने करीब करीब इसतरह की थी। पीएम मोदी के नाम प्रेषित कांग्रेस नेताओं ने पत्र में लिखा है, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वे संसद के मॉन्सून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाएं। और, 'हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

साढ़े छह साल में अर्धसैनिक बलों समेत 177 सुरक्षाकर्मियों ने की आत्महत्या

बीजेपी विधायक के सवाल का छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

नई दिल्ली, (ईएमएस)। भारतीय सेना के अलावा देश की आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाली भारतीय अर्धसैनिक बल के बारे में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट सवाल खड़े कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार ने बुधवार को बताया कि पिछले साढ़े छह साल में अर्धसैनिक बलों के जवानों समेत 177 सुरक्षाकर्मियों ने आत्महत्या कर ली है।

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डिप्टी

4 राज्यों, 40 से ज्यादा जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर राजस्थान में लोकसभा सांसद राजुकमार रोत ने शुरु की मुहिम

जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान में फिर आदिवासियों के लिए अलग भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है। दक्षिणी राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) और अन्य स्थानीय नेताओं की अगुआई में मुहिम को जोर देने की कोशिश हो रही है। बीएपी के संस्थापक और लोकसभा सांसद राजुकमार रोत ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर नक्शा साझा करके पुरानी मांग पर नई बहस छेड़ी बल्कि हर साल होने वाली भील प्रदेश संदेश यात्रा का इस बार बड़े पैमाने पर आयोजन करके मुहिम को जमीन पर तेज करने की कोशिश शुरु कर दी है।

दरअसल भील भारत की एक प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में मिलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इनकी अच्छी आबादी है। भील प्रदेश के समर्थक गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 40 से ज्यादा जिलों को मिलाकर एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं। सांसद रोत कहते हैं, इन जिलों

को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाएं। खड़गे और राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग जायज है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के दो इंटरव्यू का हवाला देकर याद दिलाया है कि कैसे सरकार की तरफ से कई मंचों से जम्मू-कश्मीर के लोगों से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हुआ है। लगे हाथ दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को याद दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे दो हिस्सों में बांटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कांग्रेस ने लद्दाख को संविधान की

छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र पहले से ही शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने से वहां के लोगों के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना आसान होगा, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों को विशेष दर्जा देती है, जिससे उन्हें अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिक स्वायत्तता मिलती है। ऐसा करने से लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासोन्मुख और राजनीतिक आकांक्षाएं पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा, और उनके अधिकार, जमीन और उनकी पहचान की भी हिफाजत हो सकेगी।

कि खुदकुशी करने वाले अन्य सुरक्षाकर्मों छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, विशेष कार्य बल और होमगार्ड समेत राज्य पुलिस की विभिन्न शाखाओं से संबंधित थे। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के जवाब के मुताबिक 2019 में 25, 2020 में 38, 2021 में 24, 2022 में 31, 2023 में 22, 2024 में 29 और 15 जून तक 2025 में आठ सुरक्षाकर्मियों ने खुदकुशी की।

तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा, भरुच, वलसाड़ा और महाराष्ट्र के नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, पाली, कोटा आदि जिलों से भील समुदाय के लोग पहुंचे। वहीं मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, मंदसौर, इंदौर, रतलाम, नीमच, बुरहानपुर, धार, देवास, खंडवा, खरगौन, बड़वानी और अलीराजपुर से बड़ी संख्या में भील पहुंचे। इतना ही नहीं गुजरात के अरवल्ली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद, सूरत, बड़ोदरा,



है और आसपास के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत 86 अन्य कार्यों को चिह्नित कर नदियों की साफ-सफाई,

गहरीकरण, तटबंध निर्माण, पौधरोपण, जलधारा पुनर्स्थापन और जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए जिनका व्यापक असर

अब साफ नजर आ रहा है। योगी सरकार ने नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन को अपनी प्राथमिकता में रखा है। जिन छोटी-छोटी नदियों

किसानों को सिंचाई का बेहतर साधन

को लोग करीब भूला चुके थे, जिन्हें नले या गंदगी के अड्डे के रूप में पहचान मिली हुई थी, आज उन्हीं नदियों में फिर से स्वच्छ जलधारा बहने लगी है। इसका सबसे ताजा और सकारात्मक उदाहरण फिरोजाबाद जिले में देखने को मिल रहा है, जहां वर्षों बाद नदियों का पुनर्जीवन स्थानीय जनता के लिए आशा और उत्साह का कारण बन रहा है। फिरोजाबाद के सिरसांगंज, शिकोहाबाद और टूंडला क्षेत्र में बहने वाली 108 किलोमीटर लंबी सिरसा जैसी छोटी नदियां गंदगी, अतिक्रमण और जलस्रोतों के सूख जाने के कारण करीब मृतप्राय हो चुकी थीं। नदियों में गंदा पानी, प्लास्टिक, सीवर ने प्राकृतिक जलधारा को खत्म किया था। इससे क्षेत्र में भुजल का स्तर गिर गया, खेती के लिए पानी की भारी समस्या बनी। यह देखकर योगी सरकार

सीमांचल क्षेत्र में बीएलओ संदिग्ध विदेशी बताकर फॉर्म आनलाइन समिट नहीं कर रहे कई बूथ लेवल ऑफिसर को मौखिक रूप से निर्देश दिए गए

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जारी स्पेशल इंटीसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया इन दिनों विवादों में आ गई है। आरोप है कि वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर इसतरह के लोगों को संदिग्ध विदेशी बताकर उनके फॉर्म रोकें जा रहे हैं, जिनके पास सभी वैध भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशनगंज, कटिहार, और पूर्णिया के कई बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को मौखिक रूप से निर्देश दिए गए हैं कि नेपाली या बंगाली मूल के लोगों के नाम अलग से चिह्नित कर उन्हें फिलहाल ऑनलाइन सबमिट न करें। किशनगंज के दिथेल के बर्वै ब्लॉक में एक बीएलओ ने माना कि उन्हें 27 इसतरह के फॉर्म लंबित रखने को कहा गया जो नेपाली मूल के लोगों के थे। इसमें एक महिला भी शामिल है जिसके पास आधार, राशन कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट जैसे वैध दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी बीएलओ अधिकारी ने उसका फॉर्म सबमिट नहीं किया। इसका मुख्य कारण महिला के पिता नेपाल में रहे हैं। बीएलओ अलग से 'शेडो लिस्ट' बना रहे हैं जिसमें वे उन आवेदकों को शामिल कर रहे हैं जिन्हें वे बाहरी मानते हैं। इसमें प्रमुख रूप से बंगाली भाषी शेरशहाबादी मुस्लिम और नेपाली मूल के लोग हैं। बीएलओ का कहना है कि उन्हें ऊपर से मौखिक आदेश मिला है कि इसतरह के फॉर्म को ऑनलाइन दर्ज न किया जाए। इसने एक दोहरी मतदाता गणना प्रणाली को जन्म दे दिया है, एक सामान्य नागरिकों के लिए और दूसरी उन पर संदेह के आधार पर बनाई गई जो 'बोलचाल' या 'वंश' से पहचाने जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने 2003 की मतदाता सूची को विरासत सत्यापन का आधार बताया है, लेकिन सीमांचल के कई इलाकों में यह सूची उपलब्ध ही नहीं है।

केंद्रीय मंत्री शाह जयपुर में सहकारिता सम्मेलन में हुए शामिल, बांटे नियुक्ति पत्र कहा- कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का अस्तित्व बचाने की जा रही कोशिश

जयपुर, (ईएमएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर माफिया को कड़ा संदेश दिया। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में बार-बार आतंकवादी हमले होते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह किया। इससे पहले उरी, पुलवामा हमले का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऊंटों के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार लगातार

प्रयास कर रही है। कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का नक्सल संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च शुरू किया गया है। इससे आने वाले दिनों में ऊंटों पर कोई खतरा नहीं रहेगा। अमित शाह गुरुवार को जयपुर से करीब 22 किमी दूर दादिया में सहकारिता सम्मेलन में पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखा रहे थे। उन्होंने सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी। सरकारी नौकरी पाने वालों को नियुक्ति पत्र बांटे।

केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार दोपहर जयपुर

एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से दादिया के लिए हेलिकॉप्टर से रवाना होने वाले थे लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलिकॉप्टर उड़ नहीं सका। इसके बाद वह सड़क मार्ग से दादिया पहुंचे। यहाँ पहुंच कर उन्होंने सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। कोऑपरेटिव का उपयोग कर ऊंटों का अस्तित्व बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दादिया में शाह ने पुलिस के 100 नए वाहनों की हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी।

हरियाणा में 12 घंटे में दो बार आया भूकंप, नुकसान की सूचना नहीं

पिछले 20 दिन में पांच बार भूकंप के लगे झटके, लोग दहशत में

चंडीगढ़, (ईएमएस)। हरियाणा में गुरुवार दोपहर भूकंप आया। इसका केंद्र झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा के पास था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। इससे पहले रोहतक में बुधवार-गुरुवार देर रात 12:46 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके लगते ही लोगों को नींद खुल गई और बह घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन तार भर डर का माहौल था। जानकारों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इस भूकंप से जमीन के 10 किलोमीटर नीचे गहराई में हलचल हुई। इसका केंद्र रोहतक का गांव बालौट के नजदीक का क्षेत्र था। प्रदेश में पिछले 20 दिन में पांच बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के लिहाज से हरियाणा में 12 जिले संवेदनशील हैं। इसमें रोहतक, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं।

ने नमामि गंगे मिशन और संचारी जलशक्ति अभियान के तहत इन नदियों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए नदियों से अतिक्रमण हटाया गया। कलौनिंग, डी-सिल्टिंग (गाद हटाना), गंदे नालों का पानी रोककर ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा गया। अब बारिश के पानी को संग्रह कर नदी में छोड़ा जा रहा है ताकि जलधारा स्थायी बनी रहे। फिरोजाबाद के लोग दशकों से जिस नदी को मृत मान चुके थे, अब उस नदी को बहते देखना किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। फिरोजाबाद से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक, हर नदी के पुनर्जीवन से गांव-गांव में भरोसा लौटा है कि सरकार यदि चाहे तब मरी हुई नदी में भी फिर से जीवन बह सकता है। उत्तर प्रदेश अब जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन का आदर्श राज्य बनता जा रहा है।

संपादकीय कोयलांचल संवाद

वैध सूदखोरी बना फांसी का फंद़ा अवैध से ज्यादा खतरनाक वैध

कर्ज से कई गुना ब्याज एवं सूदखोरी के कारण भारत में हर साल हजारों की संख्या में आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रहे हैं। सरकार ने सूदखोरी से लोगों को बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों से गरीबों एवं मध्यम वर्ग को ऋण दिलवाने का काम किया। साहूकारों के चंगुल से आम आदमियों को छुड़ाकर कानूनी बैंकिंग सिस्टम को विकसित किया, ताकि सूदखोरी के असीमित ब्याज और सूदखोरों की दादागिरी से आम लोगों को बचाया जा सके। अब देखने में आ रहा है राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी बैंकों एवं एनएफसी कंपनीयों द्वारा आम लोगों को जो ऋण मुहैया कराया जा रहा है। जिस तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं, समय-समय पर जो बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने पुराने सूदखोरों को भी मात कर दिया है। सरकारी बैंकों और निजी बैंकों के अलावा एनएफसी कंपनियों से जो ऋण आम जनता ले रही है। उनसे जिस तरह का ब्याज को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जा रहा है। मूलधन और ब्याज नहीं दिए जाने पर जिस तरह से किसानों और गरीब आदमियों की कुर्की के जरिए ऋण की वसूली की जाती है । 20०4 के बाद से बैंकों, सहकारी समितियों, तथा नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर ऋण दिया जा रहा है। ऋण की समय पर अदागिरी नहीं होने के कारण बैंकों, सहकारी समितियों और एनएफसी कंपनियों द्वारा जिस तरह से मूलधन पर ब्याज, दंड ब्याज, जुर्माना तथा तरह-तरह की शुल्क ज़रूरकर चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर वसूल कर रहे हैं। सरकारी बैंकों का ऋण 4 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा हो जाता है। एनएफसी कंपनी जो ऋण देती हैं उसमें 36 फीसदी तक ब्याज वसूल किया जा रहा है। ऋण की वसूली के लिए बाउंस लगाए जाते हैं। लोगों के सिर पर कर्ज का बोझ लाद दिया गया है। उनका आय से कई गुना ज्यादा कर्ज आम आदमी ने ले लिया है। जब वह किससे नहीं चुका पाते हैं, उनका ऋण कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अब जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उसमें लोग आत्महत्या करने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से परिवार सहित आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हजारों किसानों द्वारा हर साल कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार जीरो फ्रीसदी ब्याज पर 6 माह के लिए ऋण देती है। एक दिन भी लेट हो जाने पर शुक्र दिवस से 14 फ्रीसदी ब्याज, दंड ब्याज, जुर्माना और तरह-तरह के शुल्क लगाकर किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ इतना लाद दिया जाता है। जिससे वह नहीं चुका पाता है। उनकी जमीनों को बैंकों द्वारा नीलाम कर दिया जाता है। भोले भाले किसानों की जमीने षडयंत्र पूर्वक बहुत कम कीमत पर नीलाम हो जाती हैं। उसके बाद भी उनका कर्ज नहीं उतरता है। कर्ज में फंसे हुए लोग जब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का पैसा नहीं चुका पाते हैं। वह सूदखोरों से कर्ज लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कर्ज चुकाने का प्रयास करते हैं। जिसके कारण दोहरे कर्ज में फंसकर छोटे-छोटे से बच्चों के बेचने और बंधक रखने के समाचार रोजाना पढ़ने में मिल रहे हैं। कर्ज चुकाने के लिए पत्नियों को गिरवी रखने के समाचार तथा हत्या जैसे समाचार आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। लोग जरूरत के लिए कम, दिखावे के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। बाजारवाद और भौतिक आवश्यकताएं गरीब से गरीब परिवार के घरों तक तक पहुंच गई हैं। पढ़ाई के लिए शादी के लिए इलाज के लिए खाने पीने के समान के साथ-साथ अब मोबाइल इंटरनेट टीवी फ्रिज मोटरसाइकिल इत्यादि के लिए देखा देखी में कर्ज ज्यादा ले रहे हैं। जिसके कारण और कर्ज नहीं चुका पाते हैं। दबाब के कारण आत्म हत्या कर जीवन समाप्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज के संबंध में कई फैसले पहले भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला यह भी है कि मूल से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस पुराने फैसले का पालन बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है मूलधन से कई गुना ज्यादा ब्याज गरीबों एवं मध्यम वर्ग से वसूल किया जा रहा है। सूदखोरी और साहूकारी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। गरीबों के लिए सरकार योजनाएं बनाकर संचालित करती है। सभी योजनाओं में ब्याज एवं वसूली के लिए जो नियम बनाए गए हैं। वह पुराने सूदखोरों से भी मात करने वाले हैं। जीरो फ्रीसदी पर किसानों को ऋण देने तथा कम ब्याज दर पर ऋण देने के नाम पर गरीबों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कर्ज वसूली के लिए वित्तीय संस्थानों को विशेष अधिकार दे दिए हैं। कानून के जरिए जिस तरह से ऋण की वसूली की जा रही है। उसने एक बार फिर से सैकड़ों वर्ष पुराने शोषण की याद दिला दी है। रिजर्व बैंक द्वारा संचालित वित्तीय संस्थानों और गुंडागर्दी के बल पर अवैध रूप से सूदखोरी करने वाले में कोई अंतर नहीं रह गया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बड़े आदमियों के लिए अलग कानून बनाए जा रहे हैं। गरीब और बेहसारा लोगों के लिए अलग कानून बने हैं। गरीबों का ऋण बेशरम की तरह बढ़ता है। भारत में आत्महत्या और हत्याएं बढ़ी तेजी के साथ बढ़ गई हैं। मूलधन से ज्यादा ब्याज की वसूली पर तत्काल रोक लगाने से गरीबों और मध्यम वर्ग को आत्म हत्या से रोका जा सकता है।

संवैधानिक संकट : एक-देश: एक-चुनाव... स्तंभों में टूटकर संभावित...?

ओमप्रकाश मेहता

केन्द्र की मोदी सरकार को प्रमुख कार्यसूची में एक प्रमुख कार्य पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराना भी है और यह अहम् कार्य मोदी सरकार इसी कार्यकाल के दौरान कराना चाहती है जिससे कि अगले लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव एक साथ करा सके, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक तो बाद में पहले प्रशासनिक रूकावटें सर्वाधिक है और यह प्रस्ताव ठोस रूप से सामने आने के पहले ही अभी से न्याय पालिका व विधायिका के बीच घमासान शुरू हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस दिशा में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों के प्रति विरोध व्यक्त किया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस मसले पर गठित समिति के सामने पेश होकर अपनी आपत्ती दर्ज करवा दी थी। सरकार के इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री का तर्क यह है कि देश की आजादी के बाद यह पद्धति लागू थी और देश के सभी चुनाव कई वर्षों तक एक साथ हुए, किंतु सत्तर के दशक में यह नियम भंग हो गया क्योंकि विधायसभाओं के असमय कुछ मुद्दों पर भंग करके का सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए राज्य के विधानसभा चुनाव संसद से पिछड़ गए और फिर ये चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे, जिससे देश को भारी आर्थिक क्षति के साथ राजनीति भी प्रभावित हुई। अब मोदी सरकार पुरानी परम्परा को फिर से लागू करना चाहती है, जिससे देश में पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एकसाथ हो सके और सरकारें निश्चित होकर निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि में अपने-अपने चुनावी घोषणा-पत्र को मूर्तरूप दे सके, मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा भी की और अनेक प्रतिक्रियाएँ दल इस प्रस्ताव से सहमत भी हो गए, किंतु कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि यदि मोदी जी अपने प्रयासों से राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त कर भी लेते है तो फिर प्रजातंत्र के प्रमुख स्तंभों न्याय पालिका और कार्य पालिका की पूर्ण सहमति कैसे प्राप्त होगी ? फिर एक अहम् सवाल यह भी है कि क्या मोदी जी इस प्रस्ताव को संसद से पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत से ज्यादा जनसमर्थन प्राप्त कर सकेंगे, जो इसे लागू करने की पहली शर्त है ? फिर भी मोदी सरकार को पूरी उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव 20२९ तक यह नहीं भी हो पाया तो उसके बाद के चुनाव २०३४ तक तो यह बात-प्रतिशत संभव है और यह होकर रहेगा। किंतु फिलहाल इस मसले पर मतवैभिन्य जारी है कि इस हेतु क्या चुनाव आयोग को विशेष शक्तियाँ प्रदान करना जयजय होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ प्रत्यक्षी दल भी इस मसले पर गंभीर चिंतन कर रहे है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश पहले ही इस मामले में अपनी प्रतिरोधी राय प्रकट कर चुके है तथा चुनाव आयोग को शक्तियाँ देने वाले संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अपनी असहमति के साथ चिंता भी जताई है तथा कहा है कि चुनाव आयोग को बेलगाम ताकत मुहैया नहीं करवा सकेंगी। फिल हाल इस मसले पर कई स्तरों पर गंभीर चिंतन जारी है अब अंतिम फैसला क्या होता है, उसी की प्रतीक्षा है।

अजय टट्टा

पिछले कुछ सालों में लाखों ड्राइवर ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हैं। क्योंकि इसमें उन्हें काम करने की आजादी, अनुकूलता और तकनीकी सुविधा मिलती है। हालाँकि बढ़ते कमीशन, अस्पष्ट नीतियों, मनमाने निलंबन और सुरक्षा के अभाव ने इस वादे को कई लोगों को संके। ड्राइवरों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ऐप उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन जागरूकता, ग्राहक से बातचीत, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित ४० घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा, ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं। यात्रा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और किराए में हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म पर सभी ड्राइवरों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य जांच और व्यवहार प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक वाहन में इन ऐप आपातकालीन बटन, जीपीएस-आधारित निगरानी और यात्राओं को साझा करने की सुविधाएँ होनी चाहिए, जो सभी यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाती हैं। राज्य की निगरानी में एग्रीगेटरों द्वारा एक २४x७ निर्यंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

यात्रियों के लिए एक और बड़ा लाभ किरायों और विशेष परिस्थितियों में किराये में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) का नियमन है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैं: राज्य की नीति के आधार पर किराए में वृद्धि की सीमा आधार किराए के १.५ से २ गुना तक सीमित की गयी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च मांग के समय यात्रियों का शोषण न हो। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म को किराए का विवरण पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें आधार किराया, गतिशील शुल्क, एग्रीगेटर का हिस्सा और सरकारी कर शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं। एग्रीगेटरों को भारत-स्थित सर्वरों पर उपयोगकर्ता डेटा का संग्रह करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सहित डेटा सुरक्षा रूपरेखा का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डेटा का दुरुपयोग या लीक न होना सुनिश्चित हो सके और भारत की संप्रभु डेटा नीतियों के अनुसार इसे सुरक्षित रखा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत@२0४७ के विजन, जो समावेशी और सतत विकास पर जोर देता है तथा दिव्यांगजनों के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, दिशानिर्देश में इस बात को अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर बेड़े का एक हिस्सा दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाएं और कार्यक्षम में ड्राइवरों के रूप में दिव्यांगजनों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। ऐसे वाहनों की संख्या राज्यों द्वारा स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

स्थायित्व के लिए एक बड़े प्रयास के तहत, एग्रीगेटरों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता है। संबंधित वायु नियामक निकाय वाहन-परिचालन प्लेटफार्मों के लिए राज्यवार ईवी

कटौती, किराया विभाजन और जुमाने के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक एग्रीगेटर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करेगा, जहाँ यात्रा रद्दीकरण, भुगतान विवाद या निलंबन जैसे मुद्दों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके। ड्राइवरों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें ऐप उपयोग, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, लैंगिक संवेदनशीलता, दिव्यांगजन जागरूकता, ग्राहक से बातचीत, डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित ४० घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा, ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं। यात्रा सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और किराए में हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म पर सभी ड्राइवरों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य जांच और व्यवहार प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक वाहन में इन ऐप आपातकालीन बटन, जीपीएस-आधारित निगरानी और यात्राओं को साझा करने की सुविधाएँ होनी चाहिए, जो सभी यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाती हैं। राज्य की निगरानी में एग्रीगेटरों द्वारा एक २४x७ निर्यंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। यात्रियों के लिए एक और बड़ा लाभ किरायों और विशेष परिस्थितियों में किराये में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) का नियमन है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैं: राज्य की नीति के आधार पर किराए में वृद्धि की सीमा आधार किराए के १.५ से २ गुना तक सीमित की गयी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च मांग के समय यात्रियों का शोषण न हो। इसके अलावा, प्लेटफ़ॉर्म को किराए का विवरण पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें आधार किराया, गतिशील शुल्क, एग्रीगेटर का हिस्सा और सरकारी कर शामिल हैं। महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं। एग्रीगेटरों को भारत-स्थित सर्वरों पर उपयोगकर्ता डेटा का संग्रह करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सहित डेटा सुरक्षा रूपरेखा का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डेटा का दुरुपयोग या लीक न होना सुनिश्चित हो सके और भारत की संप्रभु डेटा नीतियों के अनुसार इसे सुरक्षित रखा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत@२0४7 के विजन, जो समावेशी और सतत विकास पर जोर देता है तथा दिव्यांगजनों के सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, दिशानिर्देश में इस बात को अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर बेड़े का एक हिस्सा दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाएं और कार्यक्षम में ड्राइवरों के रूप में दिव्यांगजनों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। ऐसे वाहनों की संख्या राज्यों द्वारा स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

स्थायित्व के लिए एक बड़े प्रयास के तहत, एग्रीगेटरों को अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता है। संबंधित वायु नियामक निकाय वाहन-परिचालन प्लेटफार्मों के लिए राज्यवार ईवी

लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तथा यह भारत के जलवायु और स्वच्छ वायु लक्ष्यों के अनुरूप है। दिल्ली की 'देवी' (डीईवीआई) बसें जैसी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ ईवी एकीकरण के उदाहरण हैं, जो पहले से ही मौजूद हैं। ये दिशानिर्देश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, विशेष रूप से अनुच्छेद ३१ के अनुरूप हैं, जो राज्य को निर्देश देता है कि गिंग श्रमिकों सहित नागरिकों के लिए आजीविका के पयांत साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद २१, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, की न्यायालयों द्वारा की गयी व्याख्या में सुरक्षित कार्य वातावरण के अधिकार और सम्मान के साथ आवागमन के अधिकार को शामिल किया गया है। कई न्यायिक निर्णयों ने यात्रा वाहन परिचालन क्षेत्र में उचित नियमन की आवश्यकता पर बल दिया है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (१९८२) और ओला टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (१९८५) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद २ के एक अभिन्न अंग के रूप में आजीविका के अधिकार पर जोर दिया। उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (२०२०) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एग्रीगेटर के मूल्य निर्धारण और लाइसेंस प्रक्रिया को विनियमित करने के राज्य सरकारों के अधिकार को बरकरार रखा, जहाँ यह कहा गया कि उपभोक्ता हितों को पूरी तरह से बाजार-संचालित मूल्य निर्धारण मॉडल के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये फैसले २०२५ के दिशानिर्देशों के तहत गिंग श्रमिकों को दी गई कई सुरक्षाओं के कानूनी आधार हैं। दिशानिर्देश मोटर वाहन एग्रीगेटरों के लाभ और यात्रियों के हितों के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है, साथ ही यह अक्सर उद्देशित गिंग श्रमिकों के अधिकारों को प्रार्थमिकता देता है। माननीय प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप, नए दिशानिर्देश एक सरल नियामक प्रणाली प्रदान करते हैं। अब एग्रीगेटर ६० दिनों के भीतर सभी राज्यों में लागू सभी प्रकार के मोटर वाहनों के लिए एकल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इससे यात्री वाहन परिचालन कंपनियों के लिए द्वाइविंग टेस्ट सुविधा की व्यवस्था करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके बजाय, अब उन्हें मंत्रालय की वाहन परिचालन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इन केंद्रों का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रशिक्षण को सुलभ बनाना है, जिसमें जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के आधार पर आईडीटीआर के लिए १७.२५ करोड़ रुपये, आरडीटीसी के लिए ५.५ करोड़ रुपये और डीटीसी के लिए २.५ करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। ये संस्थान न केवल व्यक्तियों को उच्च-गुणवत्ता वाले वाहन परिचालन कौशल प्रदान कर रहे हैं, बल्कि देश भर में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित ड्राइवरों का एक समूह बनाने में भी योगदान दे रहे हैं। इस पहल से सड़क सुरक्षा बढ़ाने और भारतीय सड़कों पर यातायात दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की आवश्यकता है। सरकार ने वर्ष २०३० तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को ५०% तक कम करने

का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, यह स्वीकार करते हुए कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित ३% का आर्थिक नुकसान होता है। इन दिशानिर्देशों का जारी होना भारत के मजबूत संघीय ढाँचे और संवैधानिक प्रावधानों की प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार परिवहन समवर्ती सूची का विषय है, जो राज्यों को एग्रीगेटरों के लाइसेंस और संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा १३ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए ऐसे दिशानिर्देश या लाइसेंस प्रक्रिया जारी करने में सक्षम बनाती है। यह पछि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए, मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश २०२५ का राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए पालन किया जा सकता है। लेकिन, राज्यों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। एग्रीगेटरों को लाइसेंस जारी करना, किराया संरचना और उच्च मांग की अवधि में किराया वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) की निगरानी करना, चालक प्रशिक्षण और सत्यापन लागू करना, अनुपालन का उल्लंघन करने वाले प्लेटफ़ार्मों को दंडित करना, साझा गतिशीलता मॉडल के तहत यात्रियों के लिए गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के उपयोग को अधिकृत करना, एग्रीगेटर बेड़े के लिए इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। जिम्मेदारियों का यह विभाजन भारत के सहकारी संघवाद के मॉडल को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ नीति निर्माण केंद्रीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन संदर्भ-संवेदनशील और राज्य-विशिष्ट है। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, २०२५ भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील और समय-अनुकूल कदम है। इस पहल की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, जन जागरूकता और प्लेटेफ़ॉर्म अनुपालन पर निर्भर करेगी। यदि राज्य इसका पालन करते हैं, तो इसमें यात्री वाहन परिचालन सेवाओं को शहरी परिवहन के एक सुरक्षित, अधिक जवाबदेह और अधिक समावेशी साधन में बदलने की क्षमता है, जो पूरे देश में ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे देश में जहाँ अनौपचारिक श्रमिकों का नीति-निर्माण में अक्सर प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, ये दिशानिर्देश एक महत्वपूर्ण बदलाव के प्रतीक हैं। ये दिशानिर्देश ऐप-आधारित ड्राइवरों को न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में बल्कि अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं वाले एक श्रमिक के रूप में देखते हैं। ये दिशानिर्देश यात्री को केवल एक उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नागरिक के रूप में मान्यता देते हैं जो सुरक्षित, सस्ती और पारदर्शी सेवाओं का हकदार है। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, २०२५ भारत में डिजिटल मोबिलिटी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पथर है। एग्रीगेटरों के लिए स्पष्ट मानक और जिम्मेदारियाँ निर्धारित करके, ये दिशानिर्देश ड्राइवरों के लिए उचित आय और सामाजिक सुरक्षा, यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा और सुविधा तथा पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं पर जोर देते हैं। यह संतुलित और समावेशी प्रेमवर्क न केवल भारत की बढ़ती गिंग अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के २०४७ तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है।

भारत माता का दुश्मन है चीन जिससे पास जाना देशहित में नहीं है



प्रतिशत तक संवर्धित है और १० परसेंट करने में कम से कम ५साल लंगेंगे ये दूसरे बम जैसा नहीं है कि जब चाहे बना लिए उसमें रेंडियो। परमाणु हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इसे लगभग १० प्रतिशत तक संवर्धित करने की आवश्यकता है अतः ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब अमेरिका डील कर रहा अब उसे इजराइल से कोई मतलब नहीं रहा यही बात अब दूसरे देश क्रो भी सिखने की जरूरत है यदि आपके पास अपना सामर्थ है तो युद्ध करो बरना आपस में समझौता कर लो हकीकत ये है कि भारत द डेली टेलीग्राफ और अन्य स्रोतों के अनुसार, चीन ने मई और जून २०२० के बीच भारतीय गरत वालें ६० वर्ग किलोमीटर (२३ वर्ग मील) क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और पाक अधिकृत काश्मीर में अपना नेटवर्क बना रहा है और चीन ने कश्मीर के करीब २० फीसदी हिस्से पर कब्जा किया है. इस हिस्से को अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है. चीन और भारत के बीच जब १९६२ में युद्ध हुआ तो उसने भारत के इस पूरे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था. ये जम्मु-कश्मीर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जिसे लेकर पिछले कई सालों से भारत और चीन के बीच तनाव है.चीन ने केवल भारत को ही नहीं परेशान कर रहा है बल्कि तिब्बत क्रो भी कब्जे में लिया और उनके धर्म गुरु दलाई लामा भारत में हैं और तिब्बत का यहाँ एक अस्थाई सरकार भी धर्मशाला में है जिसे तिब्बत का अस्थाई सरकार धर्मशाला में है और जिसे तिब्बत सेंट्रल एडमिनिस्टर कहते हैं और ये सभी भावानु बुद्ध को मानने वाले शांति प्रिय लोग है यहाँ उनके सारे मंत्रालय भी हैं जिसमें रक्षा नहीं है क्योंकि ये भारत के हिस्से में है ये १९५६ से भारत में पंडित नेहरू के कहने पर बड़ी संख्या में अपने धर्म गुरु दलाई लामा के साथ भारत आए थे जब तिब्बत ने १६ बिंदु के कारा को न मान कर तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया जो चीन की बाहबाही करते है जरा सा अपना वीर योद्धा पर भी ध्यान दें सिमांचन का ग्लेशियर जो भारत को पाकिस्तान और चीन द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को रोकने

में मदद करता है.वहाँ का तापमान -३० डिग्री में अपने जवान किस तरह सीमा की रक्षा कर रहे हैं और ज़ंदगी में क्या पाया भारत माता के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया चीन ने कश्मीर के करीब २० फीसदी हिस्से पर कब्जा किया है. इस हिस्से को अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है. चीन और भारत के बीच जब १९६२ में युद्ध हुआ तो उसने भारत के इस पूरे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था. ये जम्मु-कश्मीर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जिसे लेकर पिछले कई सालों से भारत और चीन के बीच तनाव है.इसलिए जहाँ देखें चीन की धरती है वहीं कदम भी रखना देश के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ वो आखिर आपकी क्या सुनेगा और खून का घुट पी कर आना पड़ेगा भारत स्वतंत्र देश है हम क्या ले क्या लेते ये मेरा अधिकार है चीन से तो बना हुआ क्रोई सम्मान में तो नहीं रहता हूँ यहाँ तक की चाइनीज फूड भी क्योंकि देश सर्वोपरि है हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर है तभी तो केवल में जासूसी करने आए एक ब्रिटिश विमान क्रो लॉक ही कर दिया चीन से सामान ही ना लो महात्मा गाँधी इसलिए विदेशी चीजों का विह्वार करते थे लेकिन आजादी के बाद देश का दुर्भांय ही कहे हमने उस पर अमल नहीं किया और आजादी के ७७ साल बाद भी चीन की चाल क्रो समझ नहीं रहे है ये बाद में अत्यंत हानिकारक होगा.इसलिए चीन के समान जब भारत में देखता हूँ तो कुछ समय के लिए सोचता हूँ सस्ता तो है लेकिन ये खरीदने से चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसी पैसे से फिर आतंकवादी क्रो भारत के खिलाफ हथियार देगा छोड़ो इसे नहीं चाहिए देश सर्वोपरि है.इससे विदेश में न्यूज़ में अच्छा नहीं लग रहा है भारत के स्वाभिमान का प्रश्न है भारतीय लोग भगवान राम के भक्त हैं जो मर सकते हैं लेकिन देश से कभी चीन और पाकिस्तान की धरती पर पैर नहीं रखेंगे जिन्होंने हमारे ही भाई बहन के पहलगांव में आतंकवादी हमले में मारे गए थे और पाकिस्तान के साथ युद्ध में चीन ने खुला समर्थन किया था ऐ मैं नहीं सेना के उप प्रमुख कह चुके हैं अतः सर कटा सकते हैं लेकिन दुश्मन के आगे सर नहीं झुका सकते हैं यही गुरु गोविन्द सिंह जी ने भी भारतीय क्रो एक संदेश दिया कि अपना ईमान धर्म कभी दुश्मन के आगे नहीं झुकना शरीर का क्या है ऐ तो मरने के लिए ही पैदा हुआ है लेकिन भारत माता के सम्मान में ही मरेगा और कभी दुश्मन के सामने कदम भी नहीं रखेगा क्योंकि उसने हमें नहीं देश की सेना क्रो कुचलने का प्रयास किया लेकिन हमारे सैनिकों ने मुहोड़ जबाब दिया. सेना के स्वाभिमान क्रो समझना चाहिए वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ते हैं वे देश के हीरो है जो अपनी जान को बापों लगा कर हम सभी की रक्षा कर भारत माता क्रो सर्वोपरि मानते हैं उसे छुपाने के लिए कुछ मीडिया का ऐ कहना की अमेरिका क्रो भूँ दिखाने के लिए ऐ वहाँ अच्छा रिश्ता के गए हैं लेकिन कैसे होगा धोखेबाज चीन से जब हमारे वीर सैनिक दलवान में शहीद होते हैं और सीमा में गोली खाते है क्या देश का सम्मान यहीं है एक तरफ आप खुनी लोगों के आतंकी क्रो सपोर्ट करो और फिर देश का बड़े ओहादा के मंत्री क्रो वहाँ जाना कहीं तक उचित है अमेरिका तो बहुत दूर है लेकिन जो सामने अपना दुश्मन खड़ा है उसे कैसे भूल सकते हैं इससे सेना का अपमान होता है देश सर्वोपरि है उसकी रक्षा करना किसी एक की नहीं १४० करोड़ लोगों की ताकत है जो दुश्मन के दरवाजे की ओर जाना तो दूर ताकझोंक तक नहीं करेगा. वन्दे मातरमा

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए करें आवेदन



भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का सपना देखने वाले साहसिक युवाओं के पास अच्छा अवसर है। वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31

जुलाई 2025 है।

योग्यता

12वीं पास साइंस और आर्ट्स दोनों विषय के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर वायु भर्ती का फॉर्म है। साइंस से आवेदन करने वाले कैडिडेट्स का 12वीं में मैथमेटिक्स/

फिजिक्स/और इंग्लिश विषय के साथ न्यूनतम 50 फीसदी अंकों से होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50 फीसदी अंक होने चाहिए। मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में मैकेनिकल/ऑटोमोबाइल/कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ईस्ट्रुमेंटेशन टेक्नोलॉजी/इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स करने

वाले उम्मीवार भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आर्ट्स स्ट्रीम के उम्मीदवारों की भी न्यूनतम 50 फीसदी अंक होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के अलावा आयु और हाइट संबंधित योग्यता भी मांगी जाती है।

उम्र

एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के रूप में भर्ती के लिए कैडिडेट्स की आयु 17.5 साल से अधिकतक 21 साल तक की गई है। ऐसे में कैडिडेट्स की जन्मतिथि 02 जुलाई 2005 से 02 जनवरी 2009 तक होनी चाहिए।

लंबाई

पुरुष और महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेमी होनी चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में राहत भी दी गई है। हाइट के हिसाब से ही शरीर का वजन होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आदि चरणों के माध्यम से कैडिडेट्स का चयन किया जाएगा।

वेतन

अग्निवीर वायु में चयन होने के बाद उम्मीदवार को 30,000 रुपए महीने सैलरी दी जाएगी। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे। साल के हिसाब से इनमें भी बढ़ोतरी होगी।

परीक्षा तिथि

अग्निवीर वायु की लिखित परीक्षा 25 सितंबर 2025 से संभावित तौर पर शुरू हो सकती है।

राशिफल

शुभ संवत 2082, शाके 1947, सौम्य गोष्ट, श्रावण कृष्ण पक्ष, वर्षा ऋतु, गुरु उदय पूर्व शुक्रोदय पूर्व तिथी, अष्टमी, शुक्रवासरे, अश्वनी नक्षत्रे, सु/ध योगे, कोलव करणे, मेष की चंद्रमा, मूल समाप्त रात्रि 1/23 सर्वाथ सिद्धयोग सर्वाथ सिद्ध योग तथापि पूर्व दिशा की यात्रा शुभ उत्तम तथा फलदायी होगी।

आज जन्म लिए बालक का फल.....

आज जन्म लिया बालक योग्य, बुद्धिमान, चपल, चतुर, चंचल, स्वभिमानी, उत्तम वृत्ति वाला, योगी-भोगी, कुशल वक्ता-अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कम्प्यूटर इंजीनियर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, बैंक कर्मचारी, लेखापाल, एमबीए, एमसीए करने वाला, धनी-माननी होगा।

मेघ राशि :- कार्य बाधा, स्वभाव में उद्धिन्नता तथा दुःख अवश्य ही बनेगा, कार्य पर ध्यान दें।

वृष राशि :- आरोप से बचें, कार्यगति मंद रहेगी, क्लेश व अशांति अवश्य ही बनेगी, धैर्य रखें।

मिथुन राशि :- योजनायें पूर्ण होंगी, धन लाभ होगा, आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा, समय का ध्यान रखें।

कर्क राशि :- मित्र सुख वर्धक होगा, कार्यगति में सुधार होगा, चिन्तायें कम होंगी, सोच-विचार कर कार्य करें।

सिंह राशि :- सामर्थ्य और धन अस्त-व्यस्त रहेगा, सतर्कता से कार्य अवश्य निपटायें, विचार पूर्वक निर्णय लें।

कन्या राशि :- मनोबल उत्साहवर्धक होगा, कार्यगति में सुधार होगा, चिन्ता में कमी होगी, धैर्य रखें।

तुला राशि :- मान-प्रतिष्ठा के साधन बनेंगे, स्त्री से सुख-शांति अवश्य ही रहेगी, मित्र सहयोग करेंगे।

वृश्चिक राशि :- अग्नि, चोटादि का भय, व्यर्थ भ्रमण से धन व्यय होगा, रुके कार्य अवश्य बनेंगे।

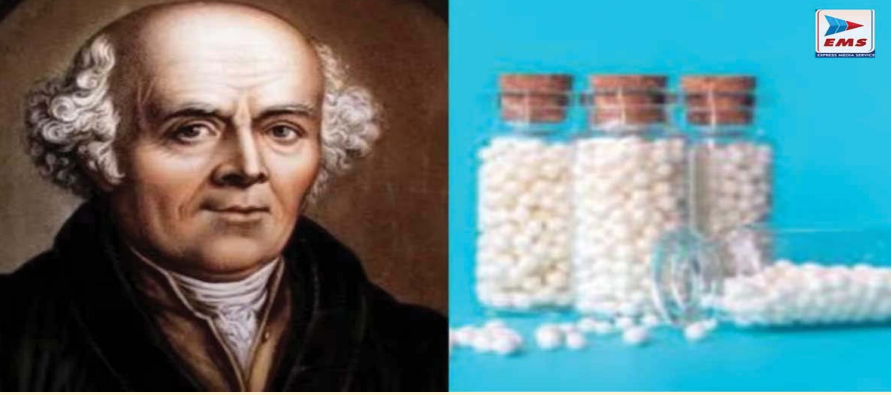
धनु राशि :- मानसिक क्लेश व अशांति, मानसिक विभ्रम तथा भय की स्थिति रहेगी, सावधानी से कार्य करें।

मकर राशि :- विवाद ग्रस्त होने से बचें, तनाव, क्लेश व मानसिक अशांति का वातावरण रहेगा।

कुंभ राशि :- धन लाभ, आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा, इष्ट मित्र सुखवर्धक होगा, समय का ध्यान रखें।

मीन राशि :- भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति, समय उल्लास से बीतेगा, मनोवृत्ति उत्तम रहेगी, अति उत्साह से बचें।

होम्योपैथिक डॉक्टरों की मांग बढ़ी



आजकल होम्योपैथिक की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इन दवाओं के दुष्प्रभाव नहीं होने के कारण दुनिया भर में होम्योपैथिक डॉक्टरों की भी मांग बढ़ती जा रही है। इससे इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो छात्र होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आने के लिए इन बातों की जरूरत रहेगी।

योग्यता

होम्योपैथी कोर्स में प्रवेश पाने की चाहत रखने वाले छात्रों को विज्ञान से 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं कक्षा में छात्रों के कम से कम अंक 50 फीसदी होने चाहिए। वहीं आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार के 45फीसदी अंक होना जरूरी है। उम्र : छात्र की कम से कम उम्र 17 साल होनी चाहिए। छात्र का नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। बता दें कि होम्योपैथी पाठ्यक्रमां में एडमिशन के लिए तमाम संस्थान परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। वहीं कई संस्थान नीट के आधार पर ही प्रवेश देते हैं। बता दें कि होम्योपैथिक कोर्स करने के लिए तमाम तरह के सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्सज की अवधि 3 से 6 महीने की होती है।

डिप्लोमा कोर्स

होम्योपैथी में कई प्रकार के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कराए जाते हैं। इन कोर्स में आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन और डिप्लोमा इन होम्योपैथी एंड मेडिसिन आदि कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सज की अवधि 1-2 वर्ष की होती है। स्नातक स्तर पर होम्योपैथिक कोर्स करने के लिए छात्र बीएचएमएस और बीईएमएस आदि पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। इन कोर्स की अवधि 3 से 5 साल की होती है।

बीएचएमएस कोर्स

BHMS यानी की बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स में बायोलॉजी, शरीर विज्ञान और चिकित्सा की तमाम शाखाओं पर बुनियादी और उन्नत ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कई विषय पढ़ाए जाते हैं। वहीं डिग्री प्राप्त करने से पहले छात्र को 1 साल की इंटरशिप पूरी करनी होती है। कैरियर होम्योपैथी के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोग होम्योपैथिक इलाज में भरोसा जताते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक पर होम्योपैथिक दवाएं समान रूप से असर करती हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है। जिनमें से माइग्रेन, अवसाद, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, रूमेटोइड गटिया, एलजी, खांसी और सर्दी, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम और प्रीमेस्ट्रुअल सिंड्रोम आदि का इलाज शामिल है। छात्र इस कोर्स की डिग्री व डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में काम कर अपने करियर को शुरू कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्षेत्रों की लिस्ट में आप होम्योपैथिक पेशेवर के तौर पर काम कर सकते हैं।

अब 12वीं में आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी बन सकेंगे कमर्शियल पायलट

अब 12वीं में आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कमर्शियल पायलट बनने का अपना सपना पूरा कर सकेंगे क्योंकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने के इच्छुक युवाओं के लिए 12वीं में गणित और भौतिकी विषयों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में अब अब आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी बतौर पायलट एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकेंगे। डीजीसीए की नई नीति के तहत त बदलाव करते हुए आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम वाले छात्र को भी भारत में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। पहले केवल साइंस के छात्र ही इस क्षेत्र में आ सकते थे। अब तक सिर्फ वही छात्र सीपीएल का लाइसेंस प्राप्त कर सकते थे, जिन्होंने 12वीं कक्षा में फिजिक्स और मैथ पढ़ा हो। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नये बदलाव से अब अन्य क्षेत्रों के भी अधिक से अधिक युवाओं को एविएशन करियर में प्रवेश मिल सकेगा। डीजीसीए ने ये बदलाव किए हैं कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए डीजीसीए ने पात्रता मानदंड में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक इन लाइसेंसों के लिए देश में मान्यता प्राप्त बोर्ड्स और संस्थानों से कैडिडेट्स का 10वीं पास होना जरूरी है। हेलीकॉप्टर, जायरोप्लेन, एयरोप्लेन, ग्लाइडर, बलून्स, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए स्टूडेंट पायलट



लाइसेंस होना चाहिए।

एयरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए प्राइवेट

पायलट लाइसेंस

पायलट लाइसेंस

फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का लाइसेंस

वहीं इन लाइसेंसों के लिए आवेदन करने

वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड और

संस्थानों से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए,

फिर उनकी स्ट्रीम कुछ भी हो।

कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में नैविगेशन,

फ्लाइट मैकेनिज्म और मौसम विज्ञान जैसे

कठिन सब्जेक्ट शामिल हैं। ऐसे में यह

फिजिक्स और मैथ्स में फाउंडेशन नॉलेज पर

अधिक निर्भर करते हैं। इन हालातों में अन्या

विषयों के छात्रों को अधिक मेहनत करनी

होगी।

हालांकि कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स

तो इन तकनीकी पहलुओं से जुझना पड़

सकता है। यह संभावित रूप से कोर्स के

साथ तालमेल रखने की क्षमता को प्रभावित

कर सकता है। इसलिए ट्रेनिंग संस्थानों में

एडिशनल फाउंडेशन कोर्सेस शुरू किया

जाएगा। इससे फीस और ट्रेनिंग की अवधि भी

बढ़ सकती हैं।

बता दें कि इस इंडस्ट्री में सुरक्षा और क्षमता

बनाए रखने जरूरत होती है। जहां पायलट

हार्ड-स्टेक इनवायरमेंट में काम करते हैं।

कमर्शियल एविएशन के लिए तेजी से फैसला

लेने और गहन तकनीकी समझ की जरूरत

होनी चाहिए। ऐसे में यह सुनिश्चित करना

जरूरी है कि सभी उम्मीदवार समान मानकों

को पूरा करें, फिर चाहे उनका ऐकेडमिक

बैकग्राउंड कुछ भी क्यों न हो।

ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंस सहित लेखन में भी है रोजगार इन नये क्षेत्रों में हैं अच्छे अवसर



निजी क्षेत्र में आजकल सेल्स, ब्रैंड मैनेजमेंट या मार्केट रिसर्च में काफी संभावनाएं हैं हालांकि इसके लिए आपकी कम्प्यूनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) काफी बेहतर होनी चाहिए। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये विकल्प मौजूद हैं

ऑपरेशंस मैनेजमेंट

अगर आप विपरीत परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं और तकनीक में आपकी रुचि है, तो आप यह स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यह क्वालिटी कंट्रोल और प्रॉडक्टिविटी

इंफ्रूवमेंट में अहम भूमिका निभाता है।

फाइनेंस

ये लोग बैंक एंड पर काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह की रीढ़ की हड्डी होते हैं।

सिस्टम मैनेजमेंट

यह स्पेशलाइजेशन आईटी से ताल्लुक रखता है और अच्छी टेक्निकल व बिजनेस समझ रखने वालों के लिए यह बेहतर रहता है। इसके बाद आपको सिस्टम कंसल्टेंट्स,

अकाउंट या प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में प्लेसमेंट मिल सकता है।

ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट

इसमें काम करने वाले लोगों पर पुरे ऑफिस के लोगों का मैनेजमेंट होता है। इसके लिए आपके पास अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी तरह बात करने की क्षमता और रिश्ते बनाने की कला का होना बेहद जरूरी है।

स्पेशलाइज्ड एमबीए

कुछ इंस्टिट्यूट्स प्लेसमेंट्स को ध्यान में रखकर कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, टेलिकॉम मैनेजमेंट, इश्योरेंस मैनेजमेंट, फॉरिन ट्रेड हैं। इस तरह के हैं कोर्स में एमबीए में दो साल की डिग्री के अलावा, एक साल का फुल टाइम प्रोग्राम, पार्ट टाइम एमबीए, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए जैसे विकल्प हैं। हालांकि हर विषय की अपनी-अपनी खूबी और खामियां हैं।

अगर आपको किताबें पढ़ना और अपने मन की बात को डायरी में लिखना पसंद है तो आप लेखन में भी अच्छा करियर बना सकते हैं, और खूब सारे पैसे भी कमा सकते हैं। लेखन में करियर बनाना चाहते हैं तो बस इन तीन बातों को अपने दिमाग में रख लें।

क्रिएटिव बने

लेखन के लिए क्रिएटिव दिमाग का होना बहुत जरूरी है। जिसे किसी भी राइटिंग कोर्स के जरिए सीखा नहीं जा सकता जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं उसमें पकड़ लाने के लिए आपको अखबार, नॉवल, कहानियों को लगातार पढ़ते रहना होगा तभी आप लिखने में महारत प्राप्त कर पाएंगे। एक बाद याद रखें कोई भी लेखन लिखते वक्त जितनी बढ़िया वर्तनी होगी उतना ही मजबूत आपका लेख होगा।।

सीधे तरीके से लिखे

अक्सर पाठक घुमावदार तरीके से लिखे हुए लेखन को पढ़ने से बचते हैं। उन्हें वहीं पढ़ना पसंद है जिसमें बात साफ और सीधे तरीके से लिखी गई हो। इसलिए प्वाइंट टू प्वाइंट लिखने की आदत डालें, ताकि आप कम वाक्य में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें सकें। एक लेखक को सफलता तभी मिलती है जब वह ताजा मामलों पर लिखता है। ऐसा ना हो कि देश और दुनिया में कुछ और बात चल रही है और आप अपने पाठकों को कोई और बात परोस रहे हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर अपडेट रहना होगा।। ताकि आप वही लिखें जो पाठक पढ़ना चाहते हैं।



रिजर्व बैंक घटाएगा ब्याज की दरें

घर, कार और वाहनों की बिक्री घटी, सस्ती लोन से बढ़ेगी मांग?



मुंबई (ईएमएस)। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की अगस्त माह में बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्याज की दरों को घटाने के बारे में निर्णय लेने की बात की जा रही है। जून माह की बैठक में रेपो रेट 0.5 फ़ीसदी घटकर 5.50 फ़ीसदी किया गया था। अभी तक इसमें एक फ़ीसदी की कटौती हो चुकी है। रिजर्व बैंक का मानना है कि 2025-26 में रिटेल महंगाई 2.1 फ़ीसदी पर आ गई है। जुलाई अगस्त माह में महंगाई दर 1 फ़ीसदी पर आ सकती है। 1 अप्रैल 2025-26 के बाद जिस तेजी के साथ महंगाई दर घट रही है। वह 1990 के बाद 2025 की प्रथम तिमाही में कम हुई है। जून माह में कारों की बिक्री 16 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। बड़े शहरों में घरों की बिक्री 20 फ़ीसदी तक घट गई है। जून माह में रल और आभूषणों में 7 फ़ीसदी की गिरावट निर्यात मे आई है। आयात भी भारत का लगभग 7 फ़ीसदी घटा है। मांग को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक, ब्याज दरों में अगस्त माह में और भी कटौती कर सकता है। इस बात की संभावना रिजर्व बैंक के सुत्रों द्वारा जताई जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञ भी यह मानकर चल रहे हैं। रिजर्व बैंक जल्द ही ब्याज की दरों को घटा सकता है। ताकि बाजार की मांग को बढ़ाया जा सके। कम ब्याज होने से लोगों की ईएमआई भी कम होगी। आम उपभोक्ता को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता उपभोक्ताओं को राहत नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.36 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। पिछले एक दिन से यहां ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ी फेरबदल देखने को नहीं मिली। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपए और डीजल 92.15 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है। चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपए तथा डीजल 92.34 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपए और डीजल 90.76 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बनी हुई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बना हुआ है। मार्च 2024 में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में प्रति लीटर दो-दो रुपए की कटौती की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कीमतों में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। सरकारी तेल कंपनियां योजना सुबह पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अपडेट करती हैं, जिससे उपभोक्ता हर दिन नवीनतम दरों से अवगत रह सकते हैं। हालांकि, मौजूदा स्थिरता से उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में भी कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

डीएलएफ की अंधेरी में 900 करोड़ की लजरी आवास परियोजना शुरू

मुंबई (ईएमएस)। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ लिमिटेड ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में एक बार फिर कदम रख दिया है। कंपनी ने अंधेरी (पश्चिम) में एक लजरी आवासीय परियोजना वेस्टपार्क की शुरुआत की है, जिसमें वह लगभग 900 करोड़ का निवेश कर रही है। डीएलएफ ने इस परियोजना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बिल्डर ट्राइडेंट समूह के साथ साझेदारी में विकसित किया है। यह कदम कंपनी की मुंबई बाजार में जुलाई 2023 में की गई पुनःप्रवेश घोषणा का हिस्सा है। डीएलएफ होम डेवलपर्स के एक अधिकारी के अनुसार, वेस्टपार्क परियोजना में कुल 416 लजरी अपार्टमेंट्स होंगे। यह परियोजना 5.18 एकड़ में फैली हुई है और यहां फ्लैट्स की कीमत 4 करोड़ से 7.5 करोड़ के बीच रखी गई है। इनकी कीमत 42,000 से 47,000 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी। उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल बिक्री से 2,300 करोड़ की आय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की शुरुआती प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही है और कंपनी पहले चरण में लगभग 200 यूनिट्स बेचने की योजना बना रही है। डीएलएफ अब तक 185 से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाएं पूरी कर चुका है और 35.2 करोड़ वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्र विकसित कर चुका है। इस नई परियोजना के साथ कंपनी ने मुंबई के प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूती से वापसी की है।

पंजाब में बनेगी 22 उद्योग-विशेष समितियां: संजीव अरोड़ा

चंडीगढ़ (ईएमएस)। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है, जिसके लिए 22 उद्योग-विशेष समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक समिति में 8 से 10 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। अरोड़ा ने बताया कि इन समितियों को सरकार को सुझाव देने और नीतिगत बदलाव सुझाने का अधिकार होगा। समितियों का कार्याकाल दो वर्ष का होगा, और उन्हें 45 दिन के भीतर अपनी पहली रिपोर्ट सौंपनी होगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर नई नीति का प्रारूप तैयार करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि यह नीति उद्योगों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द लागू की जाए।

भारत में रिकॉर्ड बिक्री से बीएमडब्ल्यू को मिली राहत

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत से सहित दुनिया भर में साल 2025 की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं एशिया में खासकर चीन में उसे बड़ा झटका लगा है। कंपनी की चीन में बिक्री पहली छमाही में 15.5 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि दूसरी तिमाही में 13.7प्रतिशत की कमी आई। पूरे एशियाई क्षेत्र में पहली छमाही में बिक्री 11.1प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 10.1प्रतिशत घटी। इसका कारण चीन की घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं और आर्थिक अनिश्चितता है। इस संकट ने बीएमडब्ल्यू को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर कर दिया है। हालांकि,



भारत बीएमडब्ल्यू के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। 2025 की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अब तक का सबसे अच्छा

भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद, लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 375.24 अंक के साथ 82,259.24 और निफ्टी 100.60 अंक के साथ 25,111.45 पर था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 101.55 अंक की गिरावट के साथ 59,519.10 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 22.75 अंक की कमजोरी के साथ 19,117.30 पर था।



एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी और एनर्जी लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, ट्रेट,

टाइटन, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा खूब चढ़े थे। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल टेक, इटरनल (जोमैटो), एलएडटी, टीसीएस, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व गुरुवार को शेयर बाजार में कमजोर साबित हुए थे। बाजार जानकार ने बताया कि भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि निवेशकों ने पहली तिमाही के नतीजों विशेष रूप से टेक्नोलॉजी और बैंकिंग क्षेत्रों में सुस्त घोषणाओं के बीच सतर्कता बरती है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के कारण लार्ज-कैप शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन और एफआईआई के

टेस्ला के आने से घरेलू ईवी कंपनियों पर फिलहाल नहीं पड़ेगा बड़ा असर



नई दिल्ली (ईएमएस)। टेस्ला ने भारत में अपनी मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी वाई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 60 लाख रुपये है। यह वाहन भारत में निर्मित नहीं होगी, बल्कि टेस्ला अपने शंघाई प्लांट से पूरी तरह निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में इसे आयात करेगी। भारत में आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 70 से 100 प्रतिशत तक टैक्स लगाता है, जो कार की कीमत को और बढ़ा देता है। इस कारण टेस्ला की कीमत घरेलू कंपनियों के मुकाबले काफी अधिक है। भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी और महिंद्रा की एक्सईवी 9ई जैसे मॉडल 21 से 31 लाख रुपये की कीमत रेंज में उपलब्ध हैं, जो टेस्ला के मुकाबले किरायती विकल्प हैं। इसी वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल टेस्ला की एंट्री से घरेलू ईवी निर्माताओं की बाजार हिस्सेदारी पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर टेस्ला की जून तिमाही में बिक्री में 13.5 फीसदी की गिरावट आई है और इसलिए भारत में प्रवेश टेस्ला के लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है। हालांकि, भारतीय बाजार में टेस्ला फिलहाल बीवायडी, ह्यूंडई, किआ जैसे ब्रांडों से 45-60 लाख रुपये की कीमत रेंज में मुकाबला करेगी। इस प्रकार, टेस्ला की एंट्री से घरेलू ईवी कंपनियों को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखाता, बल्कि यह बाजार को और प्रतिस्पर्धात्मक और उन्नत बनाने में मदद करेगी।

एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा



नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी (इंडिया) लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) गुरदीप सिंह का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे मूल रूप से 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद लिया गया है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और यह विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करती है। कंपनी के शीर्ष पद पर नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ गुरदीप सिंह एक और वर्ष तक कंपनी का नेतृत्व करेंगे। वहीं, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने इस पद के लिए 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था, जिनमें से कई उम्मीदवार एनटीपीसी और अन्य सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में शामिल थे। हालांकि पीईएसबी ने किसी भी उम्मीदवार को सीएमडी के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया। इस कारण से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के शीर्ष पद के लिए सही उम्मीदवार खोजने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं।

सोने का भाव 97,400 रुपए, चांदी लगभग 1,11,850 रुपए प्रति किलो



नई दिल्ली (ईएमएस)। चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत में गुरुवार को तेजी देखी जा रही है, जबकि सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। गुरुवार को सोने के भाव 97,400 रुपये, जबकि चांदी के भाव 1,11,850 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार सोने के वायदा भाव गिरावट और चांदी के भाव तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। मल्टी कर्माइट्री एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 277 रुपये की गिरावट के साथ 97,511 रुपये के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 97,788 रुपये था। इस समय यह 358 रुपये की गिरावट के साथ 97,430 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेज रही। एमसीएक्स

गिरावट के साथ 3,347.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव ने इस साल 3,509.90 डॉलर के भाव पर ऑल टाइम हाई छू लिया है। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 38.14 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला बंद भाव 38.11 डॉलर था। इस समय यह 0.11 डॉलर की तेजी के साथ 38.22 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

नायडू ने 2047 तक आंध्र प्रदेश को भारत का शीर्ष राज्य बनाने का खाका किया पेश



अमरावती (ईएमएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी में एक आर्थिक विकास योजना का विस्तृत खाका पेश किया। यह रिपोर्ट भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) के

सहयोग से गठित आर्थिक वृद्धि कार्यबल द्वारा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य 2047 तक आंध्र प्रदेश को भारत के अग्रणी और विश्वस्तरीय राज्यों में शामिल करना है। मुख्यमंत्री नायडू ने

कहा कि आंध्र प्रदेश 2047 तक भारत का सबसे उत्कृष्ट राज्य बन जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगा। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और बॉश के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण में रणनीतिक साझेदारी

दोनों कंपनियां मिलकर करेंगी काम



नई दिल्ली (ईएमएस)। टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने जर्मनी की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी रॉबर्ट बॉश जीएमबीएच के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोनों कंपनियां मिलकर असम और गुजरात में सेमीकंडक्टर निर्माण व चिप पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों की स्थापना करेंगी। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, असम में प्रस्तावित असेंबली और परीक्षण इकाई तथा गुजरात में स्थापित होने वाली फाउंड्री (चिप निर्माण इकाई) में दोनों कंपनियां मिलकर काम करेंगी। इस साझेदारी का

उद्देश्य भारत में एक समग्र और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना है, जो वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा कर सके। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि यह सहयोग

भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी वैश्विक ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा

कि ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को देखते हुए यह साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और लचीला बनाएगी। उन्होंने इसे भारत में तकनीकी क्षमता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

उत्पादन में सुधार और लागत को नियंत्रित करने में मदद करेगा।

ऑस्ट्रेलिया चोरी छिपे इजराइल को भेज रहा एफ-35 के पार्ट्स

रिपोर्ट से खुलासा, ऑस्ट्रेलिया पर युद्ध अपराध की कार्रवाई करने की मांग

तेहरान, (ईएमएस)। ईरान-इजराइल युद्ध में अमेरिका इजराइल की मदद तो कर करता ही है, वहीं आस्ट्रेलिया ने भी चोरी छिपे इजराइल को एफ-35 लड़ाकू विमान के पुर्जे भेजे। अब खबर आ रही कि ऑस्ट्रेलिया इजराइल के एफ-35 लड़ाकू विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स भेज रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया गुप्तचुप तरीके से इजराइल को एफ35 फाइटर जेट के पार्ट्स भेज रहा है। जांच में पया गया कि सिडनी से तेल अवीव जाने वाली उड़ानों में भेजे गए माल के कार्गो रिकॉर्ड में विमान के पुर्जे



के रूप में दर्ज थे।रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ दो अलग-अलग शिपमेंट भेजे गए, या फिर ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ एक बड़ा ट्रेड कर चुका है, जिसके तहत एफ-35 के पुर्जे उसे भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार 4 जुलाई को यह पुर्जे भेजे गए थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि विमान के पुर्जे

सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थाई एयरवेज की उड़ान टीजी472 के कार्गो होल्ड में लोड किए गए थे। यह उड़ान दोपहर 2:50 बजे बैंकॉक के लिए रवाना हुई थी और अल अल की उड़ान एलवायू82 से जुड़कर तेल अवीव पहुंची, जो 6 जुलाई को उत्तरीरिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि विमान के पुर्जों को

पैकिंग बताया गया था और उन पर ईएआर99 लिखा था। यह मैसेज साफ तौर पर दिखाता है कि कोई अमेरिकी सामान भेजा जा रहा है। हालांकि पैकेज का वजन केवल एक किलो बताया गया था। दस्तावेज में कहा गया है कि विमान के पुर्जों का खोत एफ-35 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन थी। रिपोर्टों में यह कहा गया है, लॉकहीड मार्टिन ही एफ-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर के पुर्जे बनाती है। इसके अलावा कोई और इसे नहीं बना सकता।शिपिंग रिकॉर्ड में माल के आपूर्तिकर्ता का नाम 'आरएएएफ', यानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स बताया गया है। दस्तावेज में माल पाने वाले का पता केवल तेल अवीव-जाफ़ा, इजराइल लिखा है। यह रिपोर्ट बताती है कि ऑस्ट्रेलिया

की सरकार चोरी छिपे इजराइल को फाइटर जेट के पार्ट्स भेज रही है।आस्ट्रेलिया सरकार पूरी दुनिया को इसके बारे में झूठ बोल रही है। रिपोर्टों में ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर युद्ध अपराध में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। गाजा में जारी युद्ध और नागरिकों की बढ़ती मौतों के बीच इजराइल को एफ-35 फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट्स देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार समूह और कुछ सांसदों का कहना है कि इस सप्लाई से इजराइल की सैन्य ताकत और बढ़ेगी, जिससे संघर्ष और गहरा जाएगा। आलोचकों का मानना है कि आस्ट्रेलिया का चोरी छिपे एफ35 के पार्ट्स भेजना युद्ध में एक पक्षकार माना जाएगा। यह अपराध की श्रेणी में आता है।

निमिषा प्रिया: मृतक के भाई ने कहा, पैसा नहीं चाहिए, भले फांसी में देर हो जाए

सना, (ईएमएस)। यमन में सजा-ए-मौत का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के लिए राहत का वक्त कुछ घंटे ही बचा है। अब तलाल आबदो मेहदी के परिवार ने फिर से कहा है कि वे ब्लड मनी स्वीकार नहीं करेंगे। तलाल आबदो मेहदी पर आरोप है कि उसने निमिषा प्रिया का उल्पीड़न कर उसका पासपोर्ट रख लिया था। पासपोर्ट हासिल करने के लिए ही निमिषा ने तलाल को ड्रस दिया था और उसकी ओवरडोज से वह मर गया था। मामले में निमिषा प्रिया को सजा-ए-मौत सुनाई गई है। उन्हें 16 जुलाई के दिन सजा मिलनी थी, लेकिन केरल के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार के दखल से फांसी को टाल दिया गया था।बताया गया कि निमिषा प्रिया के वकील और परिजनों को वक्त दिया जाएगा कि वे तलाल के परिवार को ब्लड मनी के लिए राजी कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तलाल के भाई का कहना है कि वे ब्लड मनी स्वीकार नहीं करेंगे। तलाल के गढ़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे परिवार ने समझौते के सभी



ऑफर खारिज किए हैं। हम चाहते हैं कि भाई की कातिल को सजा-ए-मौत ही मिले। माफी के सवाल पर अब्देलफतेह मेहदी ने कहा कि कोई माफी नहीं दी जा सकती। हम इस मामले में दीयत यानी ब्लड मनी स्वीकार नहीं करने वाले है।उन्होंने निमिषा के उन दावों को झूठा बताया जिसमें उसने कहा था कि तलाल मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उसे प्रताड़ित किया गया था। उनके मुताबिक, ये सब बातें उसे निर्दोष दिखाने के लिए गढ़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे परिवार ने समझौते के सभी

केस की लंबी कानूनी लड़ाई ने भी उनके परिवार को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए वे मुआवजे की कोई रकम नहीं लेना चाहते।रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबूबकर मुसलियार और यमन के चर्चित सूफी विद्वान शैख हबीब उमर बिन हाफिज मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मुलक के भाई भी शामिल हैं। यमन के शैख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुसलियार ने मनाया। ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पंडित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने निकाली पुरानी दुश्मनी, सरकारी वकील को पद से हटाया

वॉशिंगटन, (ईएमएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कुछ न कुछ करके चर्चा में बने हुए हैं। इस बार ट्रंप ने सरकारी न्याय विभाग में तैनात एक वकील को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया। उन्हें सिर्फ नोटिस ये दिया गया कि उन्हें राष्ट्रपति की विशेष शक्ति के तहत हटया जा रहा है। ट्रंप ने अपने ही देश के न्याय विभाग में काम करने वाली एक होनहार वकील को रातों रात नौकरी से निकाल दिया। इसके पीछे कोई तर्क भी नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मामूली वकील की राष्ट्रपति से क्या दुश्मनी? बता दें कि ये दुश्मनी ही है, जो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शक्तियाँ का इस्तेमाल करके मॉरीन कोमी को पद से हटा दिया।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वकील मॉरीन को बिना कोई कारण बताए हटा दिया। सूत्रों की मानें तो उन्हें एक भेमे मिली जिसमें राष्ट्रपति की कर्मचारियों को हटाने की शक्ति का जिक्र था। उनकी बर्खास्तगी को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप और उनके पिता को पुरानी दुश्मनी थी। वकील मॉरीन के पिता को साल 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प ने एफबीआई निदेशक पद से हटा दिया था। ट्रंप ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच में उनकी भूमिका को लेकर आलोचना की थी। ट्रंप ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी।

गाजा के फूड सेंटर पर भगदड़ और 43 की मौत हादसे के लिए इजराइली सेना और अमेरिका जिम्मेदार

गाजा, (ईएमएस)। गाजा के खान यूनि्स में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हुई भगदड़ में 43 लोगों की मौत हुई। इधमें से 21 लोग खाना लेने की कोशिश में मारे गए, जबकि 15 लोगों की मौत भगदड़ में कुचल कर हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हादसे के लिए इजराइली सेना और अमेरिका पर जानबूझकर भूखे लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) ने भी 20 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके लिए हमसा से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र इन जीएचएफ सेंटरों को मौत का जाल करार दे चुका है। मई के अंत से अब तक इन सेंटरों पर या आसपास 870 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।पिछले महीने, गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस (जीएमओ) ने इजराइली आर्मी पर फिलिस्तीनियों को ड्रस देने का आरोप लगाया था। जीएमओ का कहना था कि जीएचएफ द्वारा फिलिस्तीनी लोगों को दी गई आटे की बोरियों में ऑक्सीकोडोन नाम की नशीली गोशियां मिली हैं। जीएचएफ ने लोगों को नशे की लत लगाने की साजिश बताया था।गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में शुरू हुए युद्ध के बाद से इजराइली हमलों में गाजा के 58,573 लोग मारे गए हैं और 1,39,607 अन्य घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 94 लोगों की मौत हुई है और 252 घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता है, गाजा में हर 5 में से 1 व्यक्ति भुखमरी की चपेट में आ सकता है। जीएमओ ने दावा किया है कि गाजा का 70 प्रतिशत से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और 19 लाख लोग (85 प्रतिशत आबादी) अपने घरों से बेघर हो गए हैं।

अमेरिका 150 से अधिक देशों पर एक समान टैरिफ दर लागू करेगा: ट्रंप

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 से अधिक देशों पर यूनिफाइड टैरिफ रेट लागू करने की योजना बना रहे हैं। इन देशों को नई टैरिफ दरों की जानकारी के लिए पत्र भेजे जाएंगे। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, उस ग्रुप में सबके लिए सब कुछ एक जैसा ही होगा।रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में द्विपक्षीय समझौतों के दायरे में न आने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ लागू किया था। हालांकि, ट्रंप ने पहले 15 या 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन बुधवार को कोई नई दर तय नहीं की। अमेरिकी सरकार ने पहले ही लगभग दो दर्जन देशों, जिनमें यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, को पत्र भेज दिए हैं, जिनमें 1 आपस्त से लागू होने वाली टैरिफ दरों की जानकारी दी गई है। विश्लेषकों ने इस बात पर संदेह बताया है कि नई टैरिफ योजना 1 आपस्त से नियोजित रूप में लागू हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और फेरुल राजनीति पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। स्विटजरलैंड और भारत जैसे देश, जिन्हें अभी तक आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है, अभी भी वाशिंगटन के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं।

बलूच कार्यकर्ता के घर पाकिस्तानी सेना का छापा, परिवार को धमकाया

क्वेटा, (ईएमएस)। पाकिस्तान में मानवाधिकार संस्था बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की सदस्य सम्मी दीन बलूच के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बलूच कार्यकर्ता के घर पर बिना किसी कानूनी आधार के अवैध छापेमारी की। सम्मी ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान में बीवाईसी कार्यकर्ता साहिबा बलूच के घर में जबरन घुस गए। साहिबा ने पोस्ट में अपनी आपबीती बताकर कहा कि उनके पिता तनी महीने से गायब हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा अगवा किए जाने का आरोप है। साहिबा ने इस घटना को सामूहिक दंड के एक सोचे-समझे तरीके का हिस्सा बताया, जिसका उद्देश्य मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने वालों में डर और चुपची पैदा करना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से अपने पिता और अन्य गायब हुए सहयोगियों की तत्काल रिहाई की मांग करने और पाकिस्तान से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।इसी बीच, बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग ने पाकिस्तानी राज्य की मार डालो और फेंक दो नीति का जिक्र कर हिंसा की एक और घटना का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 13 जुलाई की रात को, बेज्जर बलूच के बेटे गुलाम जान को बलूचिस्तान के अवारन जिले में उनके घर से अगवा किया गया। कुछ घंटों बाद, गुलाम का गोलियों से छलनी शव प्रांत के कुली इलाके में मिला। इस कृत्य की कड़ी निंदा की गई है और इसके लिए पाकिस्तानी सेना तथा उसके छय मौत दर्स्तों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर सहित 20 सैनिकों की मौत

क्वेटा, (ईएमएस)। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर विद्रोहियों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर सहित 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। ये हमले बीते 12 घंटों में अवारन, क्वेटा और कलात जिलों में हुए। रिपोर्ट के अनुसार, ये हमले सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए गए थे। हालांकि, इन हमलों की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है, लेकिन इसमें फितना अल हिंदुस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के शामिल होने का शक है।वहीं, बलूचिस्तान के कालात में एक यात्री बस पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने क्वेटा-कराची हाईवे पर नेमागं इलाके में घात लगाकर बस को रोका और अंधाधुंध गोलीबारी की।बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिद ने बताया कि सुरक्षा बलों और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और हमलावरों की तलाश में अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने सड़क के दोनों ओर से हमला किया। मुख्यमंत्री मिर्जा सफरजाद बुगती ने इस हमले की निंदा की और इसे फितना अल हिंदुस्तान आतंकी संगठनों का काम बताया। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला गंभीर अपराध है। यह हमला उस दिन हुआ जब सुरक्षा बलों ने अवारन इलाके में फितना अल हिंदुस्तान से जुड़े तीन आतंकवादियों को मार गिराया।

ये संकट पूरे मिडिल ईस्ट को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है

दमिश्क, (ईएमएस)। ईरान से सीधा टकराव खत्म होते ही इजराइल ने मिडिल ईस्ट में नया युद्ध शुरू कर दिया है। इस बार सीधे सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया है। बीते 24 घंटे में इजराइल ने सीरिया में 250 से ज्यादा एयरस्ट्राइक की। 6 तो सिर्फ इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री और सिक्वोरिटी फोर्सेज के मुख्यालय पर की। दमिश्क का जनरल स्टायफ हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है और इजराइल ने लोखे तौर पर कहा है कि वह सीरिया की सीमाओं पर किसी भी सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेगा।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इजराइली पीपुप नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ आपात बैठक करने वाले हैं। जहां कई दिनों तक चलने वाले संभावित युद्ध की रणनीति तैयार की जाएगी,

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को और विस्फोटक बना रही है। सीरिया के अंदर दमिश्क के पास के डूज-बहुल इलाके जरामाना में लोगों ने सीरियाई झंडा उतारकर इजराइली झंडा लहरा दिया। इजराइल का दावा है कि उसके हमले डूज समुदाय की रक्षा के लिए थे और यह समुदाय अब खुलेकर इजराइल के समर्थन में सामने आ रहा है। जवाब में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने चेतावनी दी है कि इजराइली हमले वेस्ट एशिया की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं और लेबनान सीरिया के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। अब सवाल सिर्फ सीरिया-इजराइल का नहीं रहा...अब ये संकट पूरे मिडिल ईस्ट को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है।इलाक़ा दें सीरिया में रहने वाला डूज समुदाय जो देश का तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है, अब वह केंद्र में आ गया है। 2010 की जगणगण के मुताबिक डूज आबादी सीरिया की कुल जनसंख्या का करीब 3.2 फीसदी थी। यह

समुदाय मुख्य रूप से दमिश्क के पूर्व और दक्षिण के ग्रामीण, पहाड़ी इलाकों माउंट डूज क्षेत्र में केंद्रित है। डूज एक एकेश्वरवादी और अब्राहमिक धर्म है जिसकी धार्मिक परंपराएं अलग और गुप्त हैं। इजराइल ने दावा किया है कि दमिश्क और स्वेइदा में किया गया उसका हालिया हमला डूज समुदाय की रक्षा के लिए है, जो वहां सीरियाई सेना और अन्य सशस्त्र गुटों के बीच जारी टकरावों में फंस गया है।इजराइली डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम डूज की हत्या नहीं होने देंगे और अपनी सीमाओं के पास सैन्य जमावड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है जिस कारण इजराइल और सीरिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। नहीं, यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद भी एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। इजराइल ने पहले कई बार दावा किया कि ईरान, सीरिया में अपने लड़ाके और हथियार जमा कर रहे हैं, जिससे

इजराइल की सीमा खतरे में है।बता दें इजराइल और सीरिया की दुश्मनी की शुरुआत 1967 के सिक्स डे वॉर से हुई, जब इजराइल ने सीरिया से गोलैन हाइट्स का कब्जा कर लिया। ये केंद्राई पर बसा रणनीतिक इलाका आज भी इजराइल के कब्जे में है और सीरिया उसे अपना मानता है। इस पर संघर्ष 1973 की यौम किप्पूर वॉर तक चला, जिसमें सीरिया फिर से गोलैन हाइट्स पाने में कामयाब।इजराइल ने 1981 में 'गोलैन हाइट्स लॉ' पास कर इस इलाके को आधिकारिक रूप से खुद में मिला लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे अवैध करार दिया और बिना कानूनी मान्यता बताया। इसके बावजूद इजराइल ने वहाँ से पीछे नहीं हटा। इजराइल और सीरिया के बीच 2000 में एक समझौता करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन दोनों पक्षों की असहमति और अविश्वास की दीवार इतनी मजबूत थी कि बात बनने से पहले ही टूट गई। फिर 2011 में शुरू हुई सीरिया की गृहयुद्ध ने इस दुश्मनी

को और गहरा कर दिया। सीरिया सरकार का समर्थन करने के लिए ईरान सामने आया जो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों और हथियार डिपो पर हमले शुरू कर दिए। हाल में हुए इजराइल-ईरान युद्ध हुआ।इस बार हमला करने का इजराइल ने डूज समुदाय की सुरक्षा का हवाला दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीएम नेतन्याहू और उन्होंने मिलकर दावा किया है कि वे 'सीरियन डूज की हिफाजत करेंगे', लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल सैन्य कार्रवाई को नैतिक जाया पहनाने की कोशिश है। इस समय हालात संवेदनशील हैं। इजराइल सीधी कार्रवाई कर रहा है और सीरिया में सरकार, ईरान समर्थित लड़ाके और कई चरमपंथी गुट सक्रिय हो गए हैं। इस बार लड़ाई सीमित नहीं लग रही और अगर हालात नहीं संभाले तो आने वाला हफ्ता पश्चिम एशिया में बड़ी उथल-पुथल ला सकता है।

अल्पमत में आ गई नेतन्याहू की सरकार दो दलों ने समर्थन वापस लिया

तेलअवीव (ईएमएस)। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। अति-रूढ़िवादी शास पार्टी ने नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापस देने का ऐलान कर दिया। इससे एक दिन पहले यूनाटेड टोरा जूडाइज्म (यूटीजे) पार्टी भी इस सरकार से अलग हुई थी।इजराइल की 120 सीटों वाली संसद (नेसेट-निचला सदन) में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। इन दोनों पार्टियों के अलग होने से सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सिर्फ 50 सीटें शेष बची हैं। शास पार्टी ने गठबंधन छोड़ने के मुद्दे पर कहा कि भारी मन से हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि हम नेतन्याहू सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। हालांकि, हम इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे और कुछ कानूनों पर गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं।दरअसल

विवाद की मुख्य वजह रूढ़िवादी धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस से मिलने वाली छूट है। ये छात्र लंबे समय से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस से छूट ले रहे हैं। नेतन्याहू सरकार ने हाल ही में इस छूट को सीमित करने के लिए एक बिल लेकर आई थी, जिसकी वजह शास पार्टी और यूटीजे ने सरकार से अलग होने का फैसला किया। दोनों पार्टियों का कहना है कि धार्मिक छात्रों के सेना में भर्ती होने से उनकी धार्मिक जीवनशैली को खतरा होगा। हालांकि, कई अन्य यहूदी इजराइली इस स्पेशल सुविधा का समर्थन करते हैं। शास पार्टी ने गठबंधन छोड़ने के मुद्दे पर कहा कि भारी मन से हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि हम नेतन्याहू सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। हालांकि, हम इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं कर रहे और कुछ कानूनों पर गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं।दरअसल

रहे हैं। जानकारी का कहना है कि यह गठबंधन विवाद तुरंत नेतन्याहू की सरकार नहीं गिराएगा। हालांकि, यह इजराइल की राजनीति में और अस्थिरता लाएगा, खासकर जब गाजा में युद्धविराम और लेबनान व सीरिया में चल रहे संघर्ष को लेकर नेता आपस में टकरा रहे हैं।

अब तक 800 से ज्यादा इजराइली सैनिकों की मौत

इजराइल और हमसा के बीच युद्ध को जल्द ही तीन साल पूरे होने वाले हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 888 इजराइली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में शुरू हुए युद्ध के बाद से इजराइली हमलों में गाजा के 58,573 लोग मारे गए हैं और 1,39,607 अन्य घायल हुए हैं।

अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का आया जोरदार भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

वॉशिंगटन, (ईएमएस)। अमेरिकी राज्य अलास्का में जोरदार भूकंप आया है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 है, जो कि काफी खतरनाक है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने इसकी जानकारी दी है। भूकंप के बाद अलास्का के लोगों पर एक और खतरा मंडरा रहा है। भयावह भूकंप के कारण अब पूरे इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप हटाना तेज था कि धरती डोलने लगी। लोग थर-थर कांपने लगे और घरों से बाहर निकल सड़क की ओर भागने लगे।यूएसजीएस यानी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, बुधवार को अमेरिकी राज्य अलास्का के तट पर दोहहर 12 बजकर 37 मिनट पर (लोकल टाइम) 7.3 तीव्रता का भूकंप

आया। इस भूकंप का केंद्र द्वीपीय शहर सैंड पॉइंट से करीब 87 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। भूकंप का केंद्र अपेक्षाकृत कम गहराई पर 20.1 किलोमीटर की गहराई पर था। अलास्का की जनसंख्या करीब 7.5 लाख है। ऐसे में इन लोगों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है।बता दें इससे पहले मार्च 1964 में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जो उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसने एंकोरेज शहर को तबाह कर दिया और एक सुनामी भी दी जिसने अलास्का की खाड़ी, अमेरिका के पश्चिमी तट और हवाई को तबाह कर दिया था। फिलहाल, मौजूदा 7.3 तीव्रता वाले भूकंप से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है।भूकंप के बाद दक्षिण अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप

के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का स्थित राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र पामर ने कहा कि भूकंप के बाद अब सुनामी की पुष्टि हो गई है और इसके कुछ प्रभाव भी पड़ने की आशंका है। बहरहाल, भूकंप से अब तक कितनी तबाही हुई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। केंद्र ने कहा कि सुनामी की यह चेतावनी दक्षिण अलास्का और अलास्का प्रायद्वीप, कैनेडी एंट्रेस, अलास्का (होमर से 40 मील दक्षिण-पश्चिम) से लेकर यूनिमक पास, अलास्का (उनालास्का से 80 मील उत्तर-पूर्व) तक प्रशांत तटों) के लिए जारी की गई है। दरअसल, अलास्का भूकंपीय रूप से काफी सक्रिय इलाका है। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो भूकंप के कारण लोगों में दहशत का माहौल है।

मानसा के युवक की कनाडा में डूबने से मौत

आटोबा (ईएमएस)। मानसा के युवक की कनाडा में डूबने से मौत हो गई। वह पढ़ाई करने विदेश गया था। नदी में वॉलीबॉल गिरने पर युवक ने छलांग लगा दी और डूब गया। परिवार युवक के पार्थिव शरीर को भारत लाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम संस्कार मानसा में होगा।जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय छात्र जितन गुर्र कनाडा की थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया था। जितन अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे वॉलीबॉल खेल रहा था। तभी वॉलीबॉल नदी में गिर गई। जितन ने गेंद को निकालने के कोशिश की, लेकिन इस दौरान वह खुद भी नदी में डूब गया। जितन आपस्त 2024 में मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कनाडा गया था।मुक्त के चाचा भूषण गुर्र ने बताया कि जितन के पिता कुछ समय पहले बिजनेस के सिलसिले में चंडीगढ़ रिफ्ट हो गए थे। वर्तमान में पूरा परिवार चंडीगढ़ में रह रहा है। परिवार जितन के पार्थिव शरीर को भारत लाने का प्रयास कर रहा है। अंतिम संस्कार मानसा में किया जाएगा।

इराक के मॉल में लगी भीषण आग, 60 लोगों की मौत

बगदाद, (ईएमएस)। इराक के वासित के अल-कुत शहर में एक मॉल में बुधवार देर रात आग लग गई। इस घटना में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मॉल की एक विशाल इमारत का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है। वहां घना धुआं उठ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने में कई घंटे लागे।रिपोर्ट में बताया कि अब तक 59 शवों की पहचान कर ली है, लेकिन एक शव इतना बुरी तरह जला है कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो रही है। अभी और शवों की इमारत में होने की आशंका जताई जा रही है। आग का कारण अज्ञात है। वासित प्रांत के गवर्नर ने बताया कि इमारत और मॉल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन ने कहा है कि इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जा रही है।



लिए विशिष्ट कदमों पर सहमत हो गए हैं। इससे भयावह स्थिति का अंत हो जाएगा। इसके लिए सभी पक्षों की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा और हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दमिश्क पर इजराइली एयरस्ट्राइक के बाद अहमद अल-शरा ने डूज नागरिकों से कहा था कि हम आपको किसी बाहरी पक्ष के हाथों में सौंपने के किसी

भी प्रयास का विरोध करते हैं। उन्होंने इजराइल पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उन लोगों में से नहीं, जो युद्ध से डरते हैं। हमने अपना जीवन चुनौतियों का सामना करने और अपने लोगों की रक्षा करने में बिताया है, लेकिन हमने सीरिया के लोगों के हितों को अराजकता और निनाश से ऊपर रखा है।अल-शरा ने कहा कि इजराइल हमारी जमीन को अराजकता

कोयलांचल संवाद



ओलंपिक में भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें स्वर्ण पर रहेंगी

लॉस एंजिल्स (ईएमएस)। अगामी 2028 लॉस एंजिल्स में भारतीय टीम क्रिकेट में स्वर्ण पदक की सबसे बड़ी दावेदार होगी। भारतीय टीम एशियाई खेलों की विजेता है और अब उसका लक्ष्य ओलंपिक में भी जीत दर्ज करना रहेगा। ओलंपिक में क्रिकेट की 128 साल के बाद वापसी हो रही है। जिससे आईसीसी सहित पूरा क्रिकेट जगत उत्साहित है। आईसीसी का मानना है ओलंपिक में शामिल होने से दुनिया भर में क्रिकेट का प्रचार-प्रसार होगा।

बहरहाल ओलंपिक में होने वाले क्रिकेट मुकाबले लॉस एंजिल्स से लगभग 50 किलोमीटर दूर पोमेना शहर के फेयरग्राउंड्स स्टेडियम में 12 जुलाई को शुरू होंगे। ओलंपिक में क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 प्रारूप में ही मैच होंगे। इसमें पदक मैच 20 और 29 जुलाई, 2028 को खेले जाएंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में कुल छह-छह टीमें और 180 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के कार्यक्रम के अनुसार अधिकतर दिन दो मैच खेले जाएंगे जबकि 14 और 21 जुलाई को कोई मैच नहीं खेला जाएगा।

ओलंपिक में इससे पहले केवल एक बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था, उसमें तब केवल दो टीमें ब्रिटेन और फ्रांस ही शामिल हुई थी। तब ब्रिटेन ने प्रतियोगिता के एकमात्र मैच में जीत हासिल करके स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष और महिला वर्ग में कुल 90 खिलाड़ियों का कोटा आवंटित होने के कारण 12 प्रतिस्पर्धी टीमें 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर सकती हैं।

टीम में बुमराह की मौजूदगी पर डेविड लॉयड ने उठाए अहम सवाल



लंदन (ईएमएस)। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रनों की हार के बाद भारतीय खेमे में निराशा का माहौल है। खासतौर पर जसप्रीत बुमराह को लेकर एक दिलचस्प चर्चा छिड़ गई है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेविड लॉयड ने बुमराह की मौजूदगी और टीम के प्रदर्शन के बीच के फर्क को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बुमराह को इंग्लैंड में सबसे बड़ा मैच विवर माना जा रहा था, लेकिन मौजूदा सीरीज में उन्होंने दो टेस्ट खेले (लीड्स और लॉर्ड्स) और दोनों में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं, जिस बर्मिंघम टेस्ट में बुमराह नहीं खेले, उसमें भारत को जीत मिली। डेविड लॉयड ने एक बातचीत में कहा, “यह असाधारण आंकड़ा है। कहा जाता है कि जब वह खेलते हैं तो भारत ज्यादा हारता है और जब नहीं खेलते तो ज्यादा मैच जीतता है। वह दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन ये संयोग अब चर्चा का विषय बन गया है।” बर्मिंघम टेस्ट में बुमराह को आराम दिया गया था और उस मुकाबले में मोहम्मद सिराज व आकाश दीप की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीत दर्ज की थी। सिराज और आकाश दीप ने मिलकर उस मैच में 16 विकेट झटके थे।

इससे पहले भारतीय चयन समिति और कोच गौतम गंभीर ने यह स्पष्ट किया था कि बुमराह को पांच में से केवल तीन टेस्ट में खिलाया जाएगा। अब जबकि वह दो मैच खेल चुके हैं और सीरीज 1-2 के स्कोर पर है, डेविड लॉयड का मानना है कि चौथा टेस्ट निर्णायक होगा। उन्होंने कहा, “अगर भारत को सीरीज बराबर करनी है तो बुमराह को ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में उतरना होगा। अगर भारत 2-2 कर देता है, तो फिर शायद वह ओवल टेस्ट में भी खेलें।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इंग्लैंड चौथा मैच जीतकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेता है, तो भारत बुमराह को अंतिम टेस्ट से आराम दे सकता है। लेकिन यदि स्कोर 2-2 हो जाता है, तो टीम प्रबंधन उन्हें ओवल टेस्ट में जरूर उतारने पर विचार करेंगे।

हालांकि डेविड लॉयड ने यह भी माना कि बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं और उनका एक्शन दुनिया में सबसे अनोखा है। बावजूद इसके, उनके खेलने और टीम के नतीजों के बीच बनता यह आंकड़ों का रिसता अब विश्लेषण और रणनीति का हिस्सा बन गया है।



गुरुवार को रॉयल पोर्टरश गोल्फ क्लब, पोर्टरश उत्तरी आयरलैंड में 153वीं ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में आयरलैंड के पैट्रैक हेरिंगटन पहले राउंड के पहले होल पर अपना टी शॉट लगाते हुए।

तीनों प्रारूपों में 900+ आईसीसी रेटिंग अंक पाने वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली

नई दिल्ली (ईएमएस)। भले ही विराट कोहली ने टी20 और हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कोहली की टी20 अंतरराष्ट्रीय रेटिंग को बढ़ाकर 909 अंक कर दिया है, जिससे वह खेल के इतिहास में तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी201 में 900 या उससे अधिक आईसीसी रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने पिछले साल टी20 विश्व कप के फाइनल में 76 रनों की अहम पारी खेली थी, जिससे भारत को खिताबी जीत मिली। उसी प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी ने उनकी सर्वकालिक टी20आई रेटिंग को 897 से बढ़ाकर 909 कर दिया है। यह टी20आई इतिहास में तीसरा सबसे ऊंचा स्कोर है, उनसे आगे केवल सूर्यकुमार यादव (912) और इंग्लैंड के डेविड मलान (919) हैं। टेस्ट रैंकिंग में विराट का सर्वश्रेष्ठ रेटिंग स्कोर 937 रहा, जो उन्होंने 2018 में इंग्लैंड दौर के दौरान हासिल किया था। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज का अब तक का सर्वोच्च टेस्ट रेटिंग स्कोर है और विश्व स्तर पर 11वां। उस दौर पर उन्होंने 10 पारियों में 593 रन बनाए थे। वहीं, वनडे में 2018 में ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान उन्होंने 909 रेटिंग अंक तक पहुंचते हुए सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा छुआ था।

विराट कोहली को एक समय तीनों प्रारूपों में आईसीसी रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज रहने का गौरव प्राप्त है। इस नई उपलब्धि के साथ उन्होंने खुद को सर्वकालिक महान ऑल-फॉर्मेट बल्लेबाजों में एक मजबूत दावेदार के रूप में फिर से स्थापित कर दिया है। उन्होंने टी20आई में 125 मैचों में 48.61 की औसत से 4,188 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में उन्होंने 9,230 रन बनाए, जिनमें 30 शतक और 31 अर्धशतक हैं, और वह भारत के चौथे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वनडे में वह अब तक के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है। अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली ने कुल 27,599 रन बनाए हैं जिसमें 82 शतक और 143 अर्धशतक शामिल हैं। वह भारत के दूसरे और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से हराया, दीप्ति शर्मा रहीं हीरो

साउथैम्पटन (ईएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत की है। साउथैम्पटन में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 259 रनों का स्कोर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत की नायिका रहीं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने मुश्किल समय में संयम भरी बल्लेबाजी करते हुए 62 रनों की अहम पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बनीं।मैच की शुरुआत इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करके की, लेकिन टीम को शुरुआत में झटका लगा जब 20 रन तक पहुंचते-पहुंचते दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद सोफिया डंकली ने 92 गेंदों पर 83 रन की शानदार पारी खेली। डेविडसन रिचर्ड्स ने 53 रन



जोड़े, जबकि कप्तान साइवर ब्रंट ने 41 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 258 रन बनाए।

27 रन पर ढेर हुई वेस्टइंडीज तो आईपीएल जैसे लीग और क्रिकेट सिस्टम पर उठे सवाल

सबीना पार्क (ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 27 रन पर सिमटने के बाद क्रिकेट जगत में मची हड़कंप थमने का नाम नहीं ले रही है। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे छोटी पारी बन गई है। जमेका के सबीना पार्क में खेले गए डे-नाइट मुकाबले में महज 87 गेंदों के भीतर वेस्टइंडीज की पूरी टीम पवेलियन लौट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। इस शर्मनाक हार के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट की गिरती स्थिति को लेकर बहस तेज हो गई है और दिग्गज खिलाड़ियों ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी है। वेस्टइंडीज के पूर्व महान बल्लेबाज



ब्रायन लारा ने ‘रिस्टक टू क्रिकेट’ पॉडकास्ट में टीम के पतन की वजहों पर बात करते हुए इशारों में इंडियन प्रीमियर लीग और अन्य फ्रेंचाइजी टी20 लीग्स को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पहले खिलाड़ी वेस्टइंडीज टीम में जगह पाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, फर्स्ट क्लास

क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय टीम को केवल एक सीढ़ी माना जा रहा है जिससे खिलाड़ी टी20 लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकें। लारा ने यह भी कहा कि इसके लिए केवल खिलाड़ियों को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्रिकेट का पूरा सिस्टम ही इस दिशा

में ढल गया है।

वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड लॉयड ने इस मुद्दे पर एक और गंभीर पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रख लेते हैं, जिससे वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमों पीछे छूट जाती हैं। उनके अनुसार, ब्रॉडकास्ट डील और संसाधनों का असमान वितरण वैश्विक क्रिकेट में असंतुलन पैदा कर रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट इस समय सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि वित्तीय और संरचनात्मक स्तर पर भी संघर्ष कर रहा है। 27 रन की यह पारी सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि उस सिस्टम का आईना है, जो छोटे क्रिकेट देशों को पीछे छोड़ता जा रहा है।

जडेजा इंग्लैंड में 1000 रन बनाने के करीब पहुंचे

लंदन (ईएमएस)। भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए एक और कीर्तिमान के करीब पहुंचे हैं। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 61 रन बनाए, हालांकि भारत यह मुकाबला 22 रन से हार गया। यह जडेजा का इंग्लैंड में लगातार चौथा अर्धशतक था, जिसमें बर्मिंघम और लॉर्ड्स दोनों में जुड़वां फिफ्टी शामिल हैं। इस तरह वे सौरभ गांगुली और ऋषभ पंत के क्लब में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड में लगातार चार बार 50+ स्कोर बनाए थे।

लॉर्ड्स टेस्ट की चौथी पारी में यह जडेजा का पहला अर्धशतक रहा। इंग्लैंड में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अब

वेस्टइंडीज-पाकिस्तान मैच फॉर्मेट को लेकर नहीं बनी सहमति

नई दिल्ली (ईएमएस)। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच अगस्त में प्रस्तावित क्रिकेट सीरीज को लेकर दोनों देशों के बोर्डों में असहमति का माहौल बन गया है। 1 से 12 अगस्त तक अमेरिका और कैरेबियाई द्वीपों में दोनों टीमों को तीन-तीन टी20 और वनडे मैच खेलने हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि यह पूरी सीरीज केवल टी20 प्रारूप में खेरी जाए। इसके विपरीत वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहा और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी मैच कराने पर अड़ा है।

पाकिस्तान का तर्क है कि अगले साल भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व कप होना है, ऐसे में टीम को ज्यादा से ज्यादा टी20 मैच खेलने चाहिए ताकि तैयारी पुख्ता की जा सके। इसी कारण पीसीबी वनडे सीरीज को भी टी20 सीरीज में बदलने का आग्रह कर रहा है। लेकिन वेस्टइंडीज की स्थिति अलग है। पिछली बार जब भारत में वनडे विश्व कप खेला गया था, तो वेस्टइंडीज की टीम उसमें जगह नहीं बना पाई थी। इसी वजह से वह 50 ओवर के मुकाबलों को लेकर गंभीर है और इस फॉर्मेट में ज्यादा मैच खेलना चाहता है।

इस विवाद पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के सीईओ क्रिस डेहरिंग ने कहा कि फिलहाल शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है और



पीसीबी से बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान सिंगपुर में और चर्चा होगी। वेस्टइंडीज बोर्ड इस बात को लेकर आश्वस्त है कि त्रिनिदाद में खेले जाने वाले मैच वनडे ही होंगे और किसी बदलाव की संभावना कम है। मौजूदा कार्यक्रम के

अनुसार, 1, 2 और 4 अगस्त को अमेरिका के फ्लोरिडा में तीन टी20 मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 8, 10 और 12 अगस्त को त्रिनिदाद के तारोबा में तीन वनडे मैच होंगे। दोनों बोर्डों के बीच इस फॉर्मेट विवाद का हल सिंगपुर में होने वाली बातचीत के बाद ही निकलने की उम्मीद है।

पंत एक बेहद रोमांचक खिलाड़ी हैं, जिनका खेल दर्शकों को बांधे रखता हैं : जैक रसेल

ऋषभ की विकेटकीपिंग तकनीक में कुछ सुधार की जरूरत

लंदन (ईएमएस)। इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जैक रसेल ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि पंत एक बेहद रोमांचक खिलाड़ी हैं, जिनका खेल दर्शकों को बांधे रखता है, लेकिन उनकी विकेटकीपिंग तकनीक में कुछ सुधार की जरूरत है। रसेल का कहना है कि पंत चाहे बल्लेबाजी कर रहे हों या विकेट के पीछे खड़े हों, उन्हें देखना हमेशा मनोरंजक होता है। वह इस बात से भी बेहद खुश है कि भयानक बल्लेबाज के बाद पंत ने मैदान पर सफल वापसी की है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि पंत की विकेटकीपिंग में कुछ तकनीकी कमजोरियाँ हैं, जिन पर उन्हें काम करना होगा, विशेष रूप से स्टंप के पास खड़े होकर कीपिंग



करते समय।

61 वर्षीय रसेल ने बताया कि वह खुद एलन नॉट और बॉब टेलर जैसे कीपरीं को आदर्श मानते थे, लेकिन भारतीय विकेटकीपर सैयद किरमानी को देखकर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि जब वह छोटे थे, तब किरमानी को देखकर लगता था कि वे बेहतरीन विकेटकीपर हैं। मौजूदा दौर के कीपरों पर बात करते हुए रसेल ने इंग्लैंड के जैमी स्मिथ की भी तारीफ की और उन्हें भविष्य का महान

विकेटकीपर बताया। उनके अनुसार, स्मिथ में इतनी प्रतिभा है कि उन्हें एडम गिलक्रिस्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। रसेल ने यह भी कहा कि विकेटकीपिंग में गलतियाँ होना सामान्य है, क्योंकि ज्यादातर विकेटकीपर उनसे नहीं बच पाते। खासकर इंग्लैंड जैसी परिस्थितियों में विकेट कीपिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पंत की तकनीकी गलतियों को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी खामियां नहीं हैं, बल्कि कुछ छोटी बातें हैं जिन्हें सुधारकर वह और बेहतर हो सकते हैं। अगर पंत चाहें, तो वह उन्हें इन तकनीकी पहलुओं पर सलाह भी दे सकते हैं। क्रिकेट से संन्यास के बाद रसेल अब चित्रकला से जुड़े हुए हैं। वह रोजाना पेंटिंग करते हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें साझा भी करते हैं, जिनमें उनके अधिकतर फॉलोअर्स भारतीय हैं। हाल ही में उन्होंने भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीतसिंहजी का चित्र बनाया, जिसे

हेटमायर का तूफान

एक ओवर में लगाए 5 छक्के



नई दिल्ली (ईएमएस)। ग्लोबल सुपर लीग 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में शिमरन हेटमायर ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि मैच का रुख ही बदल गया। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुयाना ऐमर्जॉन वॉरियर्स ने होबार्ट हरिकेंस को हराकर फाइनल में जगह बना ली। हेटमायर ने 10 गेंदों में 39 रन की विस्फोटक पारी खेली और एक ओवर में 5 छक्के लगाकर सभी को हैरान कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए होबार्ट की टीम 16.1 ओवर में महज 125 रन पर सिमट गई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुयाना की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही और 9 ओवर में उसका स्कोर 43/3 था। सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में जब 72 गेंदों में 82 रन चाहिए हों, तो दबाव साफ दिखता है, लेकिन हेटमायर के इरादे कुछ और थे। वो 10वें ओवर की शुरुआत में बल्लेबाजी के लिए आए और फैबियन एलेन के ओवर में ही मैच पलट दिया। हेटमायर ने पहली गेंद को लॉग ऑन के ऊपर से सिक्स के लिए भेजा। दूसरी गेंद पर ओडीन स्मिथ ने उनका कैच छोड़ा, और गेंद बाउंड्री पर जा गिरी। अगली दो गेंदों पर उन्होंने लगातार दो और छक्के जड़े। पांचवीं गेंद पर उन्होंने दो रन लिए और फिर आखिरी गेंद को भी छक्के में बदल दिया। इस तरह एलेन के एक ओवर में 32 रन आए, जिसमें हेटमायर ने 5 सिक्स जड़े। उनकी इस धमाकेदार पारी में कुल 6 छक्के शामिल थे। हालांकि उन्हें उसामा मीर ने आउट किया, लेकिन तब तक मैच गुयाना के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका था।

गुयाना ऐमर्जॉन वॉरियर्स ने 17वें ओवर में ही 4 विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और फाइनल में प्रवेश किया। अब 18 जुलाई को फाइनल में उसका मुकाबला रंगपुर राइडर्स से होगा। हेटमायर की यह विस्फोटक बल्लेबाजी क्रिकेट प्रेमियों के लिए लंबे समय तक यादगार बनी रहेगी, खासकर जिस अंदाज में उन्होंने एक ओवर में पांच छक्के जड़कर मैच का रुख पलटा, वह लाजवाब था।



क्रांति गौड़ बुमराह की तरह फेंकती हैं इनस्विंगर

साउथैम्पटन (ईएमएस)।

रोज बायल में खेले गए पहले एकदिवसीय मुकाबले में 21 वर्षीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने अपने करियर के सिर्फ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन क्रांति ने अपने शुरुआती स्पेल में ही ही इंग्लिश टीम को झटके देना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 ओवर में 28 रन देकर दो महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिनमें अनुभवी एमी जोन्स और खतरनाक टेमी ब्यूमोंट शामिल थीं। क्रांति को टीम इंडिया की ओर से अमनजोत कौर के बाद नई गेंद सौंपी गई। शुरुआत में वह थोड़ा अस्थिर नजर आई और तीन वाइड गेंदें फेंकी, लेकिन जल्द ही उन्होंने लय पकड़ ली। उन्होंने एमी जोन्स को महज एक रन पर बोल्ड किया, जो उनका वनडे करियर का पहला विकेट बना। उनकी इनस्विंग डिलीवरी ने जोन्स के स्टंप उखाड़ दिए और बल्लेबाज को खेलने का कोई मौका नहीं मिला। क्रांति यहीं नहीं रुकीं। अपने अगले ओवर में उन्होंने टेमी ब्यूमोंट जैसे अनुभवी बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर ब्यूमोंट के पैड पर गेंद लगी, जिसे ऑन-फिल्ड अंपायर ने सही दिया। लेकिन भारत ने डीआरएस लिया और रीले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप पर लगती। ब्यूमोंट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुईं। यह विकेट भारत के लिए निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि ब्यूमोंट महिला वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाली खिलाड़ी हैं। क्रांति गौड़ महिला प्रीमियर लीग 2025 के दौरान सुर्खियों में आई थीं, जब यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 10 लाख रुपये में खरीदा था। उन्होंने उस सीजन में 8 मैचों में 6 विकेट लिए और अपनी गति व आक्रामकता से प्रभावित किया। विशेष रूप से बेंगलुरु में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उसी प्रदर्शन के बाद उन्हें श्रीलंका में त्रिकोणीय वनडे सीरीज में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और अब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

जैक क्रॉउली के टीम से बाहर जाने का समय आ गया : जेफ्री बाँयकॉट भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रोमांच जारी

लंदन (ईएमएस)। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का रोमांच चरम पर है। शुरुआती तीनों टेस्ट मुकाबले पूरे पांच दिन तक चले, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को टेस्ट क्रिकेट का भरपूर आनंद मिला। मजेबान इंग्लैंड ने पहला और तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है, जबकि भारत ने दूसरा टेस्ट अपने नाम किया था। तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला गया और बेहद करीबी रहा, जिसमें भारत महज 22 रन से हार गया। हालांकि इंग्लैंड की जीत के बावजूद टीम के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉउली के खराब प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो गए हैं। मौजूदा सीरीज में क्रॉउली का औसत केवल 21.33 रहा है और तीन मैचों में उन्होंने कुल 128 रन ही बनाए हैं। पहले टेस्ट में हेडिले में उन्होंने 65 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनके स्कोर 19, 0, 18 और 22 ही रहे। उनके लगातार कमजोर प्रदर्शन को लेकर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सर जेफ्री बाँयकॉट ने उन्हें टीम से बाहर करने की मांग की है। बाँयकॉट ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्रॉउली ने 57 टेस्ट खेलने के बावजूद कुछ नहीं सीखा है और वे बार-बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। बाँयकॉट ने यह भी जोड़ा कि विपक्षी गेंदबाज उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाली विंड एंशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क, हेजलवुड और कर्मिस जैसे तेज गेंदबाज उन्हें आसानी से आउट करेंगे। जैक क्रॉउली ने 2019 में इंग्लैंड से लिपटे टेस्ट डेब्यू किया था और अब तक 57 मैचों में 30.89 की औसत से 3151 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। इसके बावजूद हालिया फॉर्म ने टीम में उनकी जगह पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।



जकार्ता, इंडोनेशिया, में पुरुष एसईए वॉलीबॉल लीग के दूसरे चरण में इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच मैच के दौरान स्याइम्स लगाते इंडोनेशिया के अर्नेज अरबी (बाएं)।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से रुपये की ठगी करने वाले साइबर ठगों के विरुद्ध जागरूकता

धनबाद, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद को ज्ञात हुआ है कि साइबर ठगों द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से लाखों रुपये की ठगी की जा रही है । वर्तमान में साइबर ठगों द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से रुपये की ठगी के कुछ मामले सामने आये हैं। जिसमें स्वयं को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद के अधिकारी या कर्मचारी बताकर संपर्क करते हैं तथा पेंशन शीघ्र दिलाने का वादा, पेंशन बंद होने की सूचना, बैंक, पेंशन संबंधी दस्तावेजों की तत्काल आवश्यकता का झांसा एवं अन्य भ्रम फैलाकर ओ.टी.पी या बैंक जानकारी प्राप्त करके ठगी की गयी है । सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, धनबाद के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के निजी फोन अथवा मोबाइल नंबर पर बैंक खाता, ओ.टी.पी, पेंशन संख्या, आधार नंबर या कोई भी संवेदनशील जानकारी नहीं मांगी जाती है । धनबाद रेल मंडल प्रबंधक द्वारा सलाह दी जाती है कि बैंक और पेंशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी और दस्तावेज फोन, मोबाइल पर किसी के साथ साझा न करें। ताकि साइबर ठगों के जाल से बचा जा सके। उक्त जानकारी हिंदी दैनिक अखबार के आर एन चौरसिया को मोहम्मद इकबाल वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक, धनबाद एवं वरीय जनसंपर्क अधिकारी ने दी।

लोयाबाद में दुर्गा पूजा और काली पूजा को लेकर एक बैठक का आयोजन



लोयाबाद। लोयाबाद सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक मे बीसीसीएल के प्रति नाराजगी जाहिर की गई। लोयाबाद में दुर्गा पूजा और काली पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन लोयाबाद कोलियरी कार्यालय के परिसर में गुरुवार को किया गया। जिसमें बीसीसीएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों समेत लोयाबाद के विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता लोयाबाद कोलियरी प्रबंधक अभिषेक कुमार, संचालन सुनील पांडे ने किया। बैठक में सर्वप्रथम दुर्गा पूजा समिति के सचिव वीरेंद्र पासवान ने पिछले साल का अमद एवं खर्च का ब्यूरो दिए।तभी बैठक में आये हुये श्रद्धालुओं ने इस वर्ष के लिए पुरानी कमेटी को ही पूजा संपन्न कराने की जिम्मेवारी दिया। जिसके पश्चात कर्मचारियों ने सर्व सम्प्ति से इस बार दुर्गा पूजा में सहयोग राशि 1200 रुपया देने पर अपने सहमति जताए। कमेटी द्वारा मूर्ति विसर्जन के दरम्यान विशेष सक्तता बरतने का अपील की गई। साथ ही सभी लोगों ने पूजा के दौरान उत्पन्न समस्याओं को लेकर गहन विचार विमर्श किया।जिसमें लोयाबाद तीन नंबर स्थित माँ काली मंदिर का गुंबज की प्ररम्ती को लेकर विशेष रूप से चर्चा तथा अन्य बिंदुओं पर भी शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब राष्ट्रीयकरण के समय सारी सम्प्ति कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया तो क्षेत्र के दुर्गा मंदिर,काली मंदीर व ठाकुरबाड़ी का मरम्पति कार्य क्यू बंद कर दिया गया। कुछ वर्षों से बीसीसीएल कम्पनी मंदिर का रख रखाव संबंधी कार्यों पर रोक लगाया है। अंत में द्वितीय रविवार को संस्था चार बजे लोयाबाद दुर्गा मंदिर के प्रांगण में माँ दुर्गा की पूजा को सफल बनाने को लेकर एक बैठक पुनः रखत का निर्णय लिया गया। इस बैठक के मौके पर मुख्य रूप से लोयाबाद कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक प्रमोद सिंह, लोयाबाद कोलियरी के अभियंता तरुण कुमार,जयप्रकाश पांडेय,सोहन महतो,रवि चौबे,सियाही चौहान,अनवर मुखिया,कलीम अंसारी, सोमन घोष,बिनोद पासवान,राजेन्द्र पासवान, शंकर केशरी,धर्मेन्द्र पांडेय,एसएस प्रमल,विरेंद्र शर्मा,राणा प्रताप चौहान,पुतुल झा,सुरेश यादव,प्रदीप गुप्ता, गणेश साव,रंजीत साहनी,उज्जवल नायक,बिट्टू सिंह, रवि चौहान, महावीर चौहान,मुकेश पासवान,राजेंद्र राम,सहित दर्जनाधिक लोग मौजूद थे।

कनकनी कोलियरी के पी.ओ. व आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक पर आरोप मदनाडीह निवासी रैयत दिलीप कुमार, निजी सीएनटी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध कोयला उत्खनन कराने का आरोप

लोयाबाद।मदनाडीह निवासी रैयत दिलीप कुमार ने कनकनी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल जी एवं आउटसोर्सिंग कंपनी रामअवतार के प्रतिनिधि आदित्य सिंह पर निजी सीएनटी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध कोयला उत्खनन कराने का गंभीर आरोप लगाया है।इस संबंध में उन्होंने धनबाद उपायुक्त को एक लिखित पत्र सौंपा है।जिसकी प्रतियां कोयला मंत्री,बीसीसीएल के सीएमडी,एसएसपी,एसडीओ,सीओ पुटकी, लोयाबाद थाना व डुमरी विधायक जयराम महतो को भी प्रेषित की गई है।शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बताया है कि सेन्द्रा मौजा खाता संख्या 70, खेसरा संख्या 12 के तहत भूजल 1.46 एकड़ भूमि उनके परदादा स्व. भोजू रवानी के नाम पर दर्ज है, जिसका वे 2016 तक नियमित लगान भी अदा करते रहे हैं।दिलीप कुमार का आरोप है कि इस जमीन का न तो अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा मिला और न ही किसी प्रकार की



नियोजन सुविधा दी गई,बावजूद इसके कंपनी द्वारा जबरन अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर कई बार कनकनी कोलियरी से लेकर एरिया प्रबंधन तक गुहार लगाई,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।उपरोे अब उन्हें कथित रूप से धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होंने कार्य में बाधा पहुंचाई तो उनके खिलाफ सरकारी काम में विघ्न का केस दर्ज कर

आईएसएम, धनबाद में ईएमआरएस के टॉप स्टूडेंट्स के लिए तीन दिवसीय आईटी बूट कैंप शुरू



धनबाद, आईआईटी,आईएसएम धनबाद ने जजतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ईएमआरएस,एकलव्य मॉडल रेंजिडेशियल स्कूल के टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए तीन दिवसीय आईटी और कंप्यूटर ट्रेनिंग बूट कैप की शुरुआत की है।ज्ञात हो की 17 से 19 जुलाई तक चलने वाला यह कैप, झारखंड के ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें डिजिटल स्किलस और टेक्नोलॉजी की बेसिक व एडवांस ट्रेनिंग दी जा सके। इस कैप का उद्घाटन संस्थान के मैनेजमेंट हॉल में किया गया ।, जिसमें आईआईटी

आईएसएम, धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने विज्ञान और तकनीक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कैसे इंग्लैंड ने 15वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर दुनियाभर में प्रभाव बनाया। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे इस बूट कैप का भरपूर फायदा उठाएं और सीखने की ह्र चीज को गंभीरता से लें। इस प्रोजेक्ट की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रो. रश्मि सिंह हैं, जबकि प्रो. संदीप मंडल और प्रो. नीलाद्रि दास को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका में रहे। प्रो. मंडल, जो मैनेजमेंट स्टडीज एंड

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख भी हैं, मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में छात्रों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करने की सलाह दी।कुल सात ईएमआरएस स्कूलों, सालगडीह, कथिजोरिया (दुमका), भोगनाडीह (साहिबगंज), टसरिया (गोड्डा), बसिया (गुमला), कुजरा (लोहरदगा) और टोरसिंडुरी (पश्चिमी सिंहभूम) से आए कुल 30 स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग कैप में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से लेकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ईआरपी 9.0 और पायथन प्रोग्रामिंग जैसे मॉड्यूल्स में हैंड्स-ऑन

ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही छात्रों को आईआईटी आईएसएम के टेक्नोलॉजी इन्वोवेशन हब टेक्समिन, एसोआईसी-आई2एच, सीआईएल इनक्यूबेशन हब और एनवीसीटीआई जैसे प्रमुख इन्वोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटरस का विजिट कराया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी, सेंट्रल लाइब्रेरी, रोबोटिक्स लैब, जियोलॉजिकल म्यूजियम और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जैसे अकादमिक संसाधनों से भी रूबरू कराया जाएगा। कैप के दौरान एक सांस्कृतिक संख्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें छात्र अपनी परंपरागत सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रो. रश्मि सिंह ने कहा कि यह बूट कैप छात्रों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। जो उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म देगा। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए प्रो. नीलाद्रि दास ने बताया कि आईआईटी, आईएसएम के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के जरिए अब तक झारखंड के सात ईएमआरएस स्कूलों के 1500 से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और यह मंत्रालय के अंतर्गत देश के श्रेष्ठ केंद्रों में एक है।

महिला समिति,बोकारो की सदस्याओं के द्वारा ‘सावन मिलन’ समारोह का आयोजन



बोकारो । महिला समिति,बोकारो की सदस्याओं के द्वारा बोकारो क्लब में “सावन मिलन” समारोह का आयोजन किया गया. इसमें समिति की मेंबर्स हरे परिधान में सजी धजी नजर आई. आयोजन का शुभारंभ अध्यक्ष श्रीमती अनिता तिवारी के आगमन से हुआ. सभी सदस्याओं ने तन्मयता से अतिथियों का स्वागत किया. सांस्कृतिक सचिव श्रीमती रश्मिता कुमार के नेतृत्व में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई

जिसमें सावन के उपलक्ष्य में कविताएं,गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए. इस अवसर पर ‘सावन कवीन’ का भी सर्वसहमति से चुनाव हुआ तथा सुंदर मेंहदी,आकर्षक केशा विन्यास वाली सदस्याओं को भी पुरस्कृत किया गया. विभिन्न प्रकार के मनोरंजक खेल तथा आयोजनों से कार्यक्रम सुसज्जित रहा. सावन का झूला सजाया गया,नई सदस्याओं का स्वागत किया गया,सावन के गीत गाए गए

तथा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई. इस भव्य समारोह का आयोजन सचिव श्रीमती ऋचा प्रियदर्शिनी की कुशल देखरेख में संपन्न हुआ. महिला समिति के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आपसी सौहार्द व प्रेम को बढ़ाना तथा साथ ही महिलाओं में समाज सेवा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना एवं उन्हें इस नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना था.

इस अवसर पर समिति की उपाध्यक्षगण



श्रीमती मोनिका रंगानी,श्रीमती इति रथ,श्रीमती देवजानी मिश्रा,श्रीमती अल्का मनवटी,श्रीमती अंजू सिंह,कोषाध्यक्ष अभिरुचि प्रिया,उप कोषाध्यक्ष अंजली तिवारी,सुरभि प्रभागी अनिरा झा,विद्यालय प्रभारी नीतू सुनीत व आशा राज,सिलाई व सैनिटरी प्रभारी प्रीति राजेश,श्रीमती समिता मोहंती,श्रीमती कल्पना वर्मा,श्रीमती यामिनी श्री तथा नव चर्चनित सदस्या श्रीमती रूपांशी श्रीवास्तव ने अपना बहुमूल्य सहयोग दिया.

सावन महोत्सव 2025 में “सावन कवीन” श्रीमती श्रद्धा, फस्ट रनर्स अप श्रीमती अन्नपूर्णा कुमार, सेकंड रनर्स अप श्रीमती संध्या राज, को चुना गया एवं मेंहदी के लिए श्रीमती चंदना को प्रथम पुरस्कार तथा श्रीमती रूपाली को द्वितीय तथा केश विन्यास के लिए श्रीमती सुष्मिता माडों और सावन स्पेशल पुरस्कार के लिए श्रीमती आशी सिंह को अध्यक्ष, महिला समिति श्रीमती अनिता तिवारी के द्वारा सम्मानित किया गया.

उपायुक्त के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता ने सामान्य/विधि/उच्च न्यायालय/मानवाधिकार से संबंधित बैठक की, दिए जरूरी दिशा-निर्देश



सभी विभागों से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

गिरिडीह जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज समाहर्णालय सभागार में अपर समाहर्ता ने सामान्य/विधि/ उच्च न्यायालय/मानवाधिकार से

संबंधित बैठक की। बैठक में सभी विभागों से संबंधित लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में विभागवार बारी-बारी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अपर समाहर्ता ने लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि वे मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु शपथ पत्र दायर

करके त्वरित रूप से कार्रवाई करें। न्यायालय के लंबित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने गंभीर और जटिल मामलों को अचलब संज्ञान में देने की बात कही, ताकि तत्त्वरित तरीके से उसका हल निकाला जा सके। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ, अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, जिला उप रजिस्ट्रार, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला, खनन इंस्पेक्टर, सामान्य शाखा, विधि शाखा के प्रधान सहायक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बृथ लेवल पदाधिकारियों और सुपरवाइजर को भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में पीपीटी के माध्यम से एवं डमी प्रपत्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया

गिरिडीह। आज गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के सभागार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के संबंध में अंतिम दिवस के प्रशिक्षण में अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा प्रतिनियुक्त मास्टर ट्रेनरों विजयेंद्र सेठ,बुजेश कुमार गुप्ता ,बद्री नारायण,अरविंद कुमार और आलोक कुमार के द्वारा 32 गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत प्रतिनियुक्ति बृथ लेवल पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजर को भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में पीपीटी के माध्यम से एवं डमी प्रपत्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी सुपरवाइजर्स को बृथ लेवल पदाधिकारियों को को गणन प्रपत्र, भवनों का मानकीकरण, नजरी नक्शा का टैगिंग, प्रपत्र 6 ,7 ,

एवं पिछले प्रशिक्षण में छूट गए बृथ लेवल पदाधिकारी को डमी प्रपत्रों में निर्धारित कॉलम एवं शर्तों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन मतदाता सूची देखने और मोबाइल एप के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रंजीत कुमार वर्मा और अशोक कुमार ने अपना योगदान दिए।



कनकनी कोलियरी के पी.ओ. व आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक पर आरोप

मदनाडीह निवासी रैयत दिलीप कुमार, निजी सीएनटी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध कोयला उत्खनन कराने का आरोप

लोयाबाद।मदनाडीह निवासी रैयत दिलीप कुमार ने कनकनी कोलियरी के प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल जी एवं आउटसोर्सिंग कंपनी रामअवतार के प्रतिनिधि आदित्य सिंह पर निजी सीएनटी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध कोयला उत्खनन कराने का गंभीर आरोप लगाया है।इस संबंध में उन्होंने धनबाद उपायुक्त को एक लिखित पत्र सौंपा है।जिसकी प्रतियां कोयला मंत्री,बीसीसीएल के सीएमडी,एसएसपी,एसडीओ,सीओ पुटकी, लोयाबाद थाना व डुमरी विधायक जयराम महतो को भी प्रेषित की गई है।शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बताया है कि सेन्द्रा मौजा खाता संख्या 70, खेसरा संख्या 12 के तहत भूजल 1.46 एकड़ भूमि उनके परदादा स्व. भोजू रवानी के नाम पर दर्ज है, जिसका वे 2016 तक नियमित लगान भी अदा करते रहे हैं।दिलीप कुमार का आरोप है कि इस जमीन का न तो अधिग्रहण किया गया, न मुआवजा मिला और न ही किसी प्रकार की



नियोजन सुविधा दी गई,बावजूद इसके कंपनी द्वारा जबरन अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर कई बार कनकनी कोलियरी से लेकर एरिया प्रबंधन तक गुहार लगाई,लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।उपरोे अब उन्हें कथित रूप से धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होंने कार्य में बाधा पहुंचाई तो उनके खिलाफ सरकारी काम में विघ्न का केस दर्ज कर

जेल भेजा जाएगा और धारा 144 भी लगा दी जाएगी।इस संबंध में जब कनकनी कोलियरी करने का आधार भी है। यही संदेश लेकर धनबाद के प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर सिजुआ स्थित शहीद शक्ति नाथ महतो स्मारक आरोप लगाया जा रहा है,वह बीसीसीएल की इंटर कॉलेज, जहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में टॉपर संपत्ति है और शिकायतकर्ता के दावे निराधार छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया । एसएसपी, हैं।उन्होंने बताया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है।शिकायतकर्ता द्वारा 2015 कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके जाये में भी ऐसा ही दावा किया गया था,जिसका जवाब बीसीसीएल के भूसंपदा पदाधिकारी ने छात्रों को मोबाइल व इंटरनेट के इस्तेमाल से दूर स्पष्ट रूप से यह कहते हुए दिया था कि खाता संख्या 70 की उक्त जमीन डीड नंबर 4131 पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। साथ ही के तहत 1957 में भूतपूर्व कोलियरी मालिक करने से अधिग्रहीत की गई थी और यह संपत्ति कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत नियमों के पालन करने की भी अपील की। मौके केन्द्र सरकार व बीसीसीएल की घोषित संपत्ति पर उन्होंने मैट्रिक और इंटर के टॉपर छात्रों को है।बताया गया कि शिकायतकर्ता ने 2019 में भी इसी विषय में उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी,जिसका विधिवत जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

प्रतिभा सम्मान समारोह, शिक्षा से ही संवर सकता है भविष्य :एसएसपी

धनबाद, (सिजुआ), शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का आधार भी है। यही संदेश लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर सिजुआ स्थित शहीद शक्ति नाथ महतो स्मारक आरोप लगाया जा रहा है,वह बीसीसीएल की इंटर कॉलेज, जहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में टॉपर संपत्ति है और शिकायतकर्ता के दावे निराधार छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया । एसएसपी, हैं।उन्होंने बताया कि यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है।शिकायतकर्ता द्वारा 2015 कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके जाये में भी ऐसा ही दावा किया गया था,जिसका जवाब बीसीसीएल के भूसंपदा पदाधिकारी ने छात्रों को मोबाइल व इंटरनेट के इस्तेमाल से दूर स्पष्ट रूप से यह कहते हुए दिया था कि खाता संख्या 70 की उक्त जमीन डीड नंबर 4131 पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। साथ ही के तहत 1957 में भूतपूर्व कोलियरी मालिक करने से अधिग्रहीत की गई थी और यह संपत्ति कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत नियमों के पालन करने की भी अपील की। मौके केन्द्र सरकार व बीसीसीएल की घोषित संपत्ति पर उन्होंने मैट्रिक और इंटर के टॉपर छात्रों को है।बताया गया कि शिकायतकर्ता ने 2019 में भी इसी विषय में उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी,जिसका विधिवत जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

जिला पशुपालन कार्यालय, धनबाद ।

—: आम सूचना —:

भारत सरकार के केन्द्र प्रायोजित योजना LHDCP योजनान्तर्गत धनबाद जिला के सभी ग्रामों तथा शहरी क्षेत्रों में Brucellosis टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक– 19.07.2025 से दिनांक– 18.08.2025 तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जाना है । इस कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालकों के घर-घर जाकर Brucellosis रोग के रोकथाम हेतु सभी मादा गौ जाति एवं भैंस जाति (4–8 माह) के पशुओं को Brucellosis का निःशुल्क टीकाकरण किया जाना है ।

टीकाकरण के पूर्व सभी मादा गौ वंशीय एवं भैंस प्रजाति (4–8 माह) के पशुओं को 12 अंकों के (UID) टैग से चिह्नीकरण करते हुए भारत पशुधन ऐप में निबंधन किया जाना आवश्यक है ।

अतः सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने-अपने आधार नं० एवं मोबाइल नं० इस कार्य हेतु विभाग द्वारा प्राधिकृत टीकाकर्मियों को उपलब्ध कराकर अपने पशुओं का पंजीकरण, टैगिंग एवं टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य में विभाग को सहयोग प्रदान करें।

जिला के सभी जिला परिषद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं अन्य सभी जन प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अपने-अपने क्षेत्र में वृहत प्रचार-प्रसार कर पशुओं का टैगिंग एवं टीकाकरण के लिए पशुपालकों को प्रेरित करें।

नोट :- अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड के पशुपालन पदाधिकारी / भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी से सम्पर्क करें।

टैग नहीं तो टीका नहीं।
जन-जन तक संदेश पहुंचाना है।
Brucellosis रोग को जड़ से मिटाना है।

निवेदक,
प्रभारी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
धनबाद।

PR 357581 (Animal Husbandry) 25-26 (D)

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह (जिला समाज कल्याण शाखा) ई—मेल :- dswgiridih2324@gmail.com

ऑँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के स्थित पदों पर चयन हेतु सूची						
क्र० सं०	परियोजना का नाम	ऑँगनबाड़ी केन्द्र का नाम	चयनित पद	चयन की तिथि	समय	चयन स्थल
01	बेंगाबाद	गहिरजोर	सहायिका	04.08.2025	11:00AM	आँगनबाड़ी केन्द्र परिसर
02		बरियारपुर	सहायिका	05.08.2025	11:00AM	आँगनबाड़ी केन्द्र परिसर
03		मँवरडीह	सहायिका	06.08.2025	11:00AM	आँगनबाड़ी केन्द्र परिसर
04		शहरपूरा	सहायिका	07.08.2025	11:00AM	आँगनबाड़ी केन्द्र परिसर
05		हरिनवाटांड	सहायिका	08.08.2025	11:00AM	आँगनबाड़ी केन्द्र परिसर
06	गिरिडीह सदर	जेटको	सहायिका	29.07.2025	10:00 a.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र
07		जम्बाद	सहायिका	29.07.2025	01:30 p.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र
08		चुंजका	सहायिका	30.07.2025	10:00 a.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र
09		पिपराटांड	सहायिका	30.07.2025	01:30 p.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र
10		गंगापुर	सेविका	31.07.2025	11:00 a.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र
11		छाताटांड	सेविका—सहायिका	05.08.2025	10:00 a.m.	पंचायत भवन
12		अलगुन्दा	सेविका	06.08.2025	11:00 a.m.	पंचायत भवन
13		चैताडीह	सेविका	07.08.2025	11:00 a.m.	आँगनबाड़ी केन्द्र

PR 357575 Social Welfare,Women and Child Development(25-26)#D

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह

पंचायती राज क्षेत्र में धनबाद रहा अत्वल

धनबाद को मिला राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र



धनबाद की उपलब्धि पूरे झारखंड राज्य के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरी

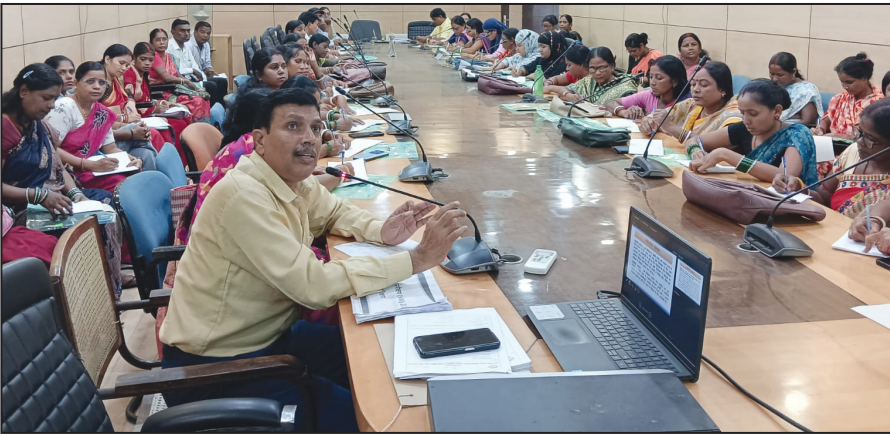
धनबाद, पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार द्वारा रांची स्थित होटल चाणक्या बीएनआर में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0

पंचायत उन्नति सूचकांक के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय प्रसार कार्यशाला में धनबाद जिला पूरे राज्य में अत्वल स्थान पर रहा।

धनबाद को स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण एवं सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

उप विकास आयुक्त, सादात अनवर की उपस्थिति में जिले को यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इससे धनबाद की पंचायत व्यवस्था को राज्य स्तर पर विशेष पहचान मिली। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह सफलता जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शारदा सिंह के कुशल नेतृत्व, सक्रिय जनप्रतिनिधियों और कर्मठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास का प्रतिफल है। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष, श्रीमती शारदा सिंह ने कहा कि यह सम्मान धनबाद जिले के जनप्रतिनिधियों, कर्मियों और ग्रामीण जनता की भागीदारी का परिणाम है। हमारा उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और जनकल्याणकारी बनाना है। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने पंचायत उन्नति सूचकांक के विभिन्न मापदंडों पर चर्चा की और आगे की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि धनबाद की यह उपलब्धि पूरे झारखंड राज्य के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरी है।

धनबाद विस के बीएलओ और सुपरवाइजरों का दस दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न



घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरण करने का निर्देश

धनबाद, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज 40 धनबाद विधानसभा क्षेत्र के 458 मतदान केंद्र के बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ तथा बीएलओ सुपरवाइजरों का दस दिवसीय प्रशिक्षण अनुमंडल कार्यालय पुराना समाहरणालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस संबंध में धनबाद विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, राजेश कुमार ने बताया कि गत 8 जुलाई से प्रशिक्षण शुरू हुआ था। दस दिवसीय प्रशिक्षण में धनबाद विधानसभा के 458 मतदान केंद्र के बूथ लेवल ऑफिसर व 48 बूथ सुपरवाइजर को स्पेशल ट्रेनिंग रिविजन विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक, राजकुमार वर्मा, राजेश साहनी, सतीश राय, बिनोद सिंह ने दिया।

प्रशिक्षण में बीएलओ व सुपरवाइजरों को उनके कर्तव्य, घर-घर गणना, फॉर्म के साथ देने वाले दस्तावेजों की सूची, मतदान केंद्र का नक्शा, नजरी नक्शा के साथ वोटर को टैग करना, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे एवं आपत्ति की अवधि, मतदाताओं के एंट्रेस का मानकीकरण, बूथ लेवल एजेंट के साथ सहभागिता सहित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी को अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरण करने, पूरी तरह से जाँच पड़ताल कर मतदाता का रंगीन फोटो, भरा फॉर्म हस्ताक्षर करवाकर संग्रह करने, कार्य में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने तथा शून्य त्रुटि के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। मौके पर सहायक निवाचक निबंधन पदाधिकारी सह धनबाद प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती पल्लवी सिन्हा, नीरज कुमार, ज्योति कुमार, सेजल कुमार आदि मौजूद थे।

रोटरी क्लब ऑफ धनबाद का 79वाँ चेंज ओवर डे 20 जुलाई को डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर बीके दास होंगे शामिल



धनबाद, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के द्वारा जीवन ज्योति विशेष विद्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष नवल उपाध्याय ने बताया कि आगामी रविवार 20 जुलाई को रोटरी क्लब ऑफ धनबाद का 79वाँ चेंज ओवर डे का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ० बी.के. दास होंगे। डॉ० दास को भारत की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों, आकाश और आकाशतीर, के विकास का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लब प्रेरणा, कृतज्ञता और सेवा के प्रति नई प्रतिबद्धता से भरे एक भव्य समारोह की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस चेंज ओवर डे कार्यक्रम में रोटरी वर्ष 2025-26 के कार्यकारिणी के सभी सदस्य विविधत कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि विगत 79 वर्षों से रोटरी क्लब ऑफ धनबाद अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती आ रही है और वर्ष 2025-26 में भी हम रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के द्वारा सामाजिक कार्यों का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही पत्रकारों को रविवार को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रेस वार्ता की समर्पित की। प्रेस वार्ता में नवल उपाध्याय, अध्यक्ष, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद, गौरव सराफ, सचिव, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद, राजेश परकेरिया, आशीष दुदानी, उत्तम गंगेसरिया, हरमन चोपड़ा आदि मौजूद थे।

जिले का कोई भी दिव्यांग सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे : न्यायाधीश



दिव्यांग बच्चों के लिए डालसा ने किया विशेष शिविर का आयोजन

धनबाद, झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, डालसा द्वारा सदर अस्पताल धनबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष निःशुल्क दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह

चेयरमैन डालसा वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि जिले का एक भी दिव्यांग बच्चा सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। जिले का हर बच्चा खास है और उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। वहीं शिविर के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तृपार टोपानों ने बताया कि शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह

अध्यक्ष, डालसा, वीरेंद्र कुमार तिवारी के निर्देशन में चल रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित किया गया। अभियान 6 जुलाई से 20 जुलाई 2025 तक जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाना है। मयंक ने बताया कि आज आयोजित शिविर में दर्जनों दिव्यांग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी किया गया। सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों की एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम में डॉ० राजीव कुमार सिंह, ओपिधि, डॉ० सरोजिनी मुर्मू नेत्र, डॉ० ०. मुकेश प्रसाद, हड्डी, डॉ० संजीव गुलास, सर्जरी, डॉ० जूनेद ई एन टी, काउंसलर अभिष्ठाता मुखर्जी व मीनाक्षी दुबे शामिल थे। शिविर को सफल बनाने में सदर अस्पताल प्रशासन एवं डालसा टीम के सदस्य हेमराज चौहान, डिपेंटी गुप्ता, बिना कुमारी, प्रदय कर्मा, निमाई प्रमाणिक, मानिक दुबे, नवीन कुमार, सोनू सिंह, कमल किशोर, सविता कुमारी, सोरभ सरकार, अरुण कुमार, राजेश सिंह आदि ने सहायनी योगदान दिया।

सरकार जमीन अधिग्रहण करें तथा सड़क बनावें : सदानंद महतो



धनबाद, (तोपचांची), देश अमृत वर्ष मना रहा है। देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, वहीं झारखंड राज्य को बने लगभग 25 वर्ष हो गये, लेकिन तोपचांची प्रखंड के दर्जनों राजस्व गांव मुख्य सड़क से आज भी नहीं जुड़ पाया है। झारखंड प्रदेश में बीसीसीएल, सीसीएल, डीवीसी, सेल कंपनी, टाटा कंपनी, डैम आदि औद्योग लगाने के लिए समय-समय पर जमीन अधिग्रहण कार्य होते रहे हैं। देश के विकास में झारखंड प्रदेश का अहम योगदान रहा है। लेकिन राज्यावासियों को अब तक मूलभूत समस्याओं से आज भी जुझते रहे हैं। प्रदेश में जमीन अधिग्रहण कानून कई तरह के बने हुए हैं, समय-समय पर कानूनों में संशोधन भी होते रहा है। गांव में बसोबास करने वाले खतियानी लोगों को आज भी सरकार मुख्य धारा से वंचित रखा है। तोपचांची क्षेत्र के घुनघुसा पंचायत के बदाही गांव, चितरपुर पंचायत के धाजाटांड, पिपराडीह, मंदेयडीह, के कालाझार, दुमदुमी पंचायत के दांदुभगाठ, खरियो के कुबडी आमटांड, रामाकुंडा पंचायत के तुरसाबाद रजक टोला व चैता के नवाबारी, पिपराटोला आदि कई गांव आज भी विकास के बाटजोह रहा है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता व आजसू नेता सदानंद महतो ने कहा कि तोपचांची के दर्जनों गांव मुख्य पथ से नहीं जुड़ पाया है। सरकार जमीन अधिकरण कानून के तहत जमीन उपलब्ध कराये तथा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी ले तथा सड़क बन पायेगी।

पुटकी बलिहारी महाप्रबंधक से स्थानीय रोजगार को लेकर मिले पिंटू कुमार सिंह



धनबाद। पुटकी बलिहारी क्षेत्र के महाप्रबंधक धर्मेन्द्र मिश्र से उनके कार्यालय में धनबाद जदयू जिलाध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता किया। ज्ञात हो की विगत 21 जुलाई को कोयला भवन मुख्यालय में सीएमडी सिमरन दत्ता से मिलकर बीसीसीएल कोल ब्लॉक्स क्षेत्र में स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया था। पुनः आज वार्ता में महाप्रबंधक ने समुचित व्यवस्था के साथ सकारात्मक क्रियाचर्यन हेतु आश्वासन दिया। वार्ता में जदयू धनबाद नगर अध्यक्ष धनलाल दूबे एवं युवा अध्यक्ष बबलू मोदक भी उपस्थित थे।

ज्ञान विज्ञान समिति धनबाद द्वारा गोविंदपुर प्रखण्ड सम्मेलन का किया गया आयोजन

धनबाद, (गोविंदपुर), गोविंदपुर प्रखण्ड कार्यालय के अंतर्गत प्रखण्ड साक्षरता कार्यालय में ज्ञान विज्ञान समिति धनबाद के सम्मेलन व पंचायत प्रेक संघ धनबाद की बैठक एबादुल रहमान के अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन मनोज कुमार महतो द्वारा किया गया। इस बैठक में मुख्यरूप से बी. जी. भी. एस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी रवि सिंह, राज्य उपाध्यक्ष, हेमंत कुमार जायसवाल जिले के नेतृत्वकारी साथी में सचिव भोला नाथ राम, संयुक्त सचिव सह पंचायत प्रेक संघ के अध्यक्ष, मो. हकीमुद्दीन अंसारी मधेश्वर नाथ भगत मौजूद थे। बैठक में प्रेरकों के वर्तमान



स्थिति, सक्रिय साथियों के संदर्भ में, ज्ञान विज्ञान समिति धनबाद के सदस्यता, प्रखण्ड सम्मेलन व जिला सम्मेलन को बैठक की गई।

सभी पुराने कार्यकर्ता के स्थिति को जानना है। उन्हें अपने साथ जोड़ना है, सभी सक्रिय प्रेरकों की बैठक गोल्फ ग्राउंड में 23 जुलाई को जिला स्तर पर प्रेरकों के बकाया मानदेय, समायोजन आदि मुद्दों को लेकर बैठक के पश्चात पद यात्रा करते हुए रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। ज्ञात हो की ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्यता, प्रखण्ड सम्मेलन व जिला सम्मेलन को लेकर बैठक की गई। सम्मेलन का संचालन करते हुए जिले के संयुक्त सचिव मनोज कुमार महतो द्वारा कहा गया कोविड काल के पूर्व वर्ष 2019 में प्रखंड सम्मेलन किया गया था। कोविड काल के वजह से देर हुई है, आज पांच वर्ष से अधिक समय हो गई, इस बीच

शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक चेतना, एकल शिक्षक विद्यालय का सर्वेक्षण, बेस लाइन सर्वेक्षण आदि किया गया है। इस दरम्यान हमारे बीच कई साथी नहीं रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी रवि सिंह द्वारा बीजीवीएसके राष्ट्रीय स्तर, व राज्य स्तर तथा जिला के गतिविधियों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। इसके पश्चात नई प्रखण्ड कार्यकारिणी में अध्यक्ष, एबादुल रहमान, उपाध्यक्ष में नीलम देवी व निमाई कुंभकार, सचिव में मनोज कुमार महतो, संयुक्त सचिव में नर्सिंग महतो, प्रतिमा मंडल, कोषाध्यक्ष, मुस्तकीम अंसारी, सह कोषाध्यक्ष, बासुदेव महतो तथा कार्यकारिणी में आसिफ अंसारी, दीपक मंडल, अलीमुद्दीन अंसारी, निमाई चंद्र महतो, वी, अलाउद्दीन अंसारी, माला देवी, वीना कुमारी सहित अन्य मौजूद थे। राज्य उपाध्यक्ष, हेमंत कुमार जायसवाल द्वारा सभी नई कार्यकारिणी को शुभ कामनाएं देते हुए जिला सम्मेलन 11 अप्रैल 2025 को शहीद खुदी राम बोस के शहादत दिवस पर आठवाँ जिला सम्मेलन आयोजित है। उपरोक्त कार्यक्रम को लेकर हिस्सेदारी लेकर सफल बनाने का आग्रह किया। अध्यक्ष के द्वारा सभी दिवंगत साथियों के लिए एक मिनट के मौन के पश्चात कार्यकारिणी का समापन किया गया। मौके पर संतोष दास, मनोज पंडित व निर्मल कुमार आदि उपस्थित थे।

मुगमा इसीएल द्वारा चिरकुंडा में स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन



चिरकुंडा, (धनबाद), इसीएल मुगमा परिया द्वारा चिरकुंडा गोस्वामी पाड़ा दुर्गा मंदिर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बहुचर्चा कर ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाया। मौके पर निरसा विधायक अरुण चटर्जी, इसीएल मुगमा परिया जीएम, ओम प्रकाश दुबे के साथ इसीएल के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी को दुर्गा मंदिर कमिटी द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। विधायक और जीएम ने भी अपना शुगर और प्रेशर का जाँच कराया। विधायक अरुण चटर्जी ने कहा स्वास्थ्य को देखते हुए मुगमा इसीएल के सीएसआर के तहत यहाँ जांच शिविर लगाया गया है। जिसमे शुगर, प्रेशर के साथ अन्य जांच की जा रही है। ग्रामीण काफी संख्या में अपना जांच करा रहे है। ज्ञात हो की इसीएल के डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच की गई। जांच के बाद दवा भी दी गई।

झारखंड में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों के वर्ष 2008 से लंबित प्रमोशन की मांग को लेकर तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव और निदेशक से शिक्षक संघ मिले



धनबाद, झारखंड में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वर्ष 2008 से लंबित प्रमोशन के मांग को लेकर बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल संघ के अध्यक्ष, डॉ० डी. के. सिंह और

महासचिव डॉ० अमृत्यु सुमन बेक के नेतृत्व में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव एवं निदेशक से मिलकर प्रमोशन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं से अवगत कराया। साथ ही इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आग्रह

किया। इस मांग पर दोनों अधिकारियों ने जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। विदित हो कि शिक्षकों के प्रमोशन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार ने सीएएस-2010 को वर्ष 2022 में

स्वकृत एवं अनुमोदित किया था, जिसके पृष्ठ संख्या 15 में यह प्राधान्य दिया गया है कि पूर्वव्यापी जानकारी एकत्र करने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और सीएएस-2010 प्रमोशन में 01-01-2009 से इन विनियमों के कार्याचरण को सुगम बनाने के लिए एपीआई आधारित प्रमोशन को पूर्वव्यापी जानकारी को एकत्र करने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसे उत्तरोत्तर और भावी रूप से लागू किया जाएगा। शिक्षकों के वर्षों से लंबित प्रमोशन के आवेदन को स्कूटनी प्रक्रिया पूरी करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर वर्ष 2023 में झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किया गया था। जिसे जुलाई 2025 में आयोग ने यह कहते हुए लौटा दिया कि केटेगरी - I एवं केटेगरी-II के लिए एपीआई स्कोर से संबंधित दस्तावेज वर्ष 2008 अनुलग्न नहीं है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष डॉ० डी. के. सिंह ने कहा कि जब प्रमोशन के लिए सीएएस-2010 रेगुलेशन वर्ष 2022 में आया है तब कोई शिक्षक पीछे के तारीख वर्ष

2008 से इसे कैसे जमा कर सकता है, जबकि इस रेगुलेशन में यह वर्णित है कि यह उत्तरोत्तर और भावी रूप से लागू होगा। झारखंड लोकसेवा आयोग का यह कदम अव्यवहारिक और सीएएस 2010 के अनुरूप कदापि नहीं है। प्रोव्रत नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक न सिर्फ अधिक क्षति और मानसिक रूप से परेशान है, बल्कि विश्वविद्यालय व अन्य जगहों के शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर निकलने वाले नियुक्तियों पर आवेदन देने से भी वंचित हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा पहला कदम था आगे अगर विश्वविद्यालय और राज्य सरकार समयबद्ध सकारात्मक उचित निर्णय नहीं लेती है तो संघ आंदोलन के रणनीति तय करते हुए एक बड़ा आंदोलन करने पर विचार होगी। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर मुकुंद रविदास, डॉक्टर मासूफ अहमद, डॉक्टर अमृत्यु सुमन बेग एवं डॉक्टर डी.के. सिंह शामिल थे।